16/5/96 lib

HVS/1

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

14 मार्च, 1995

खण्ड 1, अंक 7

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 14 मार्च, 1995

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(7)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(7)20
कथित विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाना	(7)23
अध्यक्ष द्वारा रूलिंग—	
किसी व्यक्ति को सदन के समक्ष साक्षी देने के लिए बुलाने संबंधी	(7)30
प्रो0 छत्तपाल सिंह के निलम्बन को रद्द करने संबंधी मामला उठाना	(7)31
अध्यक्ष द्वारा रूलिंग (पुनरारम्भ) तथा उस पर चर्चा	(7)34
ध्यानाकर्षण सूचनाएं/नियम 84 के अधीन प्रस्ताव	(7)37
बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट	(7)40

मूल्य : 149 00

	पृष्ठ संख्या
सदन की मेज पर रखे गये कागज-पत्र	(7) 42
वर्ष 1995–96 के बजट पर सामान्य चर्चा	(7) 43
वैयक्तिक स्पष्टीकरण— चौधरी बंसी लाल द्वारा	(7) 54
वर्ष 1995–96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7) 55
बैठक का समय बढ़ाना	(7) 75
वर्ष 1995–96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7) 75
बैठक का समय बढ़ाना	(7) 77
वर्ष 1995–96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7) 78

ERRATA

TO

Haryana Vidhan Sabha Debates Vol. 1, No. 7, dated the 14th March, 1995

Read	For	Page	Line
17549	17549 लाख	2	32
20 lakh	28 lakh	5	7
किसी	कोई	14	5
टोटल	टौरल	15	5
मलकियत	मलकियात	38	18
बैठे	बैठ	49	4
था	थ	49	5
प्रौमिज़री	प्रौमोसरी	49	31
दिख	दीख	50	2
रहे	रह	50	3
ये	य	51	21
वीरेन्द्र	वीरेन्द्र	52	27
आईडैन्टिटी	आईडैन्टी	53	4
ठीक	ीक	60	8
ऐंस्टीमेट	ऐस्टीमट	69	12
पिछड़े	पिछड़	71	28
श्री ओम प्रकाश बेरी	श्री प्रकाश बेरी	78	2

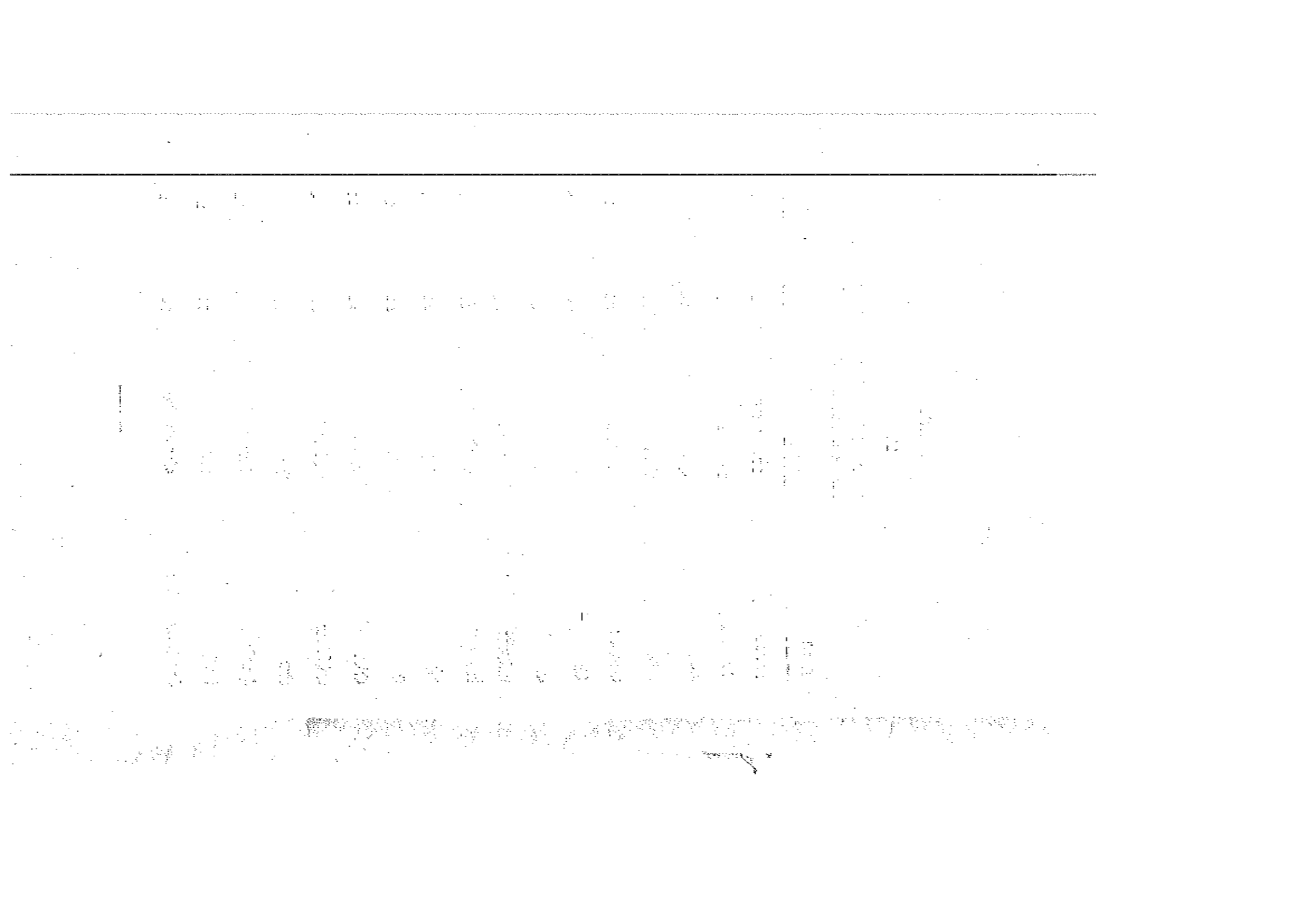

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 14 मार्च, 1995

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9-30 बजे हुई । अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे ।

*1020 **Shri Krishan Lal :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state the year in which the lining of Joshi Minor (Panipat) Hansi Branch Meter-Majra fall was done?

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) : Lining of Joshi Minor was completed under modernisation of existing channels phase-I in the year 1982.

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस माइनर को पक्का करने के बाद इसमें पानी चला है या नहीं ? यदि नहीं, तो कब तक पानी चला देंगे ? पानी न मिलने के बावजूद भी किसानों से आबियाना लिया जा रहा है । क्या उस आबियाने को वापिस किया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक दिया जाएगा ? दूसरा आश्वासन मैं यह चाहता हूं कि इस माईनर में कब तक पानी चला दिया जाएगा ?

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, इसमें शुरू में कुछ दिक्कत आई थीं । यह ठीक है कि इसमें कुछ दिन पानी चला और कुछ दिन नहीं चला, इसके कई रीजन थे । लेकिन जब पानी नहीं चला उसके लिए जो आबियाना उगाहा गया है, उसको वापिस करने का प्रावधान रूल्ज में नहीं है ।

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर साहब, जैसे मैंने कहा है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं कि पानी न देने के रीजन क्या थे, जब पानी नहीं गया तो आबियाना क्यों नहीं वापिस किया जाएगा ?

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, मैंने पहले ही बताया है कि इसके कारण तो कई थे । एक तो हांसी ब्रांच से फाल का कारण था, दूसरा पानी की कमी का भी कारण था । इसके अलावा कुछ किसानों का आपस में लिटिगेशन का कारण है । इस तरह के कई कारण थे जिस वजह से कुछ देर पानी चला और कुछ देर नहीं चला । जहां तक आबियाना वापिस करने की बात है, वह नहीं किया जा सकता । यदि आगे के लिए किसान को एक भी पानी न लगे तो उससे आबियाना न लिए जाने के बारे में सोचा जा सकता है । जैसे कनक को 5–6 पानी लगते हैं, उसमें अगर एक पानी भी लग गया तो आबियाना देना पड़ेगा और अगर पानी बिलकुल ही न लगे तो उसके लिए सोचा जा सकता है ।

Remittance of Interest of Loan

***1025. Prof. Chhattar Singh Chauhan** : Will the Minister for Cooperation be pleased to state the total amount of interest on loan of Cooperative Sector, if any, remitted by the Government during the years from 1-7-91 to 30-6-94 ?

सहकारिता मन्त्री (श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया) : माफ की गई राशि 6191.33 लाख रुपये है ।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि 61 करोड़ 91 लाख 33 हजार रुपए इन्होंने जो माफ किए हैं, इसमें इंस्टीच्यूट वाइज कितना-कितना पैसा है ? यानी प्राइमरी लैंड मार्गेज बैंक का कितना है और दूसरे सैक्टर का कितना है ? मन्त्री महोदया कृपया यह भी बताएं कि क्या इसमें ऐसा भी अमाउंट शामिल है जो डैड खाते में जा चुका है । तीसरा प्वाईंट यह है कि ये जिलावाइज बताने की भी कृपा करें कि कितना-कितना पैसा माफ किया गया और यह भी बताएं कि प्राइमरी मार्गेज बैंक का कितना हुआ और कोआपरेटिव बैंक का कितना हुआ ? क्या इन्होंने अपने जिले रिवाड़ी में ज्यादा ब्याज माफ तो नहीं किया, अगर हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया : स्पीकर साहब, इसमें ज्यादा और कम का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि जिस व्यक्ति ने जिस जिले से लोन ले रखा है, वह नार्म्ज के मुताबिक ही है । इसमें अलग अलग बैंकों की बात नहीं है, दोनों ही बैंकों की बात है । इकट्ठे ही पैसे का ब्याज माफ किया गया है । वह राशि मैंने आपको बताई है कि 61 करोड़ 91 लाख 33 हजार रुपये है । सर्कलवाइज जितना ब्याज माफ हुआ है और जितने लोग लाभान्वित हुए हैं, वह इस प्रकार है । अम्बाला में 2 करोड़ 45 लाख 66 हजार रुपए ब्याज माफ किया गया और उससे 17549 लाख

आदमी लाभान्वित हुए । यमुनानगर में 3 करोड़, 19 लाख 04 हजार रुपए ब्याज माफ किया गया और उससे 20 हजार 13 आदमी लाभान्वित हुए । नारायणगढ़ में 1 करोड़ 08 लाख 03 हजार रुपए ब्याज माफ किया गया और उससे 7506 लोग लाभान्वित हुए । कुरुक्षेत्र में 4 करोड़ 25 लाख 59 हजार रुपए ब्याज माफ किया गया और उससे 28472 लोग लाभान्वित हुए । कैथल में 2 करोड़ 35 लाख 80 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 16829 लोग लाभान्वित हुए । गुहला में 1 करोड़ 52 लाख 57 हजार रुपए ब्याज माफ किया गया और उससे 8280 लोग लाभान्वित हुए । करनाल में 5 करोड़ 08 लाख 78 हजार रुपए ब्याज माफ किया गया और उससे 27276 लोग लाभान्वित हुए । पानीपत में 3 करोड़ 77 लाख 57 हजार रुपए ब्याज माफ किया गया और उससे 19197 लोग लाभान्वित हुए । गुड़गांव में 80 लाख 74 हजार रुपए ब्याज माफ किया गया और उससे 5347 लोग लाभान्वित हुए । नूंह में 61 लाख 60 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 4382 लोग लाभान्वित हुए । सोनीपत में 1 करोड़ 43 लाख 77 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 9 हजार 04 लोगों को फायदा हुआ । फिरोजपुर झिरका में 99 लाख 53 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 7688 लोगों को फायदा हुआ । रोहतक में 1 करोड़ 29 लाख 05 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 7978 लोगों को फायदा हुआ । झज्जर में 96 लाख 37 हजार रुपए ब्याज माफ किया गया और उससे 6191 लोगों को फायदा हुआ । बहादुरगढ़ में 36 लाख 58 हजार रुपए ब्याज माफ किया गया और उससे 1955 लोगों को फायदा हुआ । गोहाना में 1 करोड़ 11 लाख 55 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 6360 लोगों को फायदा हुआ । जीन्द में 1 करोड़ 08 लाख 80 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 7336 लोगों को फायदा हुआ । करनाल में 1 करोड़ 25 लाख 40 हजार रुपए ब्याज माफ किया गया और उससे 7388 लोगों को फायदा हुआ । सफीदों में 68 लाख 08 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 4882 लोगों को फायदा हुआ । फरीदाबाद में 46 लाख 47 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 3501 लोगों को फायदा हुआ । पलवल में 1 करोड़ 60 लाख 33 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 9684 लोगों को फायदा हुआ । भिवानी में 1 करोड़ 42 लाख 23 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 12850 लोगों को फायदा हुआ । चरखी दादरी में 76 लाख 52 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 6396 लोगों को फायदा हुआ । लोहारू में 32 लाख 52 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 2744 लोगों को फायदा हुआ । महेन्द्रगढ़ में 55 लाख 42 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 4349 लोगों को फायदा हुआ । तावडू में 63 लाख 27 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 4213 लोगों को फायदा हुआ । हिसार में 3 करोड़ 91 लाख 15 हजार रुपए का ब्याज माफ

[श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया]

किया गया और उससे 25117 लोगों को फायदा हुआ । फतेहाबाद में 2 करोड़ 58 लाख 64 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 14202 लोगों को फायदा हुआ । हांसी में 90 लाख 10 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 6864 लोगों को फायदा हुआ । सिरसा में 2 करोड़ 65 लाख 57 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 13239 लोगों को फायदा हुआ । रिवाड़ी में 96 लाख 46 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 8376 लोगों को फायदा हुआ । डबवाली में 80 लाख 11 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 3822 लोगों को फायदा हुआ । इस तरह से 51 करोड़ 91 लाख 33 हजार रुपए का ब्याज माफ किया गया और उससे 328989 लोगों को फायदा हुआ ।

चौधरी सूरज भान काजल : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि लोनी जो शेयर मनी देता है जोकि 10–15 साल तक बैंक के पास रहती है और उस पर लोनी को कोई इंट्रस्ट भी नहीं दिया जाता है और न ही वह पैसा लोनी को वापिस दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष : आप क्वैश्चन पूछें ।

चौधरी सूरज भान काजल : स्पीकर सर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि किसानों का जो डिविडैंड होता है, वह 10–10 और 20–20 सालों तक बैंकों में जमा पड़ा रहता है । उस पैसे को न तो सरकार वापस करती है और न ही उस पर किसानों को कोई ब्याज आदि देती है उस पैसे का ब्याज किसानों को क्यों नहीं दिया जाता ? दूसरी बात मैं इनके नोटिस में लाना चाहूंगा कि शूगर मिल्ज में गन्ना किसानों का जो जाता है, उस की कीमत में से 50 पैसे प्रति क्विंटल किसानों का काटा जा रहा है, तो वह क्यों काटा जाता है ?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न का इस मूल सवाल से कोई संबंध नहीं है, आप बैठ जाएं ।

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया : अध्यक्ष महोदय, लगता है कि माननीय सदस्य ने मूल सवाल पढ़ा नहीं है । इसमें यह पूछा गया है कि सहकारिता क्षेत्र में कुल कितना कर्जा माफ किया गया है ।

श्री अध्यक्ष : आप यह बता दो कि इनके समय में कितना कर्जा माफ हुआ था ?

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया : हमने इस के मुकाबले में बहुत अधिक कर्जा माफ किया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1005

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य डा0 राम प्रकाश सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Releasing of amount for development works

*1051. **Shri Ram Bhajan Aggarwal** : Will the Finance Minister be pleased to state whether the amount of Rs. 28 lakh for the development schemes (through D.C. concerned) in each constituency during the year 1994-95 has been released by the Government, If not, the reasons thereof ?

वित्त मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : जी, श्रीमान जी ।

श्री रामभजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री महोदय के नोटिस में लाते हुए कहना चाहता हूं कि यह जो 20 लाख रुपये की राशि पिछले सैशन में विधायकों के क्षेत्रों में विकास के काम करने के लिए देने की घोषणा की गई थी, यह राशि अभी तक उनके पास नहीं पहुंची है । मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि 11 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक यह 20 लाख रुपया क्यों नहीं पहुंचा है ? यदि अब जायेगी तो यह राशि यूटेलाईज नहीं हो पायेगी । मैं चाहता हूं कि जब तक यह खर्च न हो जाए, तब तक इसको लैप्स न किया जाये । दूसरा मेरा सवाल यह है कि अगले साल की राशि भी अप्रैल-मई-जून के महीने तक जारी कर दी जाये ताकि समय पर विकास के कार्यों में इसको लगाया जा सके । तीसरा सवाल मेरा यह है कि सरकार इस राशि से जो काम एम0एल0एज0 करवाना चाहेंगे, वहां पर खर्च होगी या जो काम सरकार पहले ही कर रही है, उन्हीं पर एम0एल0ए0 के अंगूठे लगवायेंगी ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने जवाब में बताया कि पिछले बजट सैशन में मुख्य मन्त्री ने कहा था कि विधायकों को अपने हल्के के काम करवाने के लिए 20-20 लाख रुपये की राशि प्रत्येक क्षेत्र में दी जायेगी और यह राशि डी0सी0 को भेज दी जाएगी । इनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि इस साल की यह राशि संबंधित जिलाधीश को भेजी जा चुकी है । विधायकों को शायद कुछ कन्फ्यूजन हो कि यह राशि कैश मिलेगी या कैश लेकर काम करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है । यह राशि विधायकों की इच्छानुसार पब्लिक इन्ट्रैस्ट के जिन वर्क्स की लिस्ट वे तैयार करके देंगे, उस पर खर्च होगी । यह स्कीम चाहे गली की हो, चाहे

[श्री मांगे राम गुप्ता]

वाटर सप्लाई की हो या रोड्ज की हो, अगले साल की राशि ज्यों ही खर्च कर दी जायेगी, भेज दी जाएगी । यह पैसा जब तक खर्च नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष : रामभजन जी ने पर्टिकुलरली अगले साल की राशि भेजने के बारे में पूछा है कि क्या यह राशि मई-जून के महीने तक भेज दी जायेगी ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है कि जो राशि भेजी गई है, जब यूटेलाईज हो जाएगी तो अगले साल की राशि भी भेज दी जाएगी ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अगले साल भी हम इस स्कीम को चालू रखेंगे । मेरे सामने बैठे इन महानुभावों की जनता के विकास कार्यों में तो कोई रुचि है नहीं । इन 16 विधायकों ने कोई स्कीम विकास की बना कर डी0सीज0 को नहीं भेजी कि इस विकास के काम पर पैसा खर्च होना चाहिए । हमने पैसा कंसर्ड डी0सीज0 को भिजवा दिया है । स्पीकर साहब अगर इन्होंने कोई स्कीम बना कर भेजी हो तो ये बता दें । मैं इनके नाम पढ़ कर बता देता हूं । सर्वश्री जसविन्द्र सिंह पेहोवा से, अमर सिंह ढांडे गुहला से, कृष्ण लाल असन्ध से, सतबीर सिंह कादयान नौलथा से, बलवन्त सिंह हसनगढ़ से, दरयाव सिंह झज्जर से, जिले सिंह साल्हावास से, ओम प्रकाश चौटाला नरवाना से, सूरजभान काजल जुलाना से, सम्पत सिंह भट्टूकलां से, मनीराम दड़बा कलां से । इन लोगों ने कोई स्कीम बना कर डी0सीज0 को नहीं भेजी ।

श्री सतबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि बजट में वायदा किया गया था कि 20-20 लाख रुपये एम0एल0एज0 को लोकल फण्ड ऐरिया से देंगे । डि-सैंट्रेलाईज प्लान और लोकल फण्ड ऐरिया को मिला दिया गया है । मन्त्री जी बताएं कि जो पैसा दिया जाना है, क्या वह लोकल फण्ड ऐरिया का है या डिसैंट्रेलाईज स्कीम का है, ये दोनों स्कीमें अलग-अलग हैं या इनको मिला दिया गया है, अगर दोनों को मिला दिया गया है तो फिर इस स्कीम का क्या फायदा है, यह जनता के साथ धोखा है क्या यह पैसा डिस्ट्रिक्ट्स में चला गया है ?

चौधरी भजन लाल : यह पैसा एम0एल0एज0 के लिए रखा गया है कि वे अपने हल्के में जो भी विकास का काम चाहते हैं, वह उनकी मर्जी से होना चाहिए, उनकी इच्छा के मुताबिक होना चाहिए । हरियाणा में 90 विधायक हैं और 20-20 लाख रुपये के हिसाब से 18 करोड़ रुपये की राशि इस उद्देश्य के लिए रखी गई थी ताकि विधायक अपने हल्के के बारे में बताएं कि फलां गांव में यह काम होना चाहिए परन्तु इन महानुभावों ने इस में कोई रुचि नहीं दिखाई । किसी भी जगह का नाम

बताएं, किसी ने भी कोई स्कीम बना कर भेजी हो तो बता दें। इन्होंने अगर कोई स्कीम किसी डी0सी0 को भेजी हो तो बता दें कि इस पैसे को मेरे हल्के में इस काम पर खर्च किया जाए।

चौधरी धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने वित्त मन्त्री के पक्ष में आते हुए जवाब दिया कि इस राशि को खर्च करने के लिए विधायकों ने कोई स्कीम बना कर प्रस्तुत नहीं की। अध्यक्ष महोदय, दूसरे साथी भी इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि फरवरी-मार्च तक तो किसी भी जिले में कोई भी पैसा जारी नहीं किया गया तो फिर इस प्रकार की स्कीम बनाने का लाभ क्या है? मुख्य मन्त्री जी से मैं एक और जानकारी चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री साहब जी ने बादली हल्के के मातण गांव में बड़ी लम्बी-चौड़ी घोषणा की थी। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी की घोषणा की कोई मर्यादा होती है। मुख्य मन्त्री अपनी पार्टी का नेता हो सकता है लेकिन जहां तक मुख्य मन्त्री का ताल्लुक है, वह पूरे प्रदेश का मुख्य मन्त्री होता है, इसलिए उसका दृष्टिकोण सारे प्रदेश के लिए एक जैसा होना चाहिए क्योंकि मुख्य मन्त्री तो सारे प्रदेश का होता है और जो घोषणा उनके द्वारा की जाती है वह हर हाल में पूरी होनी चाहिए। मुख्य मन्त्री जी लम्बी चौड़ी घोषणा तो कर देते हैं, परन्तु उसको पूरा नहीं करते। जहां तक विकास की स्कीम का संबंध है, उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी जो घोषणाएं करते हैं क्या उनको अमली जामा भी पहनाया जाता है या केवल थोथी और असत्य घोषणाएं करते हैं? (विघ्न) स्पीकर साहब, जनवरी और फरवरी में तो कोई पैसा इन स्कीमों के लिए जारी नहीं हुआ है तो हम किस प्रकार की कोई स्कीम बना कर भेजें, पहले ये पैसा जारी करें, सदन में असत्य और थोथी घोषणाएं न करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि उन्होंने कुल मिला कर कितनी घोषणाएं की हैं और उनमें से कितनी घोषणाओं पर कार्यवाही हुई है?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि जो भी घोषणा की जाती है, उसको पूरी तरह से पहले एग्जामिन किया जाता है और बाद में घोषणा की जाती है। जो घोषणा की जाती है, उसको हम पूरा करते हैं।

चौधरी ब्रह्म सिंह : जो घोषणा ये करते हैं उसमें कह देते हैं कि पैसे की उपलब्धता पर पूरा कर देंगे। जब पैसा ही नहीं तो फिर एग्जामिन क्या करते हैं? 20 लाख रुपये की राशि का जहां तक ताल्लुक है, कोई पैसा नहीं दिया गया फिर स्कीम किस चीज के लिए भेजें?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, पैसा डी0सीज0 के पास पहुंच गया है और जब ये छुट्टियों में अपने अपने हल्के में जाएं और पता करके आएं तथा हाउस में बताएं कि पैसा पहुंचा था कि नहीं। (विघ्न)

Amount spent on desilting of J.S.B. Canal

*1038 **Chaudhri Zile Singh Jakhar** : Will the Minister of Irrigation be pleased to state the amount spent on desilting of J.S.B. Canal and its minors during the period from March, 1994 to-date ?

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) : No work of desilting was carried out on Jhajjar Sub Branch from 3/94 to date. However, the desilting work on its 13 off-taking channels/minors was carried out during 3/94 to date and a sum of Rs. 8.39 lacs has been incurred for the purpose.

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो मेन नहर है वह 47532 आर0डी0 से लेकर टेल तक गाद से भरी पड़ी है। उससे आगे 13 नहरें हैं जिन पर 8 लाख 39 हजार रुपया खर्च किया गया है और जो इन्होंने इतना पैसा खर्च किया है, उससे कोई फायदा नहीं हुआ है, तो क्या ये वहां से गाद निकलवा कर पानी लाने की व्यवस्था करेंगे ? दूसरे मदनपुर और एक और गांव हैं वहां पर पम्प हाऊस लगे हुए हैं। तो क्या वहां पर भी पानी लाने की व्यवस्था की जाएगी ?

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए इनको बताना चाहूंगा कि ये जो 13 माईनर्ज और सब माईनर्ज हैं, इनकी डी-सिल्टिंग की गई है और उससे फायदा भी हुआ है। (विघ्न) आप सुनें तो सही। यह बात ठीक है कि सिल्टिंग की वजह से वहां पर पानी की कैपसिटी कम हुई है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पिछली दफा भी कहा था। (शोर) अध्यक्ष महोदय, मैं ओमप्रकाश बेरी के साथ नहर देख कर आया हूं। (विघ्न) लेकिन मैंने पिछले साल एक सवाल के जवाब में कहा था कि हम इसमें डी-सिल्टिंग करवाएंगे। इस पर 16 करोड़ रुपए के करीब खर्चा होगा, इसमें 2-3 साल लगेंगे। अध्यक्ष महोदय, 1995-96 में भी इसकी डी-सिल्टिंग करवाने का प्रावधान है।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, पम्प हाऊस के बारे में इन्होंने नहीं बताया है। उनमें पानी नहीं आ रहा है। वहां पर मोटरें हैं, बिजली है और सब कुछ है लेकिन पानी नहीं है।

चौधरी जगदीश नेहरा : आप कौन से पम्प हाऊस के बारे में कह रहे हैं ?

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं तो लिफ्ट इरीगेशन वाले के बारे में कह रहा था।

चौधरी जगदीश नेहरा : ठीक है हम उनको ठीक करवा देंगे।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, वे खराब नहीं हैं । वहां पर सब कुछ है लेकिन पानी नहीं है । तो क्या वे वहां पानी लाने की कृपा करेंगे ?

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, हम वहां पर डी-सिल्टिंग करवा कर पानी लाने की व्यवस्था करेंगे ।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, यह पानी कब तक वहां पर पहुंचाएंगे ?

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, हम यह काम अप्रैल महीने से शुरू करवाएंगे और लगातार चलेगा । इसको कम्पलीट होने में दो महीने भी लग सकते हैं ।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : ठीक है जी ।

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, क्या मन्त्री जी बताएंगे कि क्या दूसरी नहरों से भी गाद निकलवाने की इनकी कोई स्कीम है क्योंकि नहरों से गाद न निकलने की वजह से पीने का पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है । मेरे गांव मीठी में तो दस अक्तूबर को ही पानी गया था और उसके बाद से आज तक भी वहां पानी नहीं गया । यह पानी वहां इसलिए नहीं गया क्योंकि नहरें गाद से भरी हुई हैं । बजट में तो इन्होंने नहरों में गाद निकालने के लिए कोई पैसा रखा नहीं है तो क्या मन्त्री जी की नहरों से गाद निकालने की कोई स्कीम है ?

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, ऐसी बात नहीं है कि बजट में प्रावधान नहीं है बजट में तो इस काम के लिए प्रावधान है । प्लान और नान प्लान का बजट होता है और नान प्लान में इस तरह के काम होते हैं । इनको जहां जहां भी दिक्कत है, वहां हम गाद निकलवाकर पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे ।

श्री ओमप्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने बताया कि हम डी-सिल्टिंग कराएंगे । क्या यह बात इनके नालेज में है कि भाखड़ा बाकरा हैड से डाउन स्ट्रीम जे0एस0बी0 प्रैक्टिकल रूप से बन्द हो चुकी है और जितने गांवों में इससे पानी आता था, उनमें पानी देने का कोई इन्तजाम नहीं किया जा रहा है । स्पीकर सर, मैं मन्त्री जी के साथ गया था और हमने जे0एस0बी0 का इन्सपैक्शन भी किया था । सर, वहां नहर के बीच में कीकर के बड़े-बड़े पेड़ खड़े हुए हैं इसलिए आगे पानी जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता । जे0एस0बी0, जे0एल0एन0 के साथ-साथ जाती है । तो स्पीकर सर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि ये कब तक जे0एस0बी0 की डी-सिल्टिंग और लाईनिंग करायेंगे ? स्पीकर सर, उसमें पानी नहीं छोड़ा जाता । जो जे0एस0बी0 से इफैक्टिड गांव हैं, क्या सरकार उन गांवों को पानी देने के लिए

[श्री ओम प्रकाश बेरी]

जे0एल0एन0 से पानी का प्रावधान कराएगी ? इसके अलावा, दूसरा मेरा सवाल यह है कि किसानों को पानी तो मिल नहीं रहा है और सरकार उन से आबियाना बार-बार वसूल कर रही है तो, क्या मन्त्री जी इस बारे में कोई जांच कराएंगे ? स्पीकर सर, मैं चैलेंज करता हूं कि इसके लिए हाऊस की एक कमेटी बनायी जाए और वह कमेटी वहां पर जाकर इस बात को देख ले कि प्रैक्टिकल रूप से इन गांवों को पानी दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है ? सरकार जानबूझ कर इन इलाकों के साथ भेदभाव कर रही है, ज्यादती कर रही है । अध्यक्ष महोदय, अगर आप चाहें तो इस बारे में बेशक हाउस की एक कमेटी बना दें ।

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, जब ये मेरे साथ वहां पर इसका इंस-पैक्शन करने के लिए गए थे तो उस समय झज्जर सब ब्रांच में पानी चल रहा था, ऐसी बात नहीं है कि पानी नहीं चल रहा था । हम इसीलिए ही वहां पर गए थे कि उसका मौके पर जाकर इन्सपैक्शन किया जाए । इसलिए ही उसमें डी-सिल्टिंग करने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है । इंस्पैक्शन के बाद मैंने स्वीकार किया कि वहां पर दिक्कत है ।

श्री ओम प्रकाश बेरी : स्पीकर सर, मन्त्री जी यह बात बता दें कि आज उसमें पानी बन्द है या नहीं । और अगर मेरी बात झूठ है तो मैं इस विधान सभा से रिजाइन करने के लिए तैयार हूं (विघ्न) यह हाउस को गुमराह कर रहे हैं कि पानी लोगों को मिलता है ।

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, ये इतना कठोर कदम न उठाएं कि इस प्वायंट पर रिजाइन करें । इसके लिए तो और मौके आएंगे । लेकिन अब मैं नहीं कह सकता कि वहां पर पानी चल रहा है या नहीं क्योंकि वहां पानी रोटेशन से चलता है । आज पानी है या नहीं मैं नहीं कह सकता । लेकिन उसमें पानी टर्न के हिसाब से चल रहा है । इन्होंने यह भी कहा कि जहां जहां पर पानी नहीं चलता है तो वहां पर जे0एल0एन0 से पानी दिया जाना चाहिए । स्पीकर सर, इनको भी पता है कि उसमें क्या प्राब्लम है, एक तरफ तो वहां जे0एल0एन0 जा रही है और लैफ्ट साईड में उनके जे0 एस0 बी0 है और जे0 एल0 एन0 के बीच में से भी जे0 एस0 बी0 से इधर मोगे हैं और जे0 एल0 एन0 सभी जे0 एस0 बी0 के साईड में मोगे हैं । जहां-जहां भी पानी की दिक्कत आयी वहां पर लगातार पानी के मोगे जे0एल0एन0 से ही दिए गए । लेकिन इनको जहां-जहां भी पानी की दिक्कत है, वहां वहां हम उसको हल करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे ।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने कहा कि जे0एल0एन0 में मोगे दे दिए गए हैं लेकिन सर, कोई भी मोगा नहीं दिया गया । जहां तक

आबियाना का सवाल है तो मातनहेल, मुनरा मादल, अकेड़ी मदनपुर के लोगों का सीपेज की वजह से काफी आबियाना आता है। पटवारी उनकी फसल को देखकर ही गिरदावरी करके चला जाता है और उन पर आबियाना लगा देता है।

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, मैंने पहले भी अर्ज किया कि अगर एक भी पानी किसानों ने लगा लिया तो सरकार आबियाना लेने की हकदार हो गयी। हो सकता है कि इन गांवों में पानी न लगा हो, लेकिन यदि वहां बिल्कुल भी पानी नहीं लगा है तो उसके लिए सरकार एंजामिन करवा कर रिलीफ देने की कोशिश करेगी।

Mr. Speaker : The Minister will visit the place and sort out the problem.

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, इसको हम मौके पर जाकर देखेंगे और अगर कोई दिक्कत है तो उसको हल करने की सरकार कोशिश करेगी।

Consolidation

*1098. **Shri Dhir Pal Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the names of the villages of Bahadurgarh and Jhajjar Tehsils of District Rohtak in which consolidation of land holding has not been done so far, togetherwith the reasons thereof ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : विभिन्न न्यायालयों में मुकदमेबाजी के कारण बहादुरगढ़ तहसील के छः गांवों नामतः छारा, माण्डोठी, बाढ़सा, असोदा टोडरान बराही, कुलताना तथा झज्जर तहसील के चार गांव नामतः किलोई खेड़ी, होशदारपुर मोहम्मदपुर माजरा, डीघल, जिला रोहतक के चकबन्दी कार्य में देरी हुई है, मुकदमेबाजी की वजह से।

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह 10.00 बजे | जानकारी चाहूंगा कि जो दस गांव दर्शाए हैं, क्या इनमें से सभी गांवों के मामले कोर्ट में गए हुए हैं या कितने ऐसे गांव हैं जिनके मामले कोर्ट में नहीं हैं, जिन गांवों के मामले कोर्ट में नहीं गए उन पर अगली कार्यवाही कब तक पूरी कर दी जाएगी ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इस समय इन दस गांवों में से किसी गांव का मामला कोर्ट में नहीं है। 10 में से 8 पर चकबंदी इस्तेमाल का काम शुरू हो गया है बाकी दो गांव रहते हैं, कोशिश करेंगे कि साल सवा साल में सभी गांवों में इस्तेमाल हो जाए।

Providing of more Stand-Posts

*1111. **Shri Ram Kumar Katwal** : Will the Minister for Public Health be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide more stand posts to supply drinking water in Alewa ; and

(b) if so, the time by which aforesaid stand-posts are likely to be provided ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी) :

(क) जी नहीं, स्वीकृत नार्मज 120 स्टैण्ड पोस्टों के विरुद्ध पहले ही 138 स्टैण्ड पोस्ट लगे हुए हैं ।

(ख) उपरोक्त "क" अनुसार प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री राम कुमार कटवाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि 1978 में चौधरी देवी लाल की सरकार ने (विघ्न).....

श्री अध्यक्ष : कटवाल साहब, आप क्वैश्चन पूछिए ।

श्री राम कुमार कटवाल : स्पीकर सर, उस वक्त 120 स्टैण्ड पोस्ट लगे हुए थे और अब 18 स्टैण्ड पोस्ट और बढ़े हैं लेकिन उस वक्त अलेवा की आबादी 6,100 थी; अब यह गांव 21 हजार की आबादी वाला हो गया है ।

श्री अध्यक्ष : कटवाल साहब, 21 हज़ार तो किसी गांव की आबादी नहीं है ।

श्रीमती शान्ति देवी राठी : अध्यक्ष महोदय, नार्म्ज के अनुसार 120 स्टैण्ड पोस्ट ठीक लगे थे, फिर भी सरकार ने 18 स्टैण्ड पोस्ट और लगाए और इनकी संख्या बढ़कर 138 हो गई । नार्म्ज के अनुसार 100 की जनसंख्या पर एक स्टैण्ड पोस्ट लगता है । 18 ज्यादा हैं, यह बात आपने भी स्वीकारी है । जहां तक जनसंख्या का संबंध है, अलेवा में उस वक्त 11,148 जनसंख्या थी और अब 12 हजार 40 है । यदि माननीय सदस्य को 1-2 स्टैण्ड पोस्ट और लगाए जाने में इंट्रैस्ट है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लगवा देंगे ।

श्री राम कुमार कटवाल : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया ने हाउस को गुमराह करने की कोशिश की है । इस बारे में हाउस की एक कमेटी गठित कराई जाए । 120 + 18 = 138 स्टैण्ड पोस्ट हैं, ये केवल आपने पढ़कर सुनाया है मन्त्री महोदया, आबादी भी आज 21 हजार से कम नहीं है ।

श्रीमती शान्ति देवी राठी : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बता देना चाहती हूं कि मैं जो आंकड़े बता रही हूं, यह तथ्यों पर आधारित हैं । इन आंकड़ों को ये चैलेन्ज नहीं कर सकते । ये जो आंकड़े बता रहे हैं, ये अपने अनुमान से बता रहे हैं । इनकी पिछली सरकार के सारे कारनामों से जनता पूरी तरह से अवगत है लेकिन मैं उन कारनामों को यहां पर रखना नहीं चाहती । मैं तो यह कहूंगी कि स्वच्छ पानी जनता को देने के लिये हमारी सरकार की पूरी जिम्मेवारी है और हम दे रहे हैं । फिर भी मैं इनको यह क्लीयर करना चाहती हूं और जहां कहीं भी ये स्टैण्ड पोस्ट चाहते हैं, उनके नाम ये लिखकर हमें दे दें । जहां जहां ये अनुभव करते हैं कि फलां फलां जगहों पर इनकी जरूरत है, वह हम लगवा देंगे ।

Generation of Electricity in the State

***1147. Prof. Ram Bilas Sharma** : Will the Minister for Power be pleased to state—

(a) whether there is any scheme under consideration of the Government for the generation of electricity in the State with the collaboration of any company of Israel ; and

(b) if so, the details thereof ?

बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(क) हां श्रीमान् जी ।

(ख) 700 मैगावाट यमुनानगर थर्मल परियोजना का निर्माण एक संयुक्त उद्यम कम्पनी (जे0 वी0 सी0) जिसमें हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड तथा इजराईल की आइजनबर्ग ग्रुप आफ कम्पनीज के युनाइटेड डिवैल्पमैन्ट इकोपोरेटिड शामिल हैं, के माध्यम से निर्माण किया जाना प्रस्तावित है । इसके लिये एक समझौते पर दोनों भागीदारों के मध्य 25 जनवरी, 1995 को हस्ताक्षर हुये हैं ।

वित्तीय समाप्ति (क्लोजिंग) 6 मास के अन्दर-अन्दर होनी है ।

प्रो0 राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, इन्होंने इजराइल की एक कम्पनी आइजनबर्ग ग्रुप आफ कम्पनीज के साथ 25 जनवरी, 1995 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये । पहली बात तो यह है कि इनको वह ऐग्रीमैंट सदन की पटल पर रखना चाहिये था कि कौन सी शर्तों पर वह कम्पनी बिजली पैदा करेगी और वह बिजली हरियाणा के लोगों को किस भाव पड़ेगी, कौन सी शर्तों पर वे बिजली देंगे और क्या उसमें 700 मैगावाट का यमुनानगर का थर्मल प्लांट भी शामिल है या

[श्री राम बिलास शर्मा]

नहीं ? क्या इस तरह का थर्मल प्लांट लगाने की सरकार की हिसार में भी कोई योजना विचाराधीन है ? यह बात ठीक है कि बिजली के अकाल को देखते हुए हरियाणा सरकार चिंतित है । तो मैं इन से यह जानना चाहता हूं कि बिजली जनरेशन के मामले में सरकार ने कोई विज्ञापन किया, किसी कम्पनी को इंवाइट किया ? क्या ऐसी कोई कम्पनी ने इनको लिखित रूप में कोई आफर दी जोकि इनको सस्ते रेट्स पर बिजली जनरेट करके दे सकें, जरा पोजीशन क्लीयर कर दें ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, इजराईल की कम्पनी को लेकर विपक्ष के भाई बहुत सारा प्रचार कर रहे हैं और लोगों को एक तरह से गुमराह किया जा रहा है । आपको स्पीकर सर, यह पता है कि हरियाणा प्रान्त में ही नहीं बल्कि सारे देश में आज बिजली की खपत बहुत बढ़ गई है । इस प्रकार के, हरियाणा प्रान्त के मैं चार-पांच अनुमान दूंगा । 1989-90 में बिजली की जो खपत थी, वह आज 1994-95 में कहीं ज्यादा है । बिजली एक ऐसी चीज है जोकि फौरी तौर पर पैदा नहीं की जा सकती । बढ़ी हुई लोगों की मांग को देखते हुए यह प्रयास किया जा रहा है कि आज जो हरियाणा प्रान्त इस मामले में नम्बर दो पर है, इसे इसी नम्बर पर ही कायम रखा जाए और हमारी तो यह कोशिश होगी कि हरियाणा प्रान्त को इस मामले में नम्बर वन पर लाया जाए । इसलिये सरकार का चिंतित होना जरूरी है कि इस प्रान्त में बिजली की खपत और बढ़ाई जाए और प्रान्त में बिजली की सप्लाई पूरी प्रदान की जाए । इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे मुख्यमन्त्री महोदय ने इजराईल की कम्पनी आइजनबर्ग ग्रुप से 1994 में एम० ओ० यू० साईन किया जोकि बड़ी ही नामी-काबी कम्पनी है । उस एम० ओ० यू० को अब आगे बढ़ावा दिया गया है और 25-1-95 को एक एंग्रीमैंट साइन किया गया , जिसने अभी फाइनल शेप लेनी है । जो पावर परचेज एग्रीमैंट होगा, मैं हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि वह आपके सामने लाया जाएगा । जो गवर्नमैंट आफ इंडिया की गाइड लाइन्ज है, उससे रत्ती भर भी इधर-उधर नहीं जाएंगे । जहां तक अब तक की क्लाज पर सहमति की बात बताने का सवाल है, ऐसे कामों में एक क्लाज होती है जिसको कमर्शियल एंड कन्फीडैंशियल क्लाज कहते हैं । उससे हम पाबन्द हैं, ज्यों ही पी०पी०ए० साइन होगा, उसको हाउस के सामने लाया जाएगा । फिर भी मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि गवर्नमैंट आफ इंडिया ने जो नार्मज तय किए हैं, उससे एक इंच भी इधर-उधर नहीं होगा । दूसरी बात इन्होंने हिसार में या दूसरी जगह पर प्रोजैक्ट लगाने की पूछी कि उसके लिए कोई कम्पनी आगे आई है या नहीं । मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि कम्पीटीटिव बिडिंग का एक डाकुमैंट तैयार हो रहा है । बहुत जल्द हम अखबारों के द्वारा ग्लोबल टैंडर फलोट करेंगे और जो भी आकर आएगी, उससे भी हाउस को अवगत कराया जाएगा ।

श्री सतबीर सिंह कादयान : स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आइजनबर्ग की इस कम्पनी से समझौता करने से पूर्व क्या गलोबल टैंडर इनवाइट किए गए थे, अगर किए गए थे तो देश की किस-किस कम्पनी ने उसमें पार्टिसिपेट किया और विदेश की कौन कौन सी कम्पनियों ने पार्टिसिपेट किया ? इसके अलावा, यह भी बताएं कि इसकी टोरल कास्ट आफ कंस्ट्रक्शन क्या होगी ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, कम्पीटीटिव बिडिंग के लिए जो गवर्नमैंट आफ इंडिया ने गाइड लाइन्ज तय की हैं, वे जनवरी, 1995 में की हैं । इसलिए उससे पहले कम्पीटीटिव बिडिंग करने का कोई सवाल नहीं उठता । पहले केवल हरियाणा ने ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के कई प्रदेशों जिसमें महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान हैं, इन्होंने भी इस प्रकार के एम0 ओ0 यू0 साइन किए हैं ।

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, कादयान साहब के सवाल के जवाब में मंत्री जी ने बताया कि गवर्नमैंट आफ इंडिया ने फारेन कम्पनियों को थर्मल की कंस्ट्रक्शन करने के लिए अभी परमिशन दी है । तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि फारेन कम्पनियों को इस वक्त इजाजत दी गई लेकिन हिन्दुस्तान में और भी कम्पनियां हैं, उनको आपने टैंडर जारी करने की इजाजत क्यों नहीं दी ? ऐसा करने से हिन्दुस्तान की कम्पनियां भी इसके निर्माण में आ सकती थीं ऐसा आपने क्यों नहीं किया ? स्पीकर साहब, अब तो आपने इनको गलोबल टैंडर भरने की इजाजत दे दी है, लेकिन यह भी हो सकता है उनसे सस्ते रेट पर और कम्पनियां इसको बना सकती हों ? तो क्या अब आप दूसरी कम्पनियों से गलोबल टैंडर इनवाइट करेंगे ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, जहां तक यमुनानगर का सवाल है उसका एग्रीमैंट तो आइजनबर्ग कम्पनी के साथ फाइनल है । उसके बारे में बातें चल रही हैं और करीब-करीब वहीं पर फाइनल हो जाएगा । जैसे मैंने पहले बताया कि हिसार के लिए हम ओपन बिडिंग करेंगे । उसके लिए सभी कम्पनियों को टैंडर देने की इजाजत होगी । जहां तक सम्पत सिंह जी ने यह कहा कि इंडियन कम्पनीज को भी इनवाइट करें तो इसमें इंडियन कम्पनीज का सवाल नहीं है और न उनको कोई परमिशन देने की बात है । मैंने यह कहा है कि ओपन बिडिंग के लिए भारत सरकार ने अब गाइडलाइन्ज दी हैं कि आप गलोबल टैंडर कर सकते हैं ।

प्रो0 राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस कम्पनी के साथ इन्होंने समझौता किया है और वह कम्पनी 700 मैगावाट बिजली पैदा करेगी, वह हमें किस भाव में देगी ? इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जैसे बम्बई में टाटा कम्पनी सस्ती बिजली जनरेट करती है, उसी तरह की हिन्दुस्तान की किसी एक कम्पनी ने क्यों आपको बिजली

[प्रो० राम बिलास शर्मा]

जनरेट करने की ऑफर दी थी ? वह कम्पनी आपको टाटाकम्पनी से भी सस्ती बिजली जनरेट करके दे सकती है। इस बारे में मैं मंत्री जी से कैटेगोरीकली जानना चाहता हूं ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने बड़ी तफसील के साथ सारी बातें बताई हैं । अगर इनको कोई काम बिगाड़ना हो तो चाहे ये कुछ भी कह दें । अध्यक्ष महोदय, उस कम्पनी के साथ भारत सरकार की एन० टी० पी० सी० की 5-6 मीटिंगें हो चुकी थीं । उस कम्पनी के साथ हमने जो एम० ओ० यू० साइन किया उस कम्पनी ने एन० टी० पी० सी० को कहा था आपको इतना पैसा लगाना पड़ेगा और हम इतना पैसा लगाएंगे यानि 75 परसैंट पैसा हम लगाएंगे और 25 परसैंट पैसा आप लगाएंगे । लेकिन उन्होंने यानी एम० टी० पी० सी० ने कहा कि उनके पास इतना पैसा नहीं है । अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि वह बहुत अच्छी कम्पनी है । उसने चाइना में 3 हजार मैगावाट के प्रोजैक्ट लगाये हैं । वह कम्पनी और कंट्रीज में भी प्रोजैक्ट लगाने जा रही है । वह कम्पनी हमारे यहां प्रोजैक्ट लगाने के लिए तैयार है । हम उस कम्पनी को यहां पर प्रोजैक्ट लगाने के लिए बड़ी मुश्किल से लाये हैं । हम इस काम के पीछे तीन साल से लगे हुए हैं । हमने उस कम्पनी के साथ जो एम० ओ० यू० साइन किया है वह यह किया है कि अगर 68.5 परसैंट लोड फैक्टर होगा तो बिजली का रेट होगा फी-यूनिट 1 रुपया 92 पैसे । अगर लोड फैक्टर 75 परसैंट होगा तो बिजली का रेट होगा 1 रुपया 80 पैसे । अगर लोड फैक्टर 85 परसैंट होगा तो बिजली का रेट होगा 1 रुपया 60 पैसे और अगर लोड फैक्टर 90 या 95 परसैंट हो जाएगा तो बिजली का रेट 1 रुपया 50 या 55 पैसे होगा । अध्यक्ष महोदय, हमने 68.5 परसैंट लोड फैक्टर पर 1 रुपया 92 पैसे बिजली के रेट पर एग्रीमैंट साइन किया है। अब तक किसी भी जगह पर इससे कम रेट में कोई एग्रीमैंट साइन नहीं किया गया है । मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और राजस्थान कहीं पर भी इससे कम रेट पर कोई एम० ओ० यू० साइन नहीं किया गया है । हमने यह सब कुछ भारत सरकार की इजाजत से किया है । अभी एग्रीमैंट हुआ है और अभी बात हमारे हाथ में है अगर किसी बात में कोई मतभेद हुआ तो हम उनसे कहेंगे कि नहीं आप इस रेट पर हमें बिजली दें । हम यह चाहते हैं कि किसी तरह से हमारे यहां बिजली का प्रोजैक्ट लग जाए । मेरे सामने बैठे भाईयों की सरकार ने अपने चार साल के समय में एक भी प्रोजैक्ट नहीं लगाया । इनकी मेहरबानी से हमारे प्रदेश में बिजली का बहुत बुरा हाल हो गया । अब ये चाहते हैं कि किसी तरह से यह मामला बिगड़ जाए और यह प्रोजैक्ट हरियाणा में न लगे । इस बारे में जो भी एग्रीमैंट होगा वह सदन के सामने रखेंगे ।

श्री ओम प्रकाश जिंदल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय को क्या पता है कि पावर फैक्टर क्या होता है ? हरियाणा के अन्दर 85 से कम पावर फैक्टर आता ही नहीं, जो ये कह रहे हैं कि 1.60 रुपये बिजली पड़ेगी, यह सरासर * * * * बोल रहे हैं । इतनी बिजली सस्ती हरियाणा में आ नहीं सकती, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : इस शब्द को एक्सपंज कर दिया जाये ।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने माना है कि 25 जनवरी, 1995 को दो भागीदारों के एक एग्रीमैंट पर हस्ताक्षर हुए हैं । मैं जानना चाहूंगा कि इनका यह जो एग्रीमैंट हुआ है, क्या उसको सदन की पटल पर रखेंगे ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि एम0 ओ0 यू0 का टाईम एक्सपायर हो रहा था, इसलिए उसको बांधे रखने के लिए वह एग्रीमेंट किया गया है। मेन एग्रीमैंट तो अभी होना है और जो एग्रीमैंट हुआ है, वह भी इस होने वाले मेन एग्रीमेंट का एक पार्ट होगा । ज्यों ही मेन एग्रीमैंट हो जायेगा, उसको हाउस में रख दिया जायेगा ।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, जब एक एम0 ओ0 यू0 पर दो पार्टियों के हस्ताक्षर हो गए तो वह पब्लिक डाकूमैंट बन जाता है । इसलिए मैं चाहता हूं कि उसको सदन की टेबल पर आना चाहिए ।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने हाउस में बताया है कि एक एम0 ओ0 यू0 पर जो दस्तखत हुए हैं, वह अभी कांफिडेंशियल हैं क्योंकि यह एक कमर्शियल एग्रीमैंट है । हम कुछ बातों को जनता को बताने के लिए पाबंद हैं । यह सभी को पता है कि कमर्शियल डील में कुछ ऐसी पाबंदियां होती हैं जो इस स्टेज पर नहीं बताई जा सकती । हां, मैं सदन को यह आश्वासन देता हूं कि ज्यों ही हमारा फाईनल एग्रीमैंट हो जायेगा, तो वह एग्रीमैंट सदन की पटल पर रख दिया जायेगा । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारा यह एग्रीमैंट, भारत सरकार की जो गाइडलाईन्ज है, उन्हीं पर आधारित होगा । इसमें प्रांत को किसी प्रकार का कोई नुक्सान नहीं होने दिया जायेगा और हरियाणा के हित पूरी तरह सुरक्षित रखे जाएंगे ।

श्री बंसी लाल : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिस एम0 ओ0 यू0 पर इनके दस्तखत हुए हैं, उसको सदन की पटल की पर रखने से क्या हरियाणा के हित सुरक्षित नहीं रहेंगे ?

---

*Not recorded as ordered by the Chair.

श्री वीरेन्द्र सिंह : हरियाणा के हित तो पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे । लेकिन हम इस पर पाबंद हैं कि जब तक फाईनल एग्रीमैंट नहीं हो जाता, तब तक किसी तरफ से ऐसी बात न हो जाये जो एक दूसरे के हित के खिलाफ हो । जैसा मैंने बताया है कि यह मामला फाईनल स्टेज पर है, इसलिए उस एम० ओ० यू० को इस समय पब्लिक डाकूमेंट के आधार पर हाउस में रखना उचित नहीं होगा ।

Repair of Roads of Guhla Sub-Division

*1114. **Shri Amar Singh Dhanday** : Will the Minister for P.W.D. (B & R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the roads of Guhla Sub-Division of district Kaithal ; and

(b) if so, the time by which the roads as referred to in part (a) above are likely to be repaired ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री अमर सिंह) :

(क) गुहला उपमण्डल की सड़कों की (मरम्मत) पैच कार्य द्वारा कर दी गई है ।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अमर सिंह ढांडे : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गुहला उपमण्डल की सड़कों पर कुल कितना पैसा खर्च हुआ, जो पैसा खर्च होना था, वह वहां खर्च न होकर कहां पर खर्च हुआ है, क्योंकि गुहला उपमण्डल में सड़कों की रिपेयर बिल्कुल भी नहीं हुई ?

श्री अमर सिंह : अध्यक्ष महोदय, गुहला उप-मण्डल में 328.29 किलोमीटर की रोड्ज है । इन सभी पर पैच वर्क पूरा हो चुका है जिस पर 6.79 लाख रुपये खर्च हुआ है । 30.5 कि० मी० पर रिनीवल कोट भी हो चुका है जिस पर 10 लाख 25 हजार रुपये खर्च हुए हैं । जनवरी 1995 तक 17.15 लाख रुपया खर्च किया गया ।

श्री अमर सिंह ढांडे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसी कोई स्पैशल टीम बना कर इसकी जांच करवाएंगे जो जांच करे कि वह पैसा कहां पर खर्च हुआ है । क्योंकि गुहला सर्कल के बारे में मैं कहता हूं कि आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। सड़कों का हाल बहुत ही बुरी

है इसलिए स्पैशल टीम बना कर उनकी चैकिंग करवाएं, वहां पर तो आदमी पैदल भी सड़क पर नहीं चल सकता है ?

श्री अमर सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि आनरेबल मैम्बर अपने हल्के में नहीं रहते हैं, गुहला में रिपेयर वर्क पर 47.88 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। मैं आनरेबल मैम्बर की तसल्ली के लिए बताना चाहता हूं कि 1992-93 में 7.64 लाख रुपये सिर्फ पैच वर्क पर खर्च किए गए थे और 1993-94 जनवरी 1995 तक 6.79 लाख रुपये रिपेयर पर खर्च हुआ है। 30.05 किलोमीटर लम्बी रोड़ पर 10.36 लाख खर्च हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हरियाणा में लगभग 3,135 किलोमीटर स्टेट हाईवे, 1,587 मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्ज, और लिंक रोडज या एप्रोच रोडज 16,857 किलोमीटर हैं (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आनरेबल मैम्बर को बताना चाहूंगा कि हरियाणा में पैच अभियान चलाया गया है और इसके तहत सारी रोडज की पैच वर्क (मुरम्मत) की गई है। पिछले साल 3,131 किलोमीटर रोडज टूटी थी। आनरेबल मैम्बर इस बात को मानेंगे कि हर साल फल्ड आता है। गुहला घग्गर नदी के किनारे पर पड़ता है, घग्गर में फल्ड आने से काफी नुकसान होता है और रोडज भी टूटती हैं। हर फल्ड के बाद रोडज की मुरम्मत की जाती है और पैच वर्क भी किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, सारे हरियाणा में रोडज का पैच वर्क करवा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, सदन में यह बात बार-बार आती रही है कि सड़क पर कोई टाकी नहीं लगी, हमने टाकी भी लगवा दी है और ओवर कोट भी बहुत सारी जगह पहना दिये हैं। (हंसी)

Shortage of Medicines in Government Hospitals in the State

*1107. **Sathi Lehri Singh** : Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that there is an acute shortage of medicines and also non availability of certain life saving drugs in Government Hospitals/Dispensaries in the State at present ; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to provide adequate stock of essential medicines in Government Hospitals/Dispensaries ?

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मन्त्री (बहिन करतार देवी) :

(क) और (ख) : जीवन रक्षक दवाईयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। फिर भी उपलब्ध धन राशि से दवाईयों की कुल मांग को पूरा किया जाना कठिन है।

साथी लहरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहन जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या हर साल सी० एच० सीज० और पी० एच० सीज० के लिए वर्ष के आधार पर या मन्थ वाईज दवाईयों का कोई नार्म निर्धारित है ? मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या कोई स्पैशल और सरपराईज चैकिंग कहीं पर की गई है कि वहां पर दवाईयां हैं या नहीं हैं और जो दवाईयां वहां दी जानी होती हैं, वे वहां पर पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती; अगर नहीं पहुंचती तो क्या कोई ऐसा मामला इनके नोटिस में आया है; यदि आया है तो उसके बारे में इन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

बहिन करतार देवी : स्पीकर सर, जहां तक सब-सैंटरज और प्राईमरी हैल्थ सैंटरज में दवाईयों के नार्म का ताल्लुक है, इनके लिए दवाईयों का महीने का तो नहीं लेकिन साल का बजट रखा जाता है । नार्म के मुताबिक सब-सैंटर पर 2 हजार रुपये, प्राईमरी हैल्थ सैंटर में 10 हजार रुपये और सी० एच० सी० में 50 हजार रुपये की दवाईयों का नार्म है लेकिन होस्पीटल्ज के लिए कोई नार्म फिक्स नहीं है, वहां पर धन की उपलब्धता को देखते हुए दवाईयां प्रदान की जाती हैं । दूसरे, अध्यक्ष महोदय, एक बार नहीं अनेकों बार हम जा-जा कर देखते हैं कि डॉक्टरों का व्यवहार मरीजों के साथ ठीक है या नहीं, जो दवाईयां उपलब्ध हैं वे लोगों को मिल रही हैं या नहीं, बच्चों की देखभाल, जो उनको टीके लगाए जाते हैं और अनेक सुविधाएं जो उनको दी जाती हैं, उनका अभाव तो नहीं है ? अगर कोई कमी हो तो हम उचित कार्यवाही करते हैं ।

Mr. Speaker : Questions Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Construction of Ditch Drain

*1150. **Shri Balwant Singh** : Will the Minister for irrigation be pleased to refer to starred question No.530 which was replied on 5.3.93 and to state that the time by which the construction work of Ditch Drain along J. L. N. Feeder in Rohtak district is likely to be completed ?

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) : In reply to S. Q. No. 530 which was replied on 5.3.93, it was stated that the work will be completed on the availability of funds. Work will be started & it will be completed in phases.

High Schools

*1143 **Shri Azmat Khan :** Will the Minister for Education be pleased to state —

(a) the number of High Schools of tehsil Hathin, Taoru, Nuh and Ferozepur jhirka Sub-Divisions togetherwith their location ;and

(b) the number of schools out of those as referred to in part (a) above are without Headmasters at present ?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना): सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है ।

सूचना

(ए) तहसील	उप-मण्डल	उच्च-वि0 की संख्या		स्थिति
1	2	3		4
हथीन	पलवल	13	1	राजकीय उच्च विद्यालय कोंडल
			2	रा0 उ0 वि0 गहलब
			3	रा0 उ0 वि0 गुरेकसर
			4	रा0 उ0 वि0 मदनाक
			5	रा0 उ0 वि0 अलीमेव
			6	रा0 उ0 वि0 मानपुर
			7	रा0 उ0 वि0 सेलवी
			8	रा0 उ0 वि0 धरोट
			9	रा0 उ0 वि0 अटावर
			10	रा0 उ0 वि0 (क0) बहीन
			11	रा0 उ0 वि0 कलसाड़ा
			12	रा0 उ0 वि0 छैंसा
			13	रा0 उ0 वि0 हुंडीथल
नूह	नूह	12	1	रा0 उ0 वि0 अकेड़ा
			2	रा0 उ0 वि0 छपेरा
			3	रा0 उ0 वि0 फिरोजपुर नमक
			4	रा0 उ0 वि0 कुरथाला
			5	रा0 उ0 वि0 खेड़ा खलीलपुर
			6	रा0 उ0 वि0 कैंराका

[श्री फूल चंद मुलाना]

1	2	3	4
			7 रा0 उ0 वि0 मैलाब
			8 रा0 उ0 वि0 उजीना
			9 रा0 उ0 वि0 नूह
			10 रा0 उ0 वि0 मेवली
			11 रा0 उ0 वि0 घसेरा
			12 रा0 उ0 वि0 इब्दी
तावडू	नूह	8	1. रा0 उ0 वि0 मोहम्मदपुर अहीर
			2. रा0 उ0 वि0 पादोनी
			3 रा0 उ0 वि0 राठीवास
			4 रा0 उ0 वि0 सुंद
			5 रा0 क0उ0 वि0 तावडू
			6 रा0 उ0 वि0 कलवारी
			7 रा0 उ0 वि0 बगांकी
			8 रा0 उ0 वि0 जौरासी
फिरोजपुर झिरका	फिरोजपुर झिरका	19	1 रा0 उ0 वि0 भादस
			2 रा0 उ0 वि0 बजीदपुर
			3 रा0 उ0 वि0 बिच्चौर
			4 रा0 उ0 वि0 बिवां
			5 रा0 उ0 वि0 बटेर
			6 रा0 उ0 वि0 बदरपुर
			7 रा0 उ0 वि0 ढुढोली
			8 रा0 उ0 वि0 डोहा
			9 रा0 उ0 वि0 जेटाना
			10 रा0 उ0 वि0 लोहिंगा कलां
			11 रा0 उ0 वि0 मण्डीखेड़ी
			12 रा0 उ0 वि0 माहू
			13 रा0 उ0 वि0 नाई
			14 रा0 उ0 वि0 नगीना
			15 रा0 उ0 वि0 औथा
			16 रा0 उ0 वि0 सिगार
			17 रा0 उ0 वि0 सिंगलहेड़ी
			18 रा0 उ0 वि0 सरौली

1	2	3	4
		19	रा0 उ0 वि0 शिकरावा
		20	रा0 उ0 वि0 उमरा
		21	रा0 क0 उ0 वि0 फिरोजपुर झिरका
		22	रा0 क0उ0 वि0 नगीना
		23	रा0 उ0 वि0 गंगवानी
		24	रा0 उ0 वि0 अगौन्ध
		25	रा0 उ0 वि0 बिसरू
		26	रा0 उ0 वि0 जमालगढ़
		27	रा0 उ0 वि0 रावली
		28	रा0 उ0 वि0 साकरस
		29	रा0 क0 उ0 वि0 पिनगवां

(बी) उन स्कूलों की संख्या निम्न अनुसार है, जहां मुख्याध्यापक नहीं है ।

तहसील/उप मण्डल	बिना मुख्याध्यापकों के स्कूलों की संख्या
हथीन	10
नूह	10
तावडू	6
फिरोजपुर झिरका	23

कथित विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाना

Prof. Sampat Singh : Mr. Speaker Sir, today morning we have given a notice of breach of privilege under Rule 261 of the Rules of Procedure and conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly against Shri Bhajan Lal, Chief Minister for making false and wrong statement on the floor of the House on the 10th March, 1995 that Mr. Om Parkash Chautala had demanded a bribe from Shri C.L. Verma. स्पीकर साहब, हमने डाक्यूमैंटरी प्रूफ भी उसमें लगाया है । मिस्टर सी0 एल0 वर्मा ने ट्रिब्यून के जरनलिस्ट को एक फैक्स मैसिज करवाया है । उसकी एक कापी हमने आपको भी सबमिट की है । उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि मैं बाहर गया हुआ था और बाहर से आने के बाद मैंने इंगलिश ट्रिब्यून में खबर पढ़ी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पांच करोड़ रुपए मेरी कम्पनी से उस काम को दोबारा से शुरू करने के लिए मांगे हैं । अध्यक्ष महोदय, ऊपर उन्होंने लिखा है कि हाउस के अन्दर बिना तथ्यों

[प्रो० सम्पत सिंह]

के दी हुई स्टेटमैंट बिल्कुल असत्य है और ओम प्रकाश चौटाला जी ने मेरे से कभी भी कोई पैसा नहीं मांगा है, न ही मेरी कम्पनी से मांगा है और न ही मैंने उनको कोई पैसा दिया है। अध्यक्ष महोदय, उसने यह भी लिखा है कि हाऊस में यह सब कहने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। दूसरी तरफ अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब मुख्यमंत्री जी गवर्नर ऐड्रस पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि यह बिल्कुल असत्य है, फाल्स है और मिथ्या बात है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने फिर भी बार-बार इस हाऊस की गरिमा को चोट मारने की कोशश की और अपनी बात पर डटे रहे। इन्होंने हाऊस को उस दिन फाल्स स्टेटमैंट देकर मिस-लीड किया है। यह मुख्यमंत्री जी के खिलाफ प्रिवलेज मोशन का केस है। इससे हाऊस के विशेषाधिकार का हनन हुआ है। चाहे कोई भी मैम्बर बोले, उसको सत्य बोलना चाहिए। किसी भी आदमी को बदनाम करने के लिए, पोलिटिकल फायदा उठाने के लिए हाऊस के अन्दर असत्य बोलें तो यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप रिपीट न करें।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे सबमिशन है कि आप हमारे प्रिवलेज मोशन के नोटिस को एडमिट करें ताकि यह केस प्रिवलेज कमेटी को जाए जिससे तथ्य सामने आएंगें। उस वक्त मिस्टर सी० एल० वर्मा को बुलाया जाए, डाक्यूमैंटरी प्रूफ भी आएं, उनकी भी जांच कर लें। उसके बाद कमेटी अपने रूल्ज के हिसाब से उस पर गौर करे और हाऊस में बताएं। मेरी आप से दोबारा पुरजोर अपील है कि यह जो इन्होंने ढंग अपनाया था, वह गलत था और हमारा यह प्रस्ताव स्वीकार होना चाहिए।

चौधरी भजन लाल अध्यक्ष महोदय, अब मुझे भी कहना पड़ेगा। मैं एक फाईल के थोड़े से सारांश पढ़ देता हूं। उससे सारा हाऊस, गैलरी में बैठे हुए महानुभाव और प्रैस के महानुभाव भी महसूस करेंगे कि इस तरह का वातावरण क्यों बना ?

अध्यक्ष महोदय, यह एग्रीमैंट 23 मार्च, 1987 को हुआ। उससे पहले मैं मुख्यमंत्री था फिर श्री बंसी लाल जी आ गए थे। तो इनके साथ एग्रीमैंट कान्टीनैंटल कंस्ट्रक्शन बी० टी० लिमिटिड, यू० के० के ज्वायंट वैन्चर के साथ हुआ था जिसके अनुसार 31-10-90 तक यह काम पूरा होना था। काम यह था कि फोर-लैनिंग वाली सड़क करनाल तक बनकर तैयार होनी थी। मार्च 1987 में एग्रीमैंट पर हस्ताक्षर होने के पश्चात्, 1988 के अन्त तक कोई कार्य नहीं हुआ। इस कार्य के न होने की वजह से और रुकावट की वजह से असंतुष्ट होकर बालफर-बैटी ने जनवरी 1989 में कहा कि हम इस प्रौजैक्ट से ज्वाइंट वैंचर विद ड्रा करना चाहते हैं क्योंकि काम तो करने नहीं देते और जो मांगते हैं, वह हम दे नहीं सकते। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, ये फिर हाउस को मिसलीड कर रहे हैं।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं बोलता यह तो फाईल बोलती है । मैं फाईल को स्पीकर साहब के चैम्बर में भेज देता हूं आप खुद देख लें । तो अध्यक्ष महोदय, वे कहने लगे कि हम इसमें से निकलना चाहते हैं । इसके उपरान्त कोंटीनेटल कंस्ट्रक्शन लिमिटिड ने 4-2-89 को कहा कि वालफर-वैटी के सम्बन्ध कंस्ट्रक्शन की स्पैसिफिकेशन के रेट के मुताबिक पूरा करेंगे और इस तथ्य के बारे में उनको अनुमति दी जाए । उन्होंने कहा कि अभी भी अनुमति दे दो क्योंकि वह तो बेचारा दुखी होकर जा रहा है लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम करेंगे । कंटीनेटल कंस्ट्रक्शन लिमिटड ने 18-3-89 को इसके बारे में दोबारा पत्र लिखा और बाकी काम समय पर करने के लिए अनुमति मांगी । लेकिन कम्पनी की इस प्रार्थना को 6-4-89 को पत्र द्वारा सरकार ने अस्वीकार कर दिया, उसको परेशान करने के लिए । स्पीकर साहब, वहां एक बैंक की गारंटी देनी होती है । इसी दौरान मोबलाइजेशन एडवांस की बैंक गारंटी को कैश करवाने का प्रयत्न किया गया जिसके खिलाफ कोंटीनेटल कंस्ट्रक्शन लिमिटड ने दिल्ली उच्च न्यायालय से 7-3-90 को स्टे प्राप्त किया । उस कम्पनी ने अलग से प्रस्ताव करके काम करने के लिए समय बढ़ाने की प्रार्थना की लेकिन उसको भी इन्होंने नामंजूर करके धारा 47 के तहत लिक्वीडेशन और डैमेजिज का नोटिस दे दिया गया । इन कारणों की वजह से वह कम्पनी आगे की कार्यवाही नहीं चला पायी, परिणामस्वरूप आगे कोई काम होने का सवाल ही नहीं था । इसके बाद आज की सरकार आ गयी । इस सरकार ने अगस्त में उस कम्पनी के साथ पूरक अनुबन्ध करके हस्ताक्षर किए और उनसे काम शुरू करवाया जो आज करनाल तक बनकर तैयार हो गया है । स्पीकर साहब, इसके अलावा मैं इन पर एक ऐलीगेशन और लगाना चाहता हूं कि सोनीपत जिले में जो बी0 एस0 टी0 गन्नौर में फैक्ट्री है, वह रौनक सिंह की एक बहुत बड़ी कम्पनी है, जिसमें पांच हजार वर्कर काम कर रहे थे । उससे इन्होंने आठ करोड़ रुपये मांगे । उनका मेरे पास टेलीफोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने सी0 एल0 वर्मा के बारे में ही क्यों कहा, हमारे बारे में भी कह देते । स्पीकर सर, ये उन दोनों बाप-बेटे के लफ्ज हैं । मैं ओन ओथ कहता हूं कि उन्होंने कहा कि आठ करोड़ रुपये मेरे से मांगे । आप चाहें तो इसके लिए एक हाउस की कमेटी बना दें और उस कमेटी में मुझे बुला लें, तब फिर मैं बताऊंगा कि इन्होंने क्या किया है । इन्होंने उससे आठ करोड़ रुपये मांगे लेकिन उसने कहा कि इतने मैं नहीं दे सकता, दस या बीस लाख की बात होती तो मैं कर सकता हूं, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं आठ करोड़ रुपये ही चाहिएं । पहले तो ये दस करोड़ रुपये मांग रहे थे लेकिन फिर आठ करोड़ पर आ गए । जब उसने रुपये देने से इन्कार कर दिया तो वह फैक्ट्री बन्द कर दी । पांच साल से वह फैक्ट्री बन्द है और पांच हजार लेबर इनकी मेहरबानी से आज भीख मांग रही है ।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उस बी0 एस0 टी0 में पांच साल से कर्मचारी बेकार बैठे हैं इसलिये अब तो आप उसको चालू करवा दो ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने कोशिश की है और उन्होंने वायदा भी किया है कि मार्च के महीने में यानि इसी महीने में इसको चालू कर देंगे ।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, अभी मुख्य मन्त्री जी ने फाईल का हवाला दिया, सर, आपको भी मालूम है कि अगर कोई एग्रीमैंट के रूल्ज को वायलेट करता है तो काम रुक जाता है । खुद सी० एल० वर्मा ने जो लिखा है, उसके बारे में मैं आपको कम्पनी वाला पैरा पढ़कर सुनाता हूं । मुख्यमंत्री जी बार-बार डील की बात कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आपकी फाईल मेरे पास आ गयी है ।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, लेकिन मैं भी इसको ओन रिकार्ड लाना चाहता हूं । सर, इसमें साफ लिखा है । The work on the fourlaning project between Sambalkha and Karnal.....(Noise & Interruptions).

Mr. Speaker : It is already with me, इसके अलावा कोई और बात बोलनी है तो बोलो, परन्तु इस पर नहीं ।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, अभी मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, श्री सी० एल० वर्मा की तो क्लीयर हो गई इसलिये ये अपनी पुरानी बात से भागना चाहते हैं, अपनी कही हुई बात से आज गवर्नमैंट भागना चाहती है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आपने दूसरे ऐलीगेशन पर बोलना है तो बोलें, इस पर न बोलें ।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जैसे बी० एस० टी० के बारे में मुख्य मन्त्री जी ने कहा है, जब भी कोई इंडस्ट्री लगती है उसके लिए कम्पनी लैण्ड लेती है । चेंज आफ लैण्ड की भी सैक्शन होती है जैसे एक हजार एकड़, दो हजार एकड़ या पांच सौ एकड़ चाहिए, उसने लैण्ड ली लेकिन उसका इस्तेमाल गलत किया । उसको बाकायदा इस बात का नोटिस दिया गया था कि आपने जो लैण्ड ली है, उस लैण्ड को उस परपज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जिस परपज के लिए आपने ली थी । वह चेंज आफ लैण्ड का फायदा उठाकर उससे दूसरे कामर्शियल गेन करना चाहता था, that is why Government gave notice, Sir. अगर सरकार कह रही है कि चार साल हो गए, प्लान्ट ने काम करना बंद कर दिया..... (श्री लहरी सिंह की तरफ से विघ्न)

Mr. Speaker : Lehri Singh Ji, no interruptions please. पहली बात तो यह है कि ऐलीगेशन आप पर नहीं लगाया, ओम प्रकाश चौटाला जी पर लगाया है । यह पार्टी पर नहीं लगाया है, पर्सनल लगाया है ।

प्रो० सम्पत सिंह : एक मैम्बर पर लगाया है । (Interruptions & Noise)

Mr. Speaker : Lehri Singh ji, please do not interrupt. Please take your seat.

Prof. Sampat Singh : Sir, I am the Leader of the Opposition Party. Shri Chautala is my member, that is why I am speaking, Sir.

Mr. Speaker : He should reply rather than you, please. He is already present in the House.

Prof. Sampat Singh : Sir, after me he will say something. I had also been in his Cabinet.

Mr. Speaker : May be, you were a Minister in that Cabinet but you cannot speak.

Prof. Sampat Singh : You have permitted me, Sir.

श्री अध्यक्ष : अच्छा, अपनी बात आप पांच मिनट में कह दें ।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, दुनिया देख रही है इस तरह से रूलिंग पार्टी की क्या पोजीशन होती है । I am not saying about the ruling party, Sir. स्पीकर सर, अभी जो बी० एस० टी० का जिक्र आया था, एक फैक्ट्री का जिक्र कर रहे हैं उसको जिस परपज के लिए लैण्ड दी गई थी, उस लैण्ड को उस परपज के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, अदर दैन दैट परपज किया था, इसलिये गवर्नमैंट ने उनको नोटिस दिया कि जिस परपज के लिये आपको लैण्ड मिली थी उस परपज के लिये आप लैण्ड का युटीलाइजेशन क्यों नहीं कर रहे हैं ,वह नोटिस था । ऐसा हमेशा होता रहा है कि अगर सरकार किसी सरकारी लैण्ड को या प्राईवेट लैण्ड को किसी स्पैशल परपज के लिये अलाट करती है और यदि कोई व्यक्ति लैण्ड यूज चेन्ज करवा लेता है तो सरकार उसको नोटिस देती है । वह नोटिस उनको दिया गया था, अदर-वाईज भी उनकी कोई अपनी लेबर प्रोब्लम थी । (शोर) आज फिर यह भी कह देंगे कि बी० एस० टी० से पैसा मांगा था जिस तरह से सी० एल० वर्मा की बात इन्होंने यहां पर कही । वह बिल्कुल असत्य निकली । (शोर)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : असत्य नहीं निकली, वह बिल्कुल सत्य है। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, यह सब कुछ आफटर थाट है। (शोर) यह वैलप्लैड है । (शोर) यह एक कांस्पीरेन्सी है सर । (शोर) इस लिये इन्होंने ऐसा किया है कि इस मामले में कुछ है ही नहीं और वह मामला बिल्कुल खत्म हो गया है (शोर) इसीलिये इन्होंने दूसरा मामला यहां पर लाने की कोशिश की है। (शोर) यह बिल्कुल असत्य और तथ्यों से परे है, निराधार है । (शोर) इन की सरकार को बने लगभग चार साल हो गये हैं और हमारी सरकार भी लगभग पौने चार साल रही । उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं होती थी । (शोर) लेकिन ये हर

[प्रो० सम्पत सिंह]

बात को यहां पर गोल मोल करना चाहते हैं । (शोर) केवल यही कह देना कि हमने फैक्टरी खुलवाने की बहुत कोशिश की है, कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे, इन बातों से कुछ नहीं बनने वाला । (शोर) इसका मतलब तो यह है कि इन लोगों में खुद में इस तरह की बहुत सारी कमियां हैं अगर इनमें अपने में यह कमियां हैं तो ये उन से डील करना चाहते होंगे । यह बिल्कुल असत्य है । असलियत में यह केस प्रिवलेज का ही बनता है । (शोर) इस तरह से ये हाउस को मिस लीड कर रहे हैं । (शोर)

श्री सतबीर सिंह कादयान : स्पीकर साहब, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा । (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही सीरियस मैटर है, यह कोई साधारण मैटर नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैंने हाउस में खड़े होकर इनकी प्रिवलेज मोशन के ऐलीगेशन को चैलेन्ज किया है । (शोर)

श्री सतबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस मसले पर कुछ बोलना चाहता हूं । मेरे भी कुछ अधिकार हैं यहां बोलने के ? (शोर)

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब, आप बैठिये । (शोर) क्योंकि मैं मुख्य मन्त्री महोदय को बोलने के लिये कह चुका हूं । (शोर)

श्री सतबीर सिंह कादयान : स्पीकर साहब, * * *

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब, आप बैठिये, कादयान साहब जो कुछ कह रहे हैं यह रिकार्ड न किया जाए । (शोर) सी० एम० साहब, अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोल लें, वरना मैं अपना फैसला इस पर सुनाता हूं । (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह इनका कोई बोलने का तरीका है ? (शोर)

श्री सतबीर सिंह कादयान : स्पीकर साहब, * * * * (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब, यह क्या तरीका है हाउस चलाने का ? यह क्या तरीका अपनाया जा रहा है कि प्रिवलेज मोशन पर जिन लोगों के हस्ताक्षर हैं, उनको आप बोलने नहीं दे रहे हैं, ताकि वे अपनी-अपनी बातें यहां हाउस में न कह सकें । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, मैंने पहले ही आपको बोलने के लिये कहा था (शोर)

*Not recorded as ordered by the Chair.

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, आप हमें इस तरह से सनद कर रहे हो और हमारे उन मैम्बर्ज को जिन्होंने प्रिवलेज मोशन पर हस्ताक्षर किये हैं, बोलने नहीं दिया जा रहा है । (शोर)

श्री अध्यक्ष : इन्होंने मुझ से कभी बोलने की मन्जूरी नहीं ली है । बिना आज्ञा के वे कैसे बोल सकते हैं ? (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, हम प्रिवलेज मोशन लाए हैं, उस पर तो हम बोलेंगे ही । (शोर) स्पीकर साहब, इन लोगों ने साथ में हमारे बारे में यह भी कहा कि हम भागेंगे । मैं इनको बताना चाहता हूं कि हम भागेंगे नहीं, हम तो फेस करेंगे । (शोर) जिन लोगों ने प्रिवलेज मोशन पर साईन कर रखे हैं, उनको बुलवाने की जिम्मेवारी आप की ही है । (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, सतबीर सिंह कादयान पहले अपनी बात कहेंगे । आप उन्हें बोलने क्यों नहीं देते ? (शोर)

(इस समय श्री कादयान सहित बहुत सारे मैम्बर बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब, आप बैठ जाएं । (शोर) आप सब बैठ जाएं । कादयान साहब मैं आपको बोलने की आज्ञा नहीं देता । आप कृपया बैठ जाएं । (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब, मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के प्रिवलेज मोशन पर दस्तखत हैं, वे कैसे नहीं बोल सकेंगे ? (शोर) आप उनको बोलने से कैसे रोक सकते हैं ? जिन मैम्बर्ज ने साईन किये हैं, वे तो जरूर कुछ न कुछ बोलेंगे ही (शोर) उनका बोलने का पूरा राईट है । यह सरकार प्रिवलेज मोशन को फेस नहीं करना चाहती । सब से पहले कादयान साहब इस पर बोलना चाहेंगे, उनके उस प्रिवलेज मोशन पर हस्ताक्षर हैं, सर ।

श्री सतबीर सिंह कादयान : स्पीकर सर, मुझे तकलीफ हुई है इसलिये मैं कुछ बोलना चाहूंगा, सर । (शोर)

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब आप बैठें । (शोर)

श्री सतबीर सिंह कादयान : स्पीकर साहब, आप मुझे यह बताएं कि और कौन सा प्लेटफार्म है जहां हम अपनी बात कह सकते हैं ? (शोर) मैं कहना चाहता हूं कि .....(शोर) * * *

श्री अध्यक्ष : जो कुछ कादयान साहब कह रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए ।

*Not recorded as ordered by the Chair.

चौधरी धीरपाल सिंह । यह क्या बात है स्पीकर सर, कि हमें अपने प्रिवलेज मोशन पर बोलने ही नहीं दिया जा रहा। (शोर) यह क्या तरीका है कि जिस तरह से हाउस के नेता चाहें, वही कुछ बोला जाए । (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप सब साहेबान बैठ जाएं । पहले मुझे इस बारे में कुछ बतलाने दो । (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब, पहले आप हमारी बात सुनिये, तब हम आपकी बात सुनेंगे । (शोर) हमने प्रिवलेज मोशन दिया है उस पर जिन लोगों के हस्ताक्षर हैं, वे अवश्य ही बोलेंगे । (शोर) यह कोई इनका हाउस चलाने का तरीका है क्या कि हम अपनी बात भी न कह सकें ? (शोर) हम सब अपनी बात अवश्य कहेंगे । (शोर) हम प्रिवलेज मोशन के सिवाये कोई बात मानने के लिये तैयार नहीं हैं । (शोर)

Mr Speaker : Hon'ble Member, Shri Om Parkash Chautala and other M.L.As have given a notice of breach of privilege. They had given it at 9.37 A.M. today (Interruptions). They had given it when the House had commenced. Here is my ruling on this. Rule 262 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly says:—

Notice of question of privilege

"262. A member wishing to raise a question of privilege shall give notice in writing to the Secretary before the commencement of the sitting on the day, the question is proposed to be raised. If the question raised is based on a document, the notice shall be accompanied by the document."

चूंकि यह नोटिस 9.37 पर आया था और कमेंसमैंट आफ दि हाउस 9.30 बजे हो चुकी थी । यह अंडर एग्जामिनेशन है इसलिए इस पर अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है ।

श्री सतबीर सिंह कादयान : स्पीकर साहब, मैं अपनी बात तो कह लूं ।

श्री अध्यक्ष : नहीं । आप बैठ जाइए ।

अध्यक्ष द्वारा रूलिंग—

किसी व्यक्ति को सदन के समक्ष साक्षी देने के लिए बुलाने संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, on 10th March, 1995, while the Hon'ble Chief Minister was replying to the debate on the Motion of Thanks to the Governor's Address, a point of order was

raised as to whether a person can be summoned before the House as a witness with a view to give an evidence. On this issue, I have carefully gone through the proceedings of the House dated 10th March, 1995 and I have also gone through the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assessmbly as well as the Book on Parliamentry Practice and Procedure. Neither a person has ever been summoned as a witness before the House in the Haryana Legislative Assembly nor I could lay my hands on a precedent anywhere in Parliament/State Legislatures where a witness was summoned before the House to give an evidence.

On the basis of the above, I hold that a person cannot be summoned as a witness before the House in order to give an evidence. So far as the question of enquiry into the allegation that Shri Om Parkash Chautala, M L.A. demanded a sum of Rs. 5 crores from Shri C.L. Verma, owner of Continental Constructions Limited which was entrusted with the construction of four-laning road is concerned, I place this matter for consideration of this august House in order to enable me to decide as to in what manner the enquiry of the aforesaid subject may be conducted. I, therefore, feel that further appropriate action in the matter will be taken up after a decision on this issue is taken by this august House so that an appropriate procedure is evolved in such like cases.

प्रो० छतर पाल सिंह के निलंबन को रद्द करने संबंधी मामला उठाना

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान चौधरी छत्तर पाल सिंह की सस्पैन्शन पर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कई दिन हो गए हैं इसलिए अब तो उनको वापिस ले लेना चाहिए। हमारे रूल 104 में लिखा हुआ है —

"(1) The Speaker shall preserve order and have all powers necessary for the purpose of enforcing his decisions on all points of order.

(2) He may direct any member whose conduct is, in his opinion, grossly disorderly to withdraw immediately from the Assembly and any member, so ordered, to withdraw shall do so forthwith and shall absent himself during the remainder of the day's meeting. If any member is ordered to withdraw a second time in the session, the Speaker may direct the member to absent himself from the meetings of the Assembly for any period not longer than the remainder of the session and the member so directed shall absent himself accordingly. Such member shall be deemed to be absent from the meetings of the Assembly for purposes of section 3(2) (a) of the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1975, but shall not be deemed to be absent for the purposes of Article 190(4) of the Constitution." अध्यक्ष महोदय, प्रो० छतरपाल सिंह को आपने नेम नहीं किया। यह सरकार आपके राइट्स को बेच करके सीधे रूल 121 के तहत मोशन ले आई जबकि आप

[श्री बंसी लाल]

द्वारा उनको नेम किए बगैर इनको वह मोशन नहीं लाना चाहिए था। इसके बावजूद मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप अपने आर्डरज को रिवोक करें और उनको हाउस में आने की इजाजत दें। मैं लीडर ऑफ दि हाउस से भी कहूंगा कि उनको हाउस में आने की इजाजत मिलनी चाहिए।

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, जैसे चौधरी बंसी लाल जी ने कहा, उससे मैं सहमत हूं। हम भी आपसे गुजारिश करेंगे कि प्रो0 छतर पाल सिंह, जिन को हाउस से बाहर रहते हुए एक हफ्ता हो गया है, बुला लिया जाए। गवर्नर ऐड्रैस पर भी बहस खत्म हो ली और कल बजट भी पेश हो गया। आज बजट पर डिस्कशन शुरू होनी है। यदि आप उनको हाउस में आने की इजाजत दे देंगे तो वे भी बजट पर बोल सकेंगे और अपने हल्के की समस्याएं यहां पर रख सकेंगे। इसलिये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने आर्डर्ज को रिव्यू करें और उनको यहां हाउस में आने की इजाजत दे दें ताकि वे अपने हल्के और स्टेट के ईशूज को यहां पर उठा सकें। (शोर)

श्री अध्यक्ष : बेरी साहब, क्या प्रो0 छतरपाल सिंह आपकी पार्टी के हैं।

Ch. Jagdish Nehra : Speaker Sir, he is a leader of unattached party and Prof. Chhattar Pal Singh is a member of his party.

श्री ओम प्रकाश बेरी : स्पीकर साहब, दरअसल बात यह है कि बजट सैशन चल रहा है और यहां हाउस में हर एम0 एल0 ए0 को अपनी अपनी बातें कहने का अधिकार है। प्रो0 छतरपाल सिंह को हाउस से निष्कासित करने के कारण उनकी कांस्टीच्यूएंसी अन-रिप्रेजैंटिड रह गई है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने फैसले को री-कंसिडर करें और उनको हाउस में आने की इजाजत दें ताकि वह डिबेट में हिस्सा ले सकें ताकि वह अपनी कांस्टीच्यूएंसी की बात यहां पर कह सकें। आज उनको निष्कासित किए हुए 6 दिन हो गए हैं। यह उनके लिए काफी सजा है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि सरकार उनके विरुद्ध जो मोशन ले कर आई थी, उस पर आप पुन: विचार करें और उनको सदन में आने की इजाजत दें ताकि डिबेट इफैक्टिव तरीके से चले और माननीय सदस्य अपने हल्के की बात कह सकें।

प्रो0 राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, अब तो आपका भी मन कर रहा है कि उनको हाउस में आने की इजाजत दे देनी चाहिए। आप बड़े उदार हैं। सदन के नेता से चौधरी बंसी लाल जी ने भी आग्रह किया है और हम सब आग्रह कर रहे हैं कि उनको सदन में आने की इजाजत मिलनी चाहिए। स्पीकर साहब, आप तो इस सदन के कस्टोडियन हैं। स्पीकर साहब, इस बारे में हमने कल भी आपसे रिक्वैस्ट की थी। चौधरी भजन लाल जी, आप इसको इतना प्रैस्टीज ईशू न बनाएं। आप नेहरा जी की सारी बातों को न माना करें। चौधरी बंसी लाल जी बहुत वरिष्ठ

नेता हैं, इन्होंने भी आपसे रिक्वैस्ट की है । आप हमारी बात को मानें और प्रो० छतरपाल सिंह को सदन में आने की इजाजत दें ताकि वह अपने हल्के की बात यहां पर कह सकें । He is feeling sorry. तो आपसे गुजारिश है कि चौधरी भजन लाल जी, आप इस बात को प्रैस्टीज ईशू न बनाएं और अपने प्रस्ताव को वापिस लें ।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर वह हाउस में फिर कोई गड़बड़ करेंगे तो आपको यह अधिकार है कि आप फिर उसको बाहर निकाल दें । मैं यह भी कहूंगा कि नेहरा साहब की बजाय चौधरी भजन लाल जी आप खुद बोलें क्योंकि नेहरा साहब को पढ़ना नहीं आता । ये थोड़े पढ़े लिखे हैं इसलिए ये उल्टा पढ़ेंगे । (हंसी)

श्री जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, चौधरी बंसी लाल जी बुजुर्ग हैं । मैं इनके बारे में बहुत कुछ कह सकता हूं । मैं इनको यह भी बता सकता हूं कि ये 11.00 बजे खुद कितने पढ़े लिखे हैं और मैं कितना पढ़ा लिखा हूं । स्पीकर साहब, इन्होंने दो-तीन बार कह दिया कि मुझे पढ़ना नहीं आता । अब मैं इन से बुजुर्ग होने के नाते कुछ कहना नहीं चाहता । अगर मैं ऐसी कुछ बात कह दूंगा तो फिर चौधरी बंसी लाल जी कभी नहीं कहेंगे कि मुझे पढ़ना नहीं आता । अध्यक्ष महोदय प्रो० छत्तर पाल सिंह का व्यवहार बड़ा खराब रहा था । हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जिस कारण उसे स्पीकर साहब की बात भी न माननी पड़े । स्पीकर साहब के खड़े होने के बावजूद भी वे आपत्तिजनक ढंग से खड़े रहे । हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि जब अध्यक्ष महोदय, खड़े हों तो उनके सम्मान में हम सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं । लेकिन वे दो-दो घण्टे तक बैठे नहीं और दो तीन दिन लगातार वे ऐसा ही करते रहे । स्पीकर साहब ने उनको बैठने के लिए एक दो बार नहीं, बीसियों बार कहा लेकिन वे नहीं माने । दूसरे उन्होंने कई बातें डैरोगेटरी कहीं और स्पीकर साहब के बारे में भी उनका अशोभनीय व्यवहार रहा । (विघ्न) उनके शब्द मुझे सुनाई दिए यहां पर, तो ये फिर कैसे हो सकता है कि उन्होंने नहीं कहे । उन्होंने ऐसे डैरोगेटरी शब्द पहले दिन भी कहे, दूसरे दिन भी कहे । उन्होंने हाउस की कोई डिगनटी नहीं रखी और न ही उनकी हाउस की डिबेट में कोई कन्ट्रीब्यूशन रही । उनका काम सिर्फ एलीगेशन लगाना ही रहा । जैसा विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि अब उन्होंने महसूस कर लिया है, ऐसी बात नहीं है क्योंकि खुद चौधरी बंसी लाल जी भी कह रहे हैं कि यदि दुबारा वह ऐसी गलती करेंगे तो फिर निकाल सकते हैं । इसका मतलब यह हुआ कि ये भी खुद संतुष्ट नहीं है कि उनका व्यवहार आगे ठीक ही रहेगा या नहीं । इनको खुद पूरी तरह से कान्फीडैंस नहीं है ।

श्री बंसी लाल : मैंने तो यह कहा है कि यदि आप समझें कि उसका व्यवहार ठीक न लगे तो फिर दोबारा निकाल सकते हैं ।

श्री जगदीश नेहरा : उनका व्यवहार ठीक नहीं रहेगा । यह भी अच्छा नहीं लगता कि उनको बार बार निकाला जाये । अब उनको पुनः हाउस में लेने की बात ठीक नहीं है ।

Mr. Speaker : I have already quoted here Rule 121, which says—

> "Any member may, with the consent of the Speaker, move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the Assembly and if the motion is carried, the rule in question shall be suspended for the time being."

and the motion was moved and it was adopted by the House.

श्री बंसी लाल : मेरी सबमिशन यह है कि रूल 121 बाद में आता है । पहले चेयर की तरफ से उसे नेम करना पड़ता है । यदि फिर भी न माने तो पुनः नेम करना पड़ता है, यदि फिर भी न माने तो फिर चेयर की अवहेलना करने के कारण यह रूल लाने के लिये चेयर सरकार को कहती है और फिर सरकार मोशन मूव करती है, तब जाकर रूल सस्पेंड होता है, आर्डनरी प्रोसीजर तो यही है, बाकी आपकी मर्जी है ।

Mr. Speaker : I had already warned him and consented for moving the motion.

श्री बंसी लाल : क्या आपने उनको रोका, वार्निंग दी ?

अध्यक्ष द्वारा रूलिंग (पुनरारम्भ) तथा उस पर चर्चा

Mr. Speaker : Now the matter ends. So far as the question of inquiry into the allegation that Shri Om Parkash Chautala, MLA demanded a sum of Rs. 5 crores from Shri C. L. Verma, owner of Continental Constructions company, which was entrusted with the construction of fourlaning road is concerned, I place this matter for consideration of this august House in order to enable me to decide as to in what manner the inquiry of the aforesaid subject may be conducted I, therefore, feel that further appropriate action in the matter will be taken up after a decision on this issue is taken by this august House so that an appropriate procedure is evolved in such like cases.

चौधरी वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मेरे दिमाग में एक सुझाव आ रहा है । वैसे तो उस दिन मुख्य मन्त्री जी ने भी कहा था कि यह मामला स्पीकर साहब पर छोड़ दिया जाए और आपने यहां पर हाउस में फरमाया है कि कोई ऐसा प्रैसिडेंट नहीं है कि विटनैस को सदन में बुलाया जा सकता है । आपकी यह रूलिंग आ गई

है । इसमें एक तो यह हो सकता है कि इस मामले को आप पर छोड़ दिया जाए, जिस तरीके से भी आप तसल्ली करना चाहें, कर सकते हैं । दूसरी बात यह हो सकती है कि हाउस की एक कमेटी कान्स्टीच्यूट कर दी जाए । वह कमेटी अपनी तसल्ली कर लेगी । बेशक दोनों मेटर इसी कमेटी को दे दीजिए । (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, इस बारे में मेरी सबमिशन है कि चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने स्पीकर साहब का भी हवाला दे कर सुझाव दिया है । स्पीकर सर, हमें चेयर में पूरी आस्था है और हम चेयर की कद्र करते हैं । स्पीकर सर, मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कहना चाहता हूं कि इस मैटर को इस हाउस की जो प्रिवलेज कमेटी है, उसको दे दिया जाए । प्रिवलेज कमेटी एक बड़ी कमेटी है । स्पीकर सर, यह कमेटी या तो ड्यूली इलैक्टिड है या आपके द्वारा नोमिनेटिड है, यह मामला इस प्रिवलेज कमेटी को दे दिया जाये । हमने जो प्रिवलेज मोशन दिया हुआ है, वह अपने आप क्लीयर हो जाएगा और प्रिवलेज कमेटी इसको डिसाईड कर देगी । स्पीकर सर, जैसा कि आपने कहा है कि ऐसा कोई प्रैसिडैंट नहीं रहा है जिस के तहत फिटनैस के लिए हाउस में किसी को बुलाया जाए; न ही ऐसी कोई कन्वैन्शन ही रही है । इस बारे में स्पीकर साहब, पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कन्वैंशन या प्रैसिडैंट जो बनती हैं, वह कहीं न कहीं तो बनती ही हैं । अगर पहले कोई प्रैसिडैन्ट या कन्वैंशन नहीं है तो उसको अब बना सकते हैं क्योंकि जब बाकायदा साईन्ड एण्ड वैरिफाईड स्टेटमैंट हमने आपको दे दी है तो उस बेस पर आप प्रैसिडैन्ट बना सकते हैं क्योंकि आईन्दा आने वाले वक्त में भी कोई भी सत्तासीन आदमी सत्ता से मदहोश हो कर किसी पर भी कोई भी लान्छन लगा सकता है । स्पीकर सर, इसलिये मैं कह रहा हूं कि आईन्दा के लिये एक हैल्दी प्रैसिडैन्ट हैल्दी कन्वैन्शन बन जाएगी । स्पीकर सर, आप बेहतर जानते हैं कि इंग्लैंड का कान्स्टीच्यूशन, टोटली प्रैसिडैंशियल एण्ड कन्वैन्शन्ज पर आधारित है । वहीं से हमने अपना संविधान लिया है । एक अच्छी बात की कन्वैन्शन तो हमें डालनी चाहिये । बुरी बात की चाहे कन्वैन्शन भी रही हो, तो भी हम लोगों को उसे ड्रौप कर देना चाहिये । स्पीकर सर, इसलिये मैं तो यही अपील करूंगा तथा सुजैस्ट करूंगा कि जैसे हमने रैजोल्यूशन दिया है कि इस मैटर को हाउस की ब्रीच आफ प्रिविलेज, आप एडमिट करें और प्रिविलेज कमेटी को इसको दे दें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए । स्पीकर सर, हमें यही मान्य होगा । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : पहले मिनिस्टर साहब खड़े हैं, ये अपना सुजैशन दे दें फिर आप बोल लेना ।

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर सर, मैं कहना चाहूंगा कि प्रिविलेज कमेटी को मैटर तब जाता है जहां हाउस इस बात को मान ले कि कहीं ब्रीच हुआ है तो वह मामला डायरैक्ट रैफर होता है । इस केस में यह अलैज कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है लेकिन हाउस ने इसको एसैप्ट नहीं किया । स्पीकर सर, इसके लिये तो एकमात्र रास्ता है कि

[श्री ए0 सी0 चौधरी]

हाउस की एक कमेटी बन जाए, वह इस बात को एग्जामिन करे कि दोनों बातें जो कहीं गई हैं, वे टैंटामाउंट करती हैं या ब्रीच आफ प्रिविलेज के लिये फरदर इन्वैस्टिगेशन मांगती हैं। इन्वैस्टिगेशन ही एक मात्र रास्ता है। हाउस की कमेटी बना दी जाए जो कि कन्कलूड कर दें कि आया कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है, अगर हुआ है तो उसके बाद जो प्रौसैस है वह हो सकता है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि चौटाला साहब के ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया और मुख्यमंत्री जी ने उसका हवाला दिया और आपने भी अपनी रूलिंग रिजर्व रखी तथा आज भी सदन के ऊपर छोड़ दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे देश के अन्दर कोई भी पार्लियामैंटरी कन्वैन्शन नहीं है कि हाउस की कमेटी बनाई जाए या प्रिविलेज कमेटी को मामला सौंप दिया जाए। मुझे भी पार्लियामैंट तथा इस हाउस में बैठते हुए 30-35 साल हो गए हैं। अध्यक्ष महोदय होता तो यह है कि एक मैम्बर ने दूसरे मैम्बर के ऊपर एलिगेशन लगा दिया और उसने मना कर दिया तो वह बात वहीं खत्म हो जाती है। अगर आप आज कमेटी बना देते हैं तो भविष्य में यह एक प्रैसीडैन्ट बन जाएगा। तो मेरा यह कहना है कि यह मामला यहीं पर बन्द कर दें। यह मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं आपके जरिए सदन के नेता से भी कहूंगा कि यह मामला यहीं पर बन्द कर दें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि बी0एस0टी0 ने पूरी जमीन इस्तेमाल नहीं की जिसके लिये इन्होंने ली हुई है। यह जमीन आज की नहीं है, यह फैक्टरी आज की नहीं है, यह ज्वायंट पंजाब के समय की लगी हुई है। अध्यक्ष महोदय, ये हमेशा बिना सिर-पांव की बात कहते हैं। मैं तो आपसे कहता हूं कि आप हाउस की कमेटी बना दें और ये दोनों मामले उस कमेटी को सौंप दें या फिर चौधरी बंसी लाल जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दें और वे दोनों से पूछ कर हाउस को बता दें।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये तैयार नहीं हूं। मैं तो आपके जरिए यह कहूंगा कि ऐसी कन्वैंशन न डालें और यह मामला यहीं पर बन्द कर दें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं बंसी लाल जी की बात से सहमत हूं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, बंसी लाल जी ने ठीक कहा है। आज भ्रष्टाचार के इतने मामले हैं, आप कहां कहां पर कमेटियां बनाते रहेंगे? हाउस पर छोड़ने का मतलब है कि टोटल हाउस की कन्सैंट हो। अगर हाउस की कन्सैंट ही न हो तो कैसे हो सकता है? आप ऐसा करें कि यह मामला जनता पर ही छोड़ दें और एक साल बाद सब पता चल जाएगा।

Mr. Speaker : As it is the consensus of the House that the matter should be closed, the matter is closed.

No more discussion on this subject will be allowed now.

ध्यानाकर्षण सूचनाएं/नियम 84 के अधीन प्रस्ताव

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे कालिंग अटैन्शन मोशन पर बोलना है।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, the calling attention motion No. 11, given notice of by Smt. Chandravati, M.L.A. regarding repairing of lift irrigation water courses in district Bhiwani has been admitted for 20th March, 1995.

The calling attention motion No. 5 given notice of by Shri Karan Singh Dalal M.L.A. regarding pollution being at the extreme in whole of district Faridabad has been admitted for 21st March, 1995.

The calling attention motion No. 25, given notice of by Shri Ram Bilas Sharma, M.L.A. regarding non-availability of kerosene oil and wheat on ration shops and black marketing in Haryana State has been admitted for 15th March, 1995.

The calling attention motion No. 27, given notice of by Shri Satbir Singh Kadian M.L.A. regarding pollution due to waste ash and water of Thermal Power Plant, Panipat and spreading of disease in the nearby villages has been sent to the Government for comments.

The calling attention motion No. 30 given notice of by Shri Amar Singh Dhanday and two other M.L.As. regarding atrocities on Harijans of Village Keorak, Distt. Kaithal has been sent to the Government for comments.

श्रीमती चन्द्रावती : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और मोशन राजधानी क्षेत्र के बारे में था जिसमें कहा गया था कि हरियाणा की सारी जमीन का इस्तेमाल किया गया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी आपकी सेवा में अपना एक मोशन फरीदाबाद में बिगड़ी कानून और व्यवस्था के बारे में दिया था, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि पुलिस संरक्षण में वहां अपराध हो रहे हैं लेकिन आपने उस पर अपनी रूलिंग देते हुए उसको डिसअलाउ कर दिया। अध्यक्ष महोदय, कोई बात नहीं मैं इस बारे में अपनी बात बजट स्पीच में कह लूंगा।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी एक बात और कहनी है कि जिला फरीदाबाद में जमुना के साथ लगते हुए जो हरियाणा के गांव हैं वहां पुलिस ने उत्तर प्रदेश के किसानों से पैसा लेकर हमारे लोगों को थानों में बिठा रखा है। यह सब पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। (विघ्न)

श्री राम रतन : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष : आप अभी बैठिए। (विघ्न)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी तो इसको टालने की बात कर रहे हैं हरियाणा के हित को देखते हुए इनको इसका जवाब देना चाहिये।

श्री राम रतन : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे भी समय दें।

श्री अध्यक्ष : आप अभी बैठिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे पलवल तहसील के यमुना के साथ लगते हुए धोड़ी और चांट गांव हैं, उनके मुख्य-मुख्य आदमियों को पलवल के सदर थाने में पुलिस ने बैठा रखा है। ये किसान अपने अपने खेतों की फसल काटने गए हुए थे लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों ने हरियाणा की पुलिस को पैसा देकर उनको बंद करवा दिया है। उत्तर प्रदेश के किसान उनकी फसल काटकर यू0पी0 में ले जाते हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, इनके तो गांव यमुना के किनारे लगते ही नहीं हैं बल्कि जमुना के किनारे तो हमारे इलाके के गांव लगते हैं।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कर्ण सिंह जी ने कहा कि पलवल के थाने में किसान बैठा रखे हैं। आप जानते हैं कि यमुना के किनारे पर खेत हैं। जब यमुना अपना बहाव बदलती है तो उस हिसाब से लोग खेती करने की कोशिश करते हैं। कई बार यमुना जब यू0 पी0 की साईड में चली जाती है तो हरियाणा के लोग उस जमीन में काश्त कर लेते हैं जबकि जमीन की मलकियात उनकी है और कई बार जब यमुना का बहाव इधर की ओर आ जाता है तो यू0 पी0 वाले उस जमीन पर काश्त कर लेते हैं और फसल काटते समय उनमें झगड़ा हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, इसको हम दिखवा लेंगे और जो ठीक बात होगी वह कर लेंगे।

श्री ओम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो मोशन नियम 84 के अधीन थे। एक तो मेरा मोशन एस0वाई0एल0 की कम्पलीशन के बारे में था और दूसरा यमुना के ऐग्रीमैन्ट के बारे में था जिसमें हरियाणा के हितों को बेच दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, एस0वाई0एल0 का मामला तो हरियाणा प्रदेश के हित की बात है इसलिये आप मेरे इन दोनों मोशंज पर दो घन्टे की बहस करा दें ताकि सारी चीजें ठीक से हाउस में आ सकें।

श्री अध्यक्ष : बेरी साहब, आपके मोशन अभी अंडर कंसीडेशन हैं।

डॉ0 राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैंने 9 मार्च को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था कि 7 मार्च 1995 को कुरुक्षेत्र जिले में देवीदासपुरा, रतगल, उमरी और पलवल गांवों की जमीन हुडा ने ऐक्वायर की है, इस 215.83 एकड़ जमीन के अतिरिक्त

इन गांवों और सुन्दरपुर की 255.43 एकड़ भूमि और ऐक्वायर होने लगी है। इन गांवों के किसानों को जो रेट दिया जा रहा है, वह 1991-92 के मार्किट रेट से भी कम है। चीफ मिनिस्टर साहब ने कुंडली जिला सोनीपत में घोषणा की थी कि बड़ी जल्दी यह फैसला करेंगे कि जहां किसान की जमीन ऐक्वायर की जाती है, उसके लिये पिछले पांच साल का औसत न लेकर, मार्किट रेट पर मुआवजा दिया जाए। कुरुक्षेत्र के इन लोगों में इस बात को लेकर काफी चिंता और घबराहट है। 7 मार्च को जमीन ऐक्वायर हुई है और 20 तारीख को पेमैन्ट करनी है, इस नाते मैं चाहूंगा कि मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को एडमिट करें ताकि इस के बारे में चर्चा की जा सके।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, डा0 राम प्रकाश जी ने ठीक बात कही है कि मैंने कुंडली में यह बात कही है। मैंने ऐलान किया है और आज फिर सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी किसानों की जमीन ऐक्वायर होगी, उनको मार्किट रेट का पैसा दिया जाएगा। पिछले पांच साल के ऐवरेज के हिसाब से नहीं दिया जाएगा, मेरी बात पर आप विश्वास रखें।

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर सर, हमारी तरफ से एक काल अटैंशन मोशन, स्टोन क्रशर के बारे में है। ये स्टोन क्रशर तोशाम के पास खानक गांव में लगे हैं। स्टोन क्रशर से होने वाले पौल्यूशन की वजह से वहां के लोग तपेदिक की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। इस बात को लेकर लोग कोर्ट में गए हैं और कोर्ट के फैसले भी लोगों के हक में आए हैं। इसलिये मैं गुजारिश करूंगा कि उन क्रशर्ज को क्रशर जोन बनाकर शिफ्ट किया जाए ताकि वहां पौल्यूशन न हो।

Mr. Speaker : It is disallowed as the matter is sub-judice and pending in the Hon'ble Supreme Court.

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात है कि खानक में जो क्रशर लगे हुए हैं, वे आन रोड हैं। वहां वाकई लोगों को बड़ी तकलीफ है। हमने फैसला किया है कि क्रशर यहां से उठ जायें। उनको थोड़ा समय दिया गया है। हमने उनको अलग जगह भी बता दी है, वहां क्रशर जाएंगे। उसमें छह महीने लग सकते हैं। हमारी कोशिश है कि छह महीने के बाद वहां कोई क्रशर न रहे।

साथी लहरी सिंह : स्पीकर सर, अभी चौटाला साहब के केस में जो गहमागहमी हो रही थी, तो हमारे भाई दरियाव सिंह जी ने बैठे बैठे एक बात कहीं कि मैंने * * * * * * * * * *

स्पीकर सर, इनको यह फोबिया हो गया है। स्पीकर सर, मैंने तो शुरु से ही जब से अपनी जिन्दगी संभाली आठ आने की मजदूरी की, एक रुपये की मजदूरी की है। मजदूरी करके रोटी खाता हूं। * * * * *

---

*Not recorded as ordered by the Chair.

श्री अध्यक्ष : न इसकी बात रिकार्ड पर आई है और न आपकी बात रिकार्ड पर आयेगी, इसलिये आप बैठिए ।

बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I have to report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various Business.

"The Committee met at 4.00 P.M. on Monday, the 13th March 1995 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly whilst in session, shall meet on Monday at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. and on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. without question being put.

The Committee also recommends that on Tuesday, the 28th March, 1995, the Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the business entered in the list of Business for the day.

The Committee, after some discussion, further recommends that the business from 14th March, 1995 to 15th March, 1995, 20th March, 1995 to 24th March, 1995 and from 27th March, 1995 to 28th March, 1995 be transacted by the Sabha as under :—

Tuesday, the 14th March, 1995 (9.30 a.m.)	1. Questions Hour.
	2. Presentation and adoption of Second Report of the Business Advisory Committee.
	3. Papers to be laid on the Table of the House.
	4. General discussion on the Budget Estimates for the year 1995-96.
Wednesday, the 15th March, 1995 (9.30 a.m.)	1. Questions Hour.
	2. Resumption of discussion on the Budget Estimates for the year 1995-96.
Thursday, the 16th March, 1995	Off Day
Friday, the 17th March, 1995	Holiday

Saturday, The 18th March, 1995	Off Day
Sunday, the 19th March, 1995	Holiday
Monday, The 20th March, 1995 (2.00 p.m.)	1. Questions Hour. 2. Resumption of general discussion on the Budget Estimates for the year 1995-96.
Tuesday, the 21st March, 1995 (9.30 a.m.)	1. Questions hour. 2. Resumption of general discussion on the Budget Estimates for the year 1995-96.
Wednesday, the 22nd March, 1995 (9.30 a.m.)	1. Questions Hour. 2. Resumption of general discussion on the Budget Estimates for the year 1995-96 and reply by the Finance Minister.
Thursday, the 23rd March, 1995 (9.30 a.m.)	1. Questions hour. 2. Non-official Business.
Friday, the 24th March, 1995 (9.30 a.m.)	1. Questions hour. 2. Presentation of Assembly Committee Reports. 3. Discussions and Voting on Demands for Grants on the Budget Estimates for year 1995-96.
Saturday, the 25th March 1995	Off day
Sunday, the 26th March, 1995	Holiday
Monday, the 27th March, 1995 (2.00 p.m.)	1. Questions Hour. 2. Appropriation Bill in respect of Supplementary Estimates for the year 1994-95. 3. Appropriation Bill in respect of Budget Estimates for the year 1995-96. 4. Legislative Business. 5. Official Resolutions.
Tuesday, the 28th March, 1995 (9.30 a.m.)	1. Questions hour. 2. Motion under Rule 15 regarding non-stop sitting.

[Mr. Speaker]

3. Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha Sine-die.

4. Presentation of Assembly Committee Reports.

5. Legislative Business.

6. Any other Business."

Mr Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contai nedin the second Report of the Business Advisory Committee.

Irrigation Minister (Chaudhri Jagdish Nehra) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

Mr Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

Mr Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

The motion is carried.

सदन की मेज पर रखे गये कागज-पत्र

Mr Speaker : Now a Minister will lay papers on the Table of the House.

Irrigation Minister (Chaudhri Jagdish Nehra) : Sir I beg to lay on the Table —

1. The Memorandum of Action taken on the Annual Report of National Human Rights Commission for the year 1993-94 as required under section 20 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

2. The Administrative Report of the Haryana State Electricity Board for the year 1992-93 as required under section 75(i) of the Electricity (Supply) Act, 1948.

3. The Statement showing the loans raised by the Haryana State Electricity Board upto 15-1-1995 as required under section 66 of the Electricity (Supply) Act, 1948.

वर्ष 1995-96 के बजट पर सामान्य चर्चा

Mr Speaker : Hon. Members, now general discussion on the Budget for the year 1995-96 will take place.

बिजनैस एडवाजरी कमेटी में यह तय हुआ है कि आर0एस0जे0पी0 के दो मैम्बर आधा आधा घंटा बोलेंगे और विकास पार्टी का एक सदस्य आधे घंटे के लिये बोलेगा, बाकी सब को 5-5 मिनट का टाईम देंगे । अपने हल्के की कोई भी बात कहने का सभी मैम्बर्ज को हक है, इस साइड से भी और ट्रेजरी बैंचिज से भी ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला (नरवाना) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री श्री मांगे राम जी ने बजट पेश करते वक्त बहुत बुलन्द दावे किए । इन दिनों में सामान्य तौर पर बजट आते ही हैं । व्यापारी भी अपना बस्ता तैयार करता है और किसान भी साल का अपना लेखा जोखा देखता है । प्रादेशिक सरकारें भी देखती हैं कि क्या योजना है, क्या खोया और क्या पाया । सरकारें इस बात पर विचार विमर्श करती हैं । इससे राजनीतिक नफे नुक्सान को भी आंका जा सकता है । इस सरकार की गलत इकनोमिक पालिसी और गलत नीति की वजह से अभी रीसैंटली हुए चुनावों में इनको लोगों ने खूब सबक सिखा दिया । आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आपकी पालिसी को लोगों ने पसन्द नहीं किया । इन्हें भी अपना ध्यान नहीं है इसलिये इसी आधार पर इन्होंने झूठे आंकड़े दे कर बजट पेश किया है । इससे इनकी भी सोच बन गई है । ये सोचते हैं कि तुमने अब जाना है । इन्होंने जिस तरीके का बजट पेश किया है, उससे सरकार की आमदनी नहीं बढ़ी बल्कि कर्जा बढ़ाया गया है । इससे जाहिर है कि कर्जा तो आने वाली सरकार देगी इन्होंने तो मौज लूटने का काम किया है । इनके अपने आंकड़ों के आधार पर मैं आपके द्वारा हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आपको आधा घंटा दिया गया है, टाईम का ध्यान रखना ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब, आप तो बड़े फराख दिल हैं लेकिन जब मैं खड़ा होता हूं तो पता नहीं आपको तकलीफ क्यों हो जाती है । मैं जो बात कहूंगा अगर वह इनको अच्छी लगे तो मान लेना और अगर अच्छी न लगे तो वह आपको काटने का अधिकार पहले ही है । तो मैं राजस्व घाटे की बात के बारे में कहना चाहता था । हरियाणा के राजस्व की आमदनी खर्चे से पहले हमेशा ज्यादा थी । इसलिये यह प्रदेश इस दृष्टिकोण से सरप्लस माना जाता था । अब जो आंकड़े आए हैं इनसे पता चलता है कि पहली बार 1994-95 में इस सरकार ने स्थिति को बदल कर हरियाणा सरकार को रैवेन्यू डैफिसिट स्टेट बना दिया है । इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है । मेरे ख्याल में यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने काम ही इस किस्म के किए हैं । सरकार ने 1995-96 के बजट में भी इस स्वस्थ परम्परा को कायम रखने की कोशिश की है । वर्ष 1995-96 के राजस्व की आमदन पांच हजार चार करोड़ रुपए

[चौधरी ओम प्रकाश चौटाला]

दिखाई गई है और खर्चा पांच हजार 48 करोड़ रुपए दिखाया है। तो राजस्व का घाटा 44 करोड़ रुपए है। इससे जाहिर होता है कि सरकार फिजूल खर्ची में ज्यादा दिलचस्पी रखती है। इसीलिए पब्लिक का कर्जा दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से 1994-95 के अन्त में प्रदेश 5015 करोड़ रुपए का कर्जदार हो जाएगा जो कि पिछले साल से 438 करोड़ रुपए ज्यादा है। इस बजट के मुताबिक 537 करोड़ रुपए का कर्जा और बढ़ जाएगा। इससे साफ जाहिर है कि कर्जे की हर साल परसैंटेज बढ़ती जा रही है। यह सरकार कर्जे से ही हकूमत चला रही है। मैंने पहले भी कहा है कि इनकी यह सोच है, इन्होंने जाना है इसलिये कर्जा वापिस देने के लिये आगे आने वाली सरकार अपने आप निपटती रहेगी। इन्होंने तो फिजूल खर्ची करनी है। इस सरकार की वित्तीय साधन ठीक इस्तेमाल करने की पालिसी ठीक नहीं है। इस सरकार के लौन एंड एडवांसिज बढ़ रहे हैं, उनकी रिकवरी की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1993-94 में 290 करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया और उसमें से वसूली सिर्फ 32 करोड़ रुपए की हुई। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1995-96 के बजट में 463 करोड़ रुपए का कर्जा देने का प्रावधान किया गया है यानि कर्जे की 173 करोड़ रुपए की राशि और ज्यादा दी जाएगी और इनका वसूली का लक्ष्य 33.40 करोड़ रुपए का है। इससे ऐसा लगता है कि कर्जा बोगस आदमियों को और बोगस कम्पनियों को दिया जा रहा है और इस तरह से भ्रष्टाचार करवा रहे हैं। सरकारी कोष में से पैसे को खुर्दबुर्द किया गया है, ये उस पैसे की वसूली की कोई जरुरत नहीं समझते और इनसे यह उम्मीद भी नहीं है कि ये यह पैसा भी वसूल कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से इन्होंने खर्चा दिखाने की कोशिश की है, इस बारे में क्वैश्चन आवर में यह जिक्र आया था कि भाखड़ा मेन लाइन को रैस्टोर करने के लिये सरकार प्रयास कर रही है। अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा दुखदायी बात और क्या हो सकती है कि इस सरकार ने भाखड़ा मेन लाइन को रैस्टोर करने के लिये केवल 15 लाख रुपए रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, 1990 में हमारी सरकार थी, उस समय भाखड़ा नहर के लिये 8 करोड़ रुपए रखे गए थे क्योंकि पंजाब के एरिया में उसकी मुरम्मत करने, गाद निकालने और बैंक्स को मजबूत करने के लिये पैसा खर्च होता है। वह पैसा हरियाणा सरकार वहन करती है और पंजाब सरकार को दिया जाता है। हमारी सरकार ने 1 करोड़ 90 लाख रुपए एक किश्त के, पंजाब सरकार को दी थी। हमारी सरकार के जाने के बाद इन्होंने अपने तीन साल के बर्से में उस नहर पर कोई काम नहीं किया। इस सरकार ने तो उस नहर के लिये इस साल केवल 15 लाख रुपए रखे हैं और इस पैसे से ये उसकी मुरम्मत करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की नालायकी की वजह से हमें भाखड़ा नहर से जो 12000 क्यूसिक्स पानी मिलता था, वह घट कर अब केवल 6 हजार क्यूसिक्स रह गया है। हमारे हरियाणा प्रदेश में कोई नैचुरल वाटर फ्लो नहीं है और न ही कोई दरिया है और जो दरिया हैं, जैसे घग्गर है, टांगरी है और मारकण्डा है, ये दरिया बरसात के दिनों में हरियाणा प्रदेश के अन्दर तबाही

मचा देते हैं। उनकी बाढ़ से लोग तबाह हो जाते हैं। उन नदियों के पानी से सिंचाई नहीं होती है। जो पानी के साधन हैं, उनके बारे में इस सरकार की कोई तवज्जो नहीं है। अध्यक्ष महोदय, भाखड़ा मेन लाइन को रैस्टोर न करने की वजह से हमारे हिस्से का पानी यह सरकार पंजाब से नहीं ला पाती। यह तो इनको ही मालूम होगा कि इस 15 लाख रुपए में यह सरकार क्या करने जा रही है? इसी तरीके से इन्होंने फलड कंट्रोल के लिये 10 करोड़ रुपए रखे हैं। इस 10 करोड़ रुपए में तो एस्टेब्लिशमैंट का खर्चा ही पूरा नहीं होगा। यह पैसा तो स्टाफ की तनखाहों पर ही खर्च हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस सरकार को प्रकृति के प्रकोप का ज्ञान ही नहीं है, इसलिये यह सरकार फलड की पेशबन्दी क्या करेगी? अध्यक्ष महोदय, पिछले से पिछले साल हरियाणा प्रदेश के अन्दर जो बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से प्रदेश का जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया था, लोगों के मकान बर्बाद हो गए थे, फसलें बर्बाद हो गई थी उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अगर उस प्रकार के फलड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा और फलड कंट्रोल करने के लिये पैसे का ज्यादा प्रावधान नहीं किया जाएगा तो फिर वैसा ही फलड आ गया तो यह प्रदेश पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा। इस सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इकानोमिक रिफोर्मज की बात है। उन्होंने कहा है कि मूल्य वृद्धि पर काबू पा लिया है। इन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उनके मुताबिक इन्होंने मूल्य वृद्धि पर काबू पाया है इनके लिखे हुए के मुताबिक ही मैं आपको बताऊंगा कि अप्रैल 1993 में बजट का होलसेल मूल्य सूचकांक 232 था और वह फरवरी 1995 में 285 हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि दो साल के अर्से में 25 परसैंट की मूल्य वृद्धि हुई है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से ये हमारी यह तसल्ली करवाना चाहते है कि इनकी 100 परसैंट मूल्य वृद्धि बढ़ाने की योजना होगी। कहते हैं कि मूल्यवृद्धि पर काबू पाया है, परन्तु मूल्य वृद्धि तो बढ़ती जा रही है। इस 25 परसैंट मूल्य वृद्धि से आप देख सकते हैं कि मूल्य वृद्धि हो रही है या नहीं। इनका जो इकानोमिक रिफार्मज है, उससे विदेशी कम्पनियों को व वित्तीय संस्थाओं को फायदा हो रहा है। इससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं है। इस नीति से विदेशी कम्पनियों को, वित्तीय संस्थाओं को यह सुविधा होगी कि वह यहां के पैसे को विदेशी बैंकों में जमा करवा सकेंगे। मेरा कहना यह है कि इनकी इकानोमिक रिफार्मज से आम आदमी को लाभ नहीं हो पाया है। चोरी का जो पैसा ये इधर उधर ले जा रहे थे, उसका कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र के चुनाव के परिणामों से पता चलता है। जो हश्र उन राज्यों की सरकारों को भुगतना पड़ा है, उसी प्रकार की अपनी कब्र ये यहां पर खोद रहे हैं। याहिया खां की तरह दफन होना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इनकी सरकार में मंत्री रह चुके श्री अर्जुन सिंह ने पीछे भोपाल में एक जन सभा में बताया है कि 70 हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है।

श्री अध्यक्ष : बीच में अर्जुन सिंह का रैफेंस कहां से आ गया ?

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : उसके बारे में तो ये अब कहेंगे कि वह हमारी पार्टी में नहीं हैं । (विघ्न) स्पीकर साहब श्री सैफूला जो कैबिनेट सैक्रेटरी और यहां हरियाणा के अन्दर भी हरियाणा के गवर्नर के एडवाईजर रह चुके हैं, ने कहा है कि चीनी के मामले में 20 हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है । ये उसी का अनुसरण करते जा रहे हैं और यहां पर इनका भी वही हश्र होगा जैसे अभी हाल ही में चुनाव होने वाले प्रदेशों की सरकारों का हुआ है । इनकी इकानामिक रिफार्मज की पालिसी के कारण शेयरों में भी 20 हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है । यह मौजूदा सरकार अपनी स्टेट की सम्पत्ति के शेयर मिट्टी के भाव पर बेच रही है । यह सरकार पानीपत थर्मल प्लांट को 300 करोड़ रुपये में बेचने के लिए एक विदेशी कम्पनी से सौदा कर रही है और फिर उसी कम्पनी से दुबारा लीज पर लेने की सोच रही है । इस बारे में कुछ बातें हवा में ही रही हैं, बिजली मंत्री महोदय, इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर देंगे ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जो बातें ये कह रहे हैं, इन बातों का इस मौजूदा बजट से कोई संबंध नहीं है । (विघ्न) मैं पढ़ना जानता हूं या नहीं लेकिन आपको और आपके पिता को पढ़ाना अच्छी तरह जानता हूं ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपनी बात कह रहा हूं, ये बीच में न बोलें, बाद में मेरी बातों का जवाब दे दें । इन्होंने कहा है कि प्रदेश की इकोनोमी में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका सारा श्रेय किसानों को जाता है, जिन्होंने प्रकृति की कृपा से और अपनी मेहनत से उपज को बढ़ाया । सरकार की तरफ से न तो समय पर खाद सप्लाई हुआ और न ही बिजली और पानी किसानों को मिला । इसलिए इस वृद्धि में सरकार का कोई सहयोग नहीं है । वर्ष 1993-94 में संशोधित अनुमानों में टैक्सों से आमदनी 1,784 करोड़ रुपये रखी गई है जब कि असल में 1,684 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है । यहां पर गुमराह करने की बात की गई है । अनुमानित तो 1,784 और असल में 1,684 है । मार्च में साल खत्म होता है । इनके आंकड़ों में तथा संशोधित अनुमानों में 100 करोड़ रुपये का फर्क है जो कि माना जाना चाहिए कि जानबूझ कर खाता गलत बनाया गया है । इस प्रकार के मामलों पर इस तरह के नकली खाते बड़ी होशियारी से गुप्ता जी हर बजट में देते हैं । अध्यक्ष महोदय, दूसरी बार आमदनी में 115 करोड़ रुपये की कमी रही । जो अन्दाजा लगाया जाता है, वह अन्दाजा फेल हो जाता है और जो कटौती होती है वह किसान पर, शडयूल्ड कास्ट्स के लोगों पर, वीकर सैक्शन्ज और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों पर होती है । योजना खर्च का अनुमान बढ़ा-चढ़ा कर दिया जाता है जिससे आमदनी में कमी होती है और खर्च ज्यादा हो जाता है । ग्रामीण विकास में 12 करोड़ रुपये की कमी हुई । अध्यक्ष महोदय, ये कागज पर खर्च दिखा देते हैं, वास्तव

में कोई कार्य कहीं नहीं होता है । खर्च में जो कटौती होती है, वह ग्रामीण विकास में से हो जाती है । ये किसानों के विकास और भले की बात हांकते हैं, आखिर में जो कटौती होती है वह किसानों और गरीब लोगों पर पड़ती है । इस वर्ष की योजना से अगले वर्ष की योजना को बढ़ा कर दिखाया गया है, यह सब एक छलावा है। अध्यक्ष महोदय, 1994-95 में कैपिटल एक्सपैंडिचर 252 था जब कि 1995-96 में कैपिटल एक्सपैंडिचर का संशोधित अनुमान 262 करोड़ रुपये हुए । खर्च में 11% की बढ़ौतरी है लेकिन कीमतों में जो बढ़ौतरी हुई है, वह पिछले साल के मुकाबले 15% है । अध्यक्ष महोदय जो 4,349 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है, उसमें से 30 करोड़ रुपये की राशि मानेसर जापानी ग्राम विकास सुविधा के नाम पर दी गई है । अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश का, या हिन्दुस्तान का कोई भी नागरिक वहां पर जाने की नहीं सोच सकता, वह उनके स्वाधीनता और स्वावलम्बी के नारे पर चोट करता है । ये 30 करोड़ खर्च कर रहे हैं और हरियाणा प्रदेश या हिन्दुस्तान के लोगों को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, उल्टा उससे नुकसान ही होगा । सिंचाई के लिए 1,800 करोड़ रुपये का वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है, जिसमें से ज्यादातर स्टाफ की तनख्वाहों तथा अन्य खर्चों के लिए खर्च किया जाएगा । अध्यक्ष महोदय, चर्चा चलती है कि वर्ल्ड बैंक से पैसा आ रहा है, खर्च का प्रावधान कहां से रखा गया है, वह पैसा आएगा वर्ल्ड बैंक से । अध्यक्ष महोदय, कोई भी पैसा किसानों के विकास के नाम पर किसी मद में खर्च में दिखाने की चेष्टा नहीं की गई है । 65 करोड़ रुपये यमुना नदी के किनारे पर बसे शहरों की सफाई और बेहतरी पर खर्च होगा और वह पैसा बाहर के मुल्कों से आएगा । इस काम के लिए जापान से 65 करोड़ रुपया आना है । यदि इनकी स्कीमें इस तरीके से चलती रही तो प्रदेश का विकास कैसे होगा ?

अध्यक्ष महोदय, बिजली का मामला बड़ा अहम् मामला है । 170 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर लोगों पर लगाये गये हैं । इस अतिरिक्त कर के बोझ से लोगों को लाद दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, बिजली की उत्पादन लागत को कम करने की बजाय इसके रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं और बिजली बोर्ड का घाटा निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है जिसको पूरा करने के लिए जनता पर निरन्तर टैक्स लगाए जा रहे हैं । 110 करोड़ रुपये का रूरल इलैक्ट्रिकल सबसिडी का और 337 करोड़ रुपये महकमों का बकाया है । जैसा मैंने बताया है, इसके बावजूद पानीपत थर्मल प्लांट में 100 करोड़ रुपये की मशीनरी का प्रस्ताव किया है जबकि बोर्ड के पास पैसा ही नहीं है । जिन अधिकारियों ने इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में ऐसे घपले किये हैं, सरकार को उन्हें सजा देनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, आइजनबर्ग कम्पनी का जिक्र भी किया गया और मुख्य मंत्री जी ने कहा कि 1.92 रुपये प्रति यूनिट बिजली हमें उससे मिलेगी । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, 4.50 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से यह बिजली पड़ेगी । (विघ्न) (इस समय श्री उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए ।)

[चौधरी ओम प्रकाश चौटाला]

उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट के इन्ट्रैस्ट को ध्यान में रखते हुए अगर कोई अधिकारी इन्हें कोई बात कह देता तो उसको ये खुड्डे लाईन लगा देते हैं और अगर कोई बेइमानी करता है तो उसको इज्जत देते हैं । उसका परिणाम यह है कि आज कहीं पर भी बिजली नहीं मिलती है । उपाध्यक्ष महोदय, ये कलकत्ते की एक पीयरलैस कम्पनी से 300 करोड़ रुपए साढ़े 16 प्रतिशत के हिसाब से लेने की सोच रहे हैं । अगर कोई अफसर इस बात के लिए आपत्ति करे तो उसको खुड्डे लाईन लगा देते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार के ऐसे तो हालात हैं । उपाध्यक्ष महोदय, 1992-93 के मुकाबले में इन्स्टालड कपैसिटी तो बढ़ी है लेकिन बिजली का उत्पादन 40 करोड़ यूनिट कम हुआ है । यह तो आपकी मैनेजमैंट क्षमता है । अब इजराईल की कम्पनी के बारे में बताया गया था और बड़ी डींग मारी गई थी कि बड़ी ही अच्छी कम्पनी है। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो कम्पनी वर्ल्ड व्यापार में ब्लैक लिस्टिड है, उस कम्पनी के साथ इन्होंने समझौता किया है ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। इन्होंने कहा है कि यह ब्लैक लिस्टिड कम्पनी है । इनको बात सोच समझ कर कहनी चाहिए । फिर नहीं तो इसी मामले के बारे में एक कमेटी बनाकर इन्क्वायरी करवानी पड़ेगी । उपाध्यक्ष महोदय, ये जो गलत ब्यानी कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए । क्या यह सरकार ऐसा काम करेगी, क्या हमारी सरकार किसी ब्लैक लिस्टिड कम्पनी के साथ बात करेगी ? उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया की जो पांच बड़ी कम्पनियां हैं, यह कम्पनी उन में से एक है । (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : हम अपने अधिकारों से हाऊस में आए हैं, किसी के रहमोकर्म पर नहीं हैं । उपाध्यक्ष महोदय, कल इन्होंने बहुत डींग मारने की कोशिश की थी ।

चौधरी भजन लाल : यह तो आगे चलकर जनता बता देगी ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : आगे चल कर क्यों, तुम अभी आओ । मैं भी रिजाईन देता हूं और तुम भी रिजाईन दो और दोनों हल्कों में चुनाव करवा कर देख लो। हम तो सभी रिजाईन दे देते हैं, तुम अपनी बात करो । (शोर) तुम क्या बढ़चढ़ कर बात करते हो कि कमेटी बनाएंगे और यह करेंगे, वह करेंगे । जैसे किसी पर एहसान करते होंगे । उपाध्यक्ष महोदय, आप इन्हें कंट्रोल करें । (शोर एवं व्यवधान) अगर आप कुछ बोलते हैं तो सुनने की भी हिम्मत रखें ।

श्री उपाध्यक्ष : चौटाला जी, आप अपनी बात कीजिए ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इजराईल की कम्पनी के बारे में बात कर रहा हूं कि इस हाऊस को गुमराह किया जा रहा है । हमने इनसे

एम0 ओ0 यू0 बार-बार मांगा, प्रैस के लोगों ने मांगा और ये उसकी कापी भी नहीं दे पाए ? इसके बाद फिर प्रोमिजरी एग्रीमैंट हुआ और उसकी भी कापी ये नहीं दे पाए और अभी भी हाऊस को गुमराह किया जा रहा है कि यह बात ही लाभप्रद समझौता है । उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त आप भी बैठे हुए थे और मैंने इनसे पूछा था कि किस प्रकार से इसको लाभप्रद बनाने जा रहे हैं, जबकि बिजली के उत्पादन पर प्रति यूनिट साढ़े चार रुपए खर्च आएगा । मलेशिया की एक कम्पनी ने 2.4 करोड़ मैगावाट के हिसाब से दिया है । उपाध्यक्ष महोदय, मलेशिया में एक विदेशी फर्म ने इसी प्रकार का साढ़े सात सौ करोड़ का एक प्रोजैक्ट लगाया है जो कि 2.4 करोड़ मैगावाट के हिसाब से हुआ है । जबकि हमारी यहां पर एक बहल कम्पनी है, जिसने इनको तीन करोड़ से कम की आफर दी हुई है जोकि हमारे देश की अपनी ही कम्पनी है, जिसका रिकार्ड बहुत ही अच्छा है, जिसके इंजीनियर भी बहुत अच्छे हैं । अगर ये उसको कान्ट्रैक्ट दे देते तो देश का पैसा विदेश में न जाता बल्कि देश में ही रहता । इतना पैसा मुल्क में रहना था लेकिन उससे सौदा करने के बजाए इस प्रकार की कम्पनी से सौदा कर लिया गया है । उपाध्यक्ष महोदय, इसमें हजारों करोड़ों रुपयों का वपला किया गया और इसी वजह से बोर्ड का घाटा 1,800 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है । आज प्रदेश की सम्पत्ति को लूटा जा रहा है और इसी कारण आज इस प्रकार की साजिशें रची जा रही हैं । उपाध्यक्ष महोदय, पानीपत थर्मल पावर प्लांट के बारे में इन्होंने कहा कि सरकार ने अखबारों में टैंडर काल नहीं किए । मुख्य मंत्री जी ने स्वयं यह बात इंजीनियर्ज की मीटिंग में कही है । उपाध्यक्ष महोदय, जब टैंडर अखबारों में आए हैं तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हमने टैंडर नहीं काल किए हैं ?

बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : कहां टैंडर कॉल किए हैं, आप दिखाएं ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : बता देंगे आपको दिखा देंगे । (विघ्न) सर, अब ये कहते हैं कि वह कम्पनी बहुत अच्छी है, लगता है इस कम्पनी के साथ इनकी पुरानी पार्टनरशिप रही है लेकिन इनको ज्ञान नहीं है कि केन्द्र के उर्जा मंत्री से भी पूछा गया था कि आपका इस कम्पनी से क्या ताल्लुक है ? पता नहीं सरकार के पास वह पत्र है या नहीं, सरकार के पास वह पत्र आया है या नहीं आया है । केन्द्रीय उर्जा मंत्री का भी सुझाव है कि आप बिजली के मामले में इस कम्पनी से कोई सौदा न करें । उपाध्यक्ष महोदय, ये उस लैटर को दिखाएं । लेकिन ये तो हाउस को और हरियाणा को गुमराह कर रहे हैं । स्टेट का नुक्सान हो रहा है । हमें एम0 ओ0 यू0 की और प्रोमोसरी ऐग्रीमैंट की कॉपी नहीं दी गयी और न ही ग्लोबल टैंडर कॉल किए जाते हैं, यह कह देते हैं कि जब मौका आएगा, दे देंगे और हम यह मुनाफे का सौदा करने जा रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से कृषि के बारे में है । अगले वर्ष की योजना में इस वर्ष के मुकाबले में कृषि पर खर्चा 6.4 परसैन्ट अधिक दिखाया गया है हालांकि योजना की कुल बढ़ोत्तरी 21 परसैन्ट

[चौधरी ओम प्रकाश चौटाला]

हीं है । यह सरकार ऐग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं कर रही है । सरकार की जो मंशा है वह स्पष्ट दीख रही है । इसी प्रकार से इंडस्ट्रीज के बारे में इनकी पालसी है । इन्डस्ट्रीज में सबसिडी की ये बात कहते हैं कि हम सबसिडी देने जा रहे हैं । मैं उद्योग मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अभी सबसिडी के कितने क्लेम बकाया हैं और किन किन जिलों में सबसिडी दी गयी है ? सर, अपने आदमियों और अपने चहेते ऑफिसर्ज को ही यह सबसिडी दी गयी है । आप बतायें यह सबसिडी कहां पर दी है और कहां पर नहीं दी है लेकिन यह कभी भी हाउस में नहीं बताया जाता है, केवल गुप्ता जी ने आंकड़े दिखाने की कोशिश की है कि इतने रुपये हमने सबसिडी के लिए रखे हैं लेकिन सर, यह सबसिडी कहां जाती है इतना तो कम से कम हाउस के सामने आना चाहिए । इसी प्रकार से क्रेडिट और डिपोजिट के बारे में बात आती है । यदि सरकार सौ रुपये जमा करती है तो केवल इनको 51 रुपये का ही क्रेडिट मिलता है । आज हमारी यही केडेबिलिटी रह गई है कि अगर सरकार की तरफ से सौ रुपये बैंक में जमा होते हैं तो उसे केवल 51 रुपये ही मिलते हैं यानी हमारी स्टेट का प्रौफिट दूसरे स्टेट्स, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र उठा रहे हैं, इनके मुकाबले में कम है । (घंटी) सर, अभी तो मुझे बोलते हुए केवल दस मिनट भी नहीं हुए हैं । इसी तरह से परसों मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने एम० एल० एज० के लिए बीस लाख रुपये दे दिए हैं । उपाध्यक्ष महोदय, किस तरह से हाउस को गुमराह किया जा रहा है ? यह तो वह पैसा है जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड पर पहले खर्च होता था लेकिन यहां पर हमें बहकावा दिया जा रहा है कि हम एम० एल० एज० को पैसा दे रहे हैं । मैम्बर जब अपने क्षेत्र में जाएंगे तो लोग इनसे पूछेंगे कि यह पैसा खर्च क्यों नहीं किया जा रहा है तो एम० एल० एज० क्या जबाव देंगे, क्योंकि एम० एल० ए० के काम की लिस्ट के मुताबिक अधिकारी इस पैसे को खर्च नहीं कर रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में छलावा किया जा रहा है ।

इसी तरह से आज प्रदेश में ऐजुकेशन की हालत हो गई है क्योंकि 1994 का स्कूल में पास होने वाले लड़कों का प्रतिशत केवल पांच प्रतिशत ही रहा है जबकि सरकार ने कहा कि नकल रोकने पर हमने बहुत पाबंदी लगायी है । लेकिन जिस सुशीला कुमारी टीचर ने नकल रोकने की कोशिश की थी, उसका क्या हश्र हुआ है, यह बात ये स्पष्ट नहीं कर पाए । उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के आदेश का पालन करते हुए अगर अध्यापक नकल रोकने की कोशिश करें तो उनको मार दिया जाता है। उनको मारने वाले लोग सरकारी संरक्षण प्राप्त किए हुए हैं लेकिन उनके खिलाफ सरकार कोई भी ऐक्शन नहीं ले रही है । इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, रणबीर सिंह सुहाग का मामला है, वह भी अध्यापक हैं और वह अच्छा काम कर रहा था लेकिन उसका भी वही हश्र हुआ है । सरकार के इन कामों का ही परिणाम है कि रिजल्ट केवल पांच प्रतिशत ही बना रहा ।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, ये सैनीटेशन की बात करते हैं। गुप्ता जी ने अपने भाषण में इसका जिक्र किया है। गांव में सैनीटेशन पर कोई भी पैसा खर्च नहीं किया गया है, क्या गुप्ता जी गांव की सफाई के लिए कोई प्रावधान करेंगे? उपाध्यक्ष महोदय, आज गांव सड़ रहे हैं लेकिन इन्होंने अपने बजट में कहीं भी यह दिखाने की कोशिश नहीं की कि हम रूरल एरियाज में कितना पैसा खर्च करने जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ये बड़ा दावा करते हैं हरिजनों के उत्थान का। कहते

12.00 बजे | हैं कि 80 लाख रुपया केवल हरिजन-बस्तियों पर खर्च करने की सरकार की योजना है। केवल मात्र 80 लाख रुपये में आज इस महंगाई के युग में, किसी गांव की गलियों का पक्का हो पाना भी मुश्किल है, कहां यह हरिजनों की बस्तियों का उत्थान करने जा रहे हैं? उनको लड़ाने की बात जरूर करते हैं, विकास के कामों में रुचि नहीं है, इसमें भी छलावा दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों के उत्थान की बात को लेकर इन्होंने 1994-95 में 68 हजार परिवारों को सहायता देने का लक्ष्य रखा था। लेकिन दिसम्बर तक केवल 20,173 परिवारों को लाभ पहुंचाया है। कहां 68 हजार परिवार कहां 20 हजार परिवार। इसी प्रकार से इंदिरा आवास योजना के तहत 1,707 मकान हरिजनों के लिए बनवाये थे लेकिन केवल 868 मकान ही बना पाए हैं जो 50 प्रतिशत है। यह हरिजनों के उद्धार की बात करने वाले हैं। जब उनके विकास करने का प्रश्न आता है तो उनके साथ यह सलूक किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक अप्रैल से लाटरी बंद करने की बात कही है, अब पता नहीं यह बन्द कर रहे हैं या अप्रैल फूल बना रहे हैं। खैर हम मान लेते हैं कि बंद कर रहे हैं तो दूसरे प्रदेशों की लाटरी ये क्यों अलाऊ कर रहे हैं? इससे साफ जाहिर है कि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। अपने मंजूरेनजर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है लेकिन जो लोग लाटरी से बर्बाद हो रहे हैं, जिन्होंने स्युसाइड कर लिया उनका तो विनाश हो गया। क्राइम बढ़ रहे हैं, जिन लोगों ने लॉटरी लेनी है, वे तो लेंगे ही, सरकार को भी इससे लाभ नहीं होने वाला है इसलिए इसे बन्द कर देना चाहिए।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्टेट की लॉटरी एक अप्रैल से बन्द कर दी है, बाहर की जो लॉटरी है, इसके लिए भारत सरकार का ऐक्ट है इसलिए हम किसी बाहर की लाटरी पर बैन नहीं लगा सकते, केवल स्टेट गवर्नमैंट टैक्स लगा सकती है ताकि बाहर की लाटरी यहां आकर न बिकें। टैक्स का रेट और बढ़ा सकते हैं। स्टेट गवर्नमैंट बैन नहीं लगा सकती, इस बात का ज्ञान इनको होना चाहिए।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : बजट में रोड ट्रांसपोर्ट की बात की गई है। ऐक्सप्रेस बस सर्विस के किराए 25 प्रतिशत बढ़ा दिए, इससे सरकार को नुकसान हो रहा है। बसें सड़क पर खाली जा रही हैं, जनता को किसी कीमत पर भी सस्ती

[चौधरी ओम प्रकाश चौटाला]

सवारी उपलब्ध नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडू की जो सेमी डीलक्स बसें हैं, उनका किराया 17 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से है और हमारे यहां का 37 पैसे पर किलो मीटर के हिसाब से है । लोगों को सवारी उपलब्ध नहीं है और ये भागते जा रहे हैं । इस प्रकार सरकार के खजाने में भी पैसा नहीं आ सकता ।

इकोनोमिक सर्वे के पृष्ठ 21 पर आप पढ़ लें । वर्ष 1990 में 497 डिग्री होल्डर इंजीनियर्ज हरियाणा प्रदेश में अनइम्प्लोयड थे । आज से 8 महीने पहले 30-6-94 को डिप्लोमा होल्डर्ज की संख्या 1123 थी और अब 4425 तक चली गई और दूसरी अन-स्किल्ड लेबर है इस बारे में आप अन्दाजा लगाईये कि आई0 टी0 आई0 ट्रेन्ड की संख्या पहले 260102 थी जो अब 28545 और बढ़ गई है । इस प्रकार से अन-इम्पलायडज की संख्या बढ़ रही है ।

मांगे राम जी आपकी किताब के दिये हुए आंकड़ों को ही मैं दर्शा रहा हूं । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं । अभी यहां पर सड़कों का भी जिकर आया । इनके अपने किताब के आंकड़े हैं, वही मैं बता रहा हूं । हो सकता है गुप्ता जी ने ध्यान से ये आंकड़े पढ़े न हों । सड़कें बनाने की बजाये 181 किलोमीटर समथिंग सड़कों को डिसमैंटल किया गया है । यह इनकी इकानामिक सर्वे रिपोर्ट पेज 17 कहती है । जितनी सड़कों का जिकर किया गया है, उनकी मुरम्मत नहीं हुई है और नई कोई सड़क बनी भी नहीं है । इससे साफ जाहिर है कि सरकार का ध्यान सड़कें बनाने में कम रहा और डिसमैंटल करने में ज्यादा रहा । डिसमैंटल करने में सरकार ने अपनी दिलचस्पी खूब दिखाई है । (घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मेरा पूरा समय हुआ ही नहीं है । अभी मैं अपने आगामी दो चार प्वायंटस पर आ रहा हूं और जल्दी ही समाप्त करूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत ही उदार दिल हैं । मैंने तो आपको कई बार अध्यक्ष कहकर भी सम्बोधित किया है । आपकी तरक्की की योजना बना रहा था । (हंसी) इतनी सराहना के बावजूद थोड़ा बहुत रहम का खाना आपके पास होना चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही अपनी बात को कहकर समाप्त करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिजली के बारे में भी जिकर करना चाहूंगा । चौधरी बीरेन्द्र सिंह यहां पर बैठे हैं, जरा ध्यान देवें कि इन्होंने 1 रुपये 92 पैसे पर यूनिट बिजली का रेट बतलाया, बिलिंग चार्जिज का रेट बतलाया 1 रुपया 30 पैसे पर यूनिट, ट्रांसमिशन का एक रुपया पर यूनिट, अनफोरसीन का 25 पैसे पर यूनिट । मैं इनको बताना चाहता हूं कि ट्रांसफारमंज और कोयले के रेट्स के साथ बिजली का रेट्स भी बढ़ेगा ही । इस प्रकार यह 4 रुपये 47 पैसे पर यूनिट खर्चा बैठता है । यह सब इनके अपने बताए हुए आंकड़ों के अनुसार फिगर्ज बैठती है ।

इसी प्रकार चुनावों की भी बड़ी ढींग मार रहे थे मुख्य मन्त्री महोदय कि बड़े ही फैयर चुनाव करवाए गये । इसी प्रकार लोकल बाडीज और पंचायतों का जिकर भी यहां पर आया और इन्होंने कहा कि चुनाव फैयर और अच्छे हुए हैं लोगों ने इन चुनावों की बड़ी प्रशंसा की है । भजन लाल जी ने अपने आईडैन्टी, कार्ड का भी जिक्र किया । (घण्टी) उपाध्यक्ष महोदय, आप बार बार घन्टी बजा रहे हैं । मैं बस जल्दी ही अपने एक दो प्वायंट कहकर समाप्त करूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता होगा, आप स्वयं भी चुनावों से जुड़े रहे हैं । जिस प्रकार से वोटें बनीं, वार्ड बने, वार्ड काटे, ऐसा करके सरकार ने लोगों के साथ कितना भद्दा मजाक किया है । पंचायत समितियों की तो सीकरेट् वोटिंग करवाई और जिला परिषद के चुनावों में हाथ ऊपर करके शो-अप तरीके से वोटिंग करवाई । इसी तरह से मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा कि हमें म्युनिसिपल कमेटियों के चुनावों में 85 परसैन्ट वोट मिले, हैं । 25 म्युनिसिपल कमेटियां ऐसी हैं जिनमें एस0जे0पी0के पदाधिकारी चेयरमैन हैं पांच में बी0 जे0 पी0 के हैं और 9 में निर्दलीय हैं । इनके केवल 19 हैं और वे भी जोड़ तोड़ के हिसाब से हैं, कांग्रेसी वे लोग भी नहीं हैं । (शोर) यूंही इस तरह की बातें कहकर हाउस को गुमराह कर रहे हैं । आखिर इस हाउस में कोई बात तो साफ होनी चाहिए । (शोर) इस तरह से आगे मैं बताना चाहता हूं कि एक पुराना ब्लाक ऐसा है जहां पर पंचायत समिति के चुनाव नहीं हुए हैं । इसी तरह से अम्बाला के चुनाव भी नहीं हो पाए हैं । यहां पर एक परम्परा बनती जा रही है कि इस हाउस में गल्त ब्यानी की जाए । यह प्रथा केवल ट्रेजरी बैंचिज तक ही नहीं है बल्कि दूसरे बैंचिज तक भी चली गई है । जैसे साहबी नदी के बांध का जिक्र आया था, तो चौधरी बंसी लाल ने कहा था कि 40 करोड़ रुपये बेकार में खर्च हो गए थे । उपाध्यक्ष महोदय, उस समय जितना फ्लड से नुक्सान हुआ था, उसके दृष्टिगत यह पैसा रखा गया था । बाद में राजस्थान ने बांध बांध कर इधर पानी नहीं आने दिया । ये इस बात को भूल गए कि जब ये एस0 वाई0 एल0 नहर को बनाने लगे थे तो पहले इनको नहर पंजाब में बनाने की कोशिश करनी चाहिए इन्होंने उस नहर को हरियाणा प्रदेश में पहले बना कर सैंकड़ों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए । उपाध्यक्ष महोदय, जब हरियाणा में फ्लड आता है तो प्रदेश बर्बाद हो जाता है । इसके अलावा, जब राजबीर नाम के व्यक्ति के बारे में बात आई तो ये उससे मुकर गए । कम से कम बंसी लाल जी आपने जो बात कही थी उस पर तो आपको कायम रहना चाहिए । अगर राजनैतिक लोग अपनी विश्वसनियता खत्म कर लेंगे तो कल को प्रैस वाले कहेंगे कि लिख कर दो । फिर बंसी लाल जी कहते हैं कि एमरजैंसी ठीक थी, बहिन भाई को नंगा करना ठीक था तो फिर राज वीर वाली बात को क्यों नहीं मानते ? मैं चाहूंगा कि हाउस की कुछ परम्पराएं रहनी चाहिएं । अगर गलती हो गई हो तो उसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए ।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

श्री बंसी लाल द्वारा

श्री बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पसर्नल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। यह बात बिल्कुल गलत है कि मैंने उसको अपनी पार्टी में एडमिट किया है। वह मेरे को कहने तो कुछ और आया था लेकिन वहां आ कर कहानी घड़ने लग गया। प्रैस वालों ने खुद लिखा है कि मैंने उसको धमकाया था। फिर इन्होंने बहिन भाई को नंगा करने का जिक्र किया तथा एमरजैंसी का जिक्र किया। मैं समझता हूं कि वह एमरजैंसी तो 19 महीने रही लेकिन इनके राज में तो पौने चार साल हरियाणा में एमरजैंसी रही। (हंसी) अभी मेहम के लोग इनको भूले नहीं हैं। आपको गलत फहमी हो गई है, आप मदीना का रास्ता छोड़ कर वाया लाखन माजरा मेहम पहुंचे थे। एक बात चौटाला साहब ने कही कि हरियाणा में बाढ़ आई थी इसलिये बांध बनाया गया था। अगर हरियाणा में बाढ़ आई थी तो ऐसी स्थिति नहीं आई थी कि मसानी बांध बनाना पड़े। वह तो दिल्ली को बचाने के लिए बनाया गया था और दिल्ली की सरकार के कहने से वह बनाया गया था। तो इनको वह रुपया दिल्ली की सरकार से वसूल करना चाहिए था। वह बांध बनने के बाद हरियाणा में राजस्थान से एक बूंद पानी भी नहीं आया।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, जब भी कोई काम शुरू किया जाता है तो हमेशा हैड से शुरू किया जाता है। लेकिन इन्होंने एस0 वाई0 एस0 को टेल से इसलिए बनाया था कि उसमें से कमिशन मिलेगा। इन्होंने पंजाब में हैड से इसलिए काम शुरू नहीं करवाया क्योंकि पंजाब में जो कंस्ट्रक्शन होती है, उसका काम वहीं स्टेट करती है। हरियाणा में इसलिये बनाया गया था कि यहां जो कंस्ट्रक्शन होती है उसको अपनी स्टेट के लोग करते हैं। जनाब को कमिशन मिलना था, जिस प्रकार पंजाब इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के रिजैक्ट हुए खम्बे लिए थे और उनमें इनको कमिशन मिला था, उसी प्रकार से कमिशन खाने के लिए इन्होंने उल्टी गंगा बहाई थी।

श्री बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का यह कहना कि मैंने कमिशन खाया था और पंजाब से रिजैक्टिड पोल खरीद लिए। यह सवाल नहीं है। मैं कमिशन नहीं खाता मैं तो दो रोटी खाता हूं। कमिशन खाने का काम चौटाला साहब का है, मेरा नहीं है, ऐसा काम ये करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह नहर हरियाणा प्रदेश के हिस्से में न बनती तो क्या हम पंजाब वालों से पानी मांग सकते थे ?

वर्ष 1995–96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

समाज कल्याण राज्य मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मसानी बैराज बनाने की बात है । यह बैराज बना कर चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने मेरे हल्के के 14 गांवों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीद कर किसानों को बर्बाद कर दिया वैसे तो यह लोग किसानों के हित की बात करते हैं परन्तु उस समय इन लोगों ने किसानों का अहित किया । उन गांवों के लोगों के साथ इन्होंने जितनी ज्यादती की है, उतनी और कोई नहीं कर सकता ।

श्री धीरपाल सिंह : चौधरी भजन लाल जी आप भी 1978 में मंत्री थे । उस समय ढांसा बांध बना कर बहादुरगढ़ और झज्जर तहसील के लोगों को तबाह कर दिया । दिल्ली वालों ने बाढ़ का एक बूंद पानी भी दिल्ली में नहीं जाने दिया। इसलिए मसानी बांध बनाना जरूरी था । आज आप कहां कहां से लोगों को ला कर इधर उधर की बात करवा रहे हैं । (विघ्न)

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला (बल्लभगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में हमारे सक्षम वित्त मंत्री श्री मांगे राम गुप्ता जी ने वर्ष 1995–96 का प्रगतिशील बजट पेश किया है इसलिये वे बधाई के पात्र हैं । यह बजट इस सरकार की सामाजिक एवं आर्थिक विकास के प्रति वचनबद्धता को दर्शाता है । उपाध्यक्ष महोदय, समस्त हरियाणा भली भांति जानता है कि वर्ष 1991 में हमारे आदरणीय चौधरी भजन लाल जी के नेतृत्व में हमारी इस लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ था । उस समय हमारी सरकार का यह नारा था और यह प्राथमिकता थी कि हम सारे प्रदेश के अन्दर सारे प्रदेश की जनता को साथ ले कर विकास के काम करना चाहते हैं और निष्ठा के साथ सारे प्रदेश में अमन और शांति के साथ प्रदेश के अन्दर चहुंमुखी विकास करेंगे । आज मैं फख्र के साथ हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी को यह बधाई देना चाहता हूं कि जिस समय से हमारी सरकार बनी है उस समय से हरियाणा प्रदेश चहुंमुखी विकास की तरफ निरन्तर गति के साथ बढ़ रहा है उसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है । उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि यह वर्ष हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 125वीं जयन्ती का मना रहे हैं । समस्त हरियाणा प्रदेश के अन्दर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद में अनेकों कार्यक्रम हरिजन से ले कर ऊपर की जाति तक के सभी समुदाय के लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छे कार्यक्रम निर्धारित किए हैं । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी समस्त दुनिया में महात्मा के नाम से जाने जाते हैं । हम सभी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर फख्र है । उन्होंने न केवल भारतवासियों के पिछड़े हुए लोगों के लिए आवाज उठाई बल्कि उन्होंने समस्त दुनिया के पिछड़े हुए लोगों के लिए आवाज उठाई । उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 125वीं जयन्ती मनाकर हरियाणा सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम शुरू किए हैं, इसके लिए हमारी हरियाणा सरकार बधाई की पात्र है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि

[श्री राजेन्द्र सिंह बिसला]

संविधान के अन्दर जो 73 वां व 74 वां संशोधन किया गया था, वह भी अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है । इस अमैंडमेंट के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, व इन्दिरा गांधी जी ने के सपने साकार हुए हैं। इस अमैंडमेंट के जरिए ऊपर के लैवल से लेकर नीचे ग्राम स्तर तक राजनैतिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण हुआ है । उन्हीं के सपनों को साकार करते हुए यह संशोधन किया गया था और उसी संशोधन को कार्यान्वित हरियाणा सरकार ने किया है। अभी हाल ही में जिला परिषद से लेकर ग्राम पंचायत के जो चुनाव हुए हैं और जो शक्ति का विकेन्द्रीकरण हुआ है, वह अपने आप में एक इतिहास है । इस सारे काम को अंजाम देने के लिए हरियाणा सरकार बधाई की पात्र है । पहले लोग सिर्फ विधायकों तथा एम0 पीज0 तक ही शक्ति का केन्द्रीकरण मानते थे लेकिन अब इन चुनावों से लोग फख्र के साथ कह सकते हैं कि शक्ति में उनका भी हिस्सा है । ये चुनाव चाहे जिला परिषद के थे, चाहे म्युनिस्पिल कमेटी के थे, या ब्लाक समिति के थे, या ग्राम पंचायतों के थे, इनसे सभी को अपनी अपनी शक्ति का पता चला है । इसलिये 73वां व 74वां संशोधन अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है । उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि इस काम में सारे देश के लिए एक अच्छी उदाहरण हरियाणा प्रदेश बना है और इसका नाम सबसे ऊपर आया है यह हमारे लिए बड़े फख्र की बात है । इस अधिनियम का दस्तावेज सबसे पहले लोक सभा में रखने का श्रेय हमारे मुख्य मन्त्री चौधरी भजन लाल जी को जाता है, ये केन्द्र में कृषि मंत्री थे तो उन्होंने यह दस्तावेज उस समय लोकसभा में पेश किया था, यह समस्त हरियाणा प्रदेश के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के कई नेताओं ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए और बजट पर बोलते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है । मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि सदियों से, वैदिक काल से इतिहास उठा कर देख लें कि कानून व्यवस्था में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाती है । लेकिन असल सवाल यह है कि जो मौजूदा सरकार है, वह कानून का उल्लंघन करने वाले के प्रति कैसा रवैया अख्तयार करती है आया उसको दण्डित करती है या नहीं ? मैं अपनी हरियाणा प्रदेश की सरकार को बधाई देता हूं कि हरियाणा में कानून व्यवस्था सारे देश से सबसे बढ़िया है । कानून व्यवस्था के बारे में हमारे विपक्ष के कई साथियों ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए गलत आरोप लगाए हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनके बारे में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भार सामान्यतः हमारे कर्तव्य-परायण अधिकारियों के कन्धों पर आता है । ये ब्यूरोक्रेटस जो आई0 ए0 एस0, आई0 पी0 एस0, एच0 सी0 एस0 बनते हैं यह केवल डिग्री ले कर ही नहीं बन जाते, बाकायदा उनको 24 घण्टों में से 18–18 घण्टे पढ़ना पड़ता है, तब कहीं जा कर वे इस योग्य हो पाते हैं कि इन पदों पर आए । हमारे कई साथी जो यूनिवर्सिटी

और कालेज में हमारे साथ पढ़ते रहे हैं उनमें से कुछ लीडर बने तो कुछ आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, आई० एफ० एस० और टैक्नोक्रेट आदि बने हैं । मैंने स्वयं अनुभव किया है कि इतने मेहनती और ईमानदार व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर ब्यूरोक्रेटस के रूप में आते हैं । (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है ।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही ये किस बात पर ये प्वायंट आफ आर्डर पर खड़े हो रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे निवेदन करूंगा कि ये मुझे बोलने दें और बीच में इस प्रकार से मुझे मेहरबानी करके इन्ट्रप्ट न करें । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, आप का क्या प्वायंट आफ आर्डर है ?

प्रो० सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद, मेरे काबिल दोस्त ने प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में कहा । इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए बहुत मेहनत और काबलीयत की जरूरत होती है और हरियाणा के अधिकारी मेहनती और काबिल हैं । (विघ्न) डिप्टी स्पीकर सर, हमारे काबिल 11 एच० सी० एस० अधिकारियों को आई० ए० एस० की लिस्ट में डाला गया था और उनकी सिलैक्शन की गई थी । मैं यह जानना चाहता हूं कि उनकी सिलैक्शन हुए साल होने जा रहा है लेकिन उनको अब तक पोस्टिंग क्यों नहीं दी जा रही है ? एक साल के बाद तो वह लिस्ट लैप्स हो जाएगी । उनको आई० ए० एस० की लिस्ट में पोस्टिंग क्यों नहीं दी जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है, आप बैठें ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । हमारे माननीय श्री बिसला साहब जी अभी प्रदेश में कानून और व्यवस्था की तारीफ कर रहे थे । ये पूरे राज्य के बारे में तो बात छोड़ दें, केवल फरीदाबाद जिले में ही इतने ज्यादा रैपस, हत्याएं और डकैतियां हो रहीं हैं कि जिसका कोई अन्त नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : दलाल साहब, यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है, आप बैठें ।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथी चौधरी कर्ण सिंह दलाल तथा प्रो० सम्पत सिंह जी ने एक तरीका बना रखा है कि जो बोले उसको इन्ट्रप्ट किया जाए, ये अनावश्यक रूप से मुझे टोक रहे हैं और मुझे अपनी बात नहीं कहने दे रहे हैं, इसलिये आप इन्हें रैस्ट्रेन करने की मेहरबानी करें । उपाध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैं निवेदन कर रहा था कि सजपा और विकास पार्टी के लोगों का तरीका रहा है कि ब्यूरोक्रेटस तथा प्रशासनिक अधिकारियों पर निराधार एलिगेशंज लगा

[श्री राजेन्द्र सिंह बिसला]

कर उनको डी-मोरेलाईज किया जाए । ये एलिगेशन्ज उनकी वर्किंग के कारण से नहीं लगाए जा रहे बल्कि ये अधिकारियों को गलत काम करने के आदेश देते थे और जो अधिकारी इनकी बात नहीं मानते थे, उन पर ये निराधार एलिगेशन्ज लगा रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा अभियान चलाया जाना चाहिए और भ्रष्ट अधिकारियों को किसी भी सूरत में बख्शना नहीं चाहिए लेकिन जो लोग ईमानदारी और काबलियत से इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, उनके बारे में कभी भी गलत शब्द नहीं कहे जाने चाहिए । (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, एक्जाम्पल के रूप में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेटस डी-मोरेलाईज हो जाते हैं, वहां पर हालात खराब होते हैं जिसकी वजह से आतंकवाद पनपता है । आज देश की एकता और अखण्डता के लिए आतंकवाद एक भारी खतरा बना हुआ है । अगर एडमिनिस्ट्रेशन डी-मोरेलाईज हो जाए तो कानून-व्यवस्था को बनाए रखना काफी मुश्किल होता है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौधरी बंसी लाल जी, कर्ण सिंह दलाल, चौधरी सम्पत सिंह जी से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की बातें करके प्रशासन को तथा ब्यूरोक्रेटस को डी-मोरेलाईज न करें । जिन अधिकारियों को ये पसन्द नहीं करते थे, उन अधिकारियों पर ये फाल्स ऐलिगेशन न लगाए क्योंकि वे अधिकारी यहां पर खुद को डिफैंड नहीं कर सकते हैं । हमारे जिला के एस० पी० श्री० के० के० मिश्रा हैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं कि जिला फरीदाबाद के एक तरफ दिल्ली, एक तरफ राजस्थान और एक तरफ यू० पी० है । वहां पर रातों रात क्रीमिनल आकर के घुसते हैं और वारदातें कर के चले जाते हैं । हमारे फरीदाबाद की जो सराऊंडिंग है, उसको देखते हुए आज सारे हरियाणा में फरीदाबाद में ला एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है । (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने एक एलिगेशन लगाया कि एस० पी० फरीदाबाद ने लक्ष्मण दास डी० जी० पी० साहब को उनके लड़के की शादी में कन्टैसा कार दी है । हमारे भी बच्चों की शादियां हुई हैं, बंसी लाल जी के बच्चों की भी शादियां हुई हैं, पता नहीं उनको कितनी ही कन्टैसा कारें मिल गई होंगी ? उपाध्यक्ष महोदय, ये हाऊस का मिसयूज करके गलत एलिगेशंज लगाते हैं । (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे एलिगेशन इनको नहीं लगाने चाहिए । (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, क्या आपने इनको बोलने की इजाजत दे दी है । (श्री कर्ण सिंह दलाल की तरफ से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कर्ण सिंह जी आप किस बात पर बोलना चाहते हैं ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर बोलना है । हमारे माननीय बिसला जी ने जो बात कही है कि * * * * * * * * * *

---

*चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, जो आदमी अपने आप को हाउस में डिफैण्ड नहीं कर सकता, आपको उसके बारे में कोई बात नहीं कहनी चाहिए । कर्ण सिंह जी ने जिस अफसर की बात कही है उस वर्शन को कार्यवाही से निकाल दें ।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : उपाध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद मेरा जिला है और बल्लभगढ़ मेरी कान्स्टीचुएंसी है, उसके बारे में मैं कोई बात फक्र से कह सकता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, अपोजिशन का तो एक सूत्रीय प्रोग्राम है कि सदन की कार्यवाही में बाधाएं डालें या किसी भी अफसर को कंडम करने का प्रोग्राम है । मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि जिस प्रदेश के अन्दर ब्यूरोक्रेसी में श्री एच0 डी0 बंसल जैसे चीफ सैक्रेटरी हों, वह प्रदेश तो तरक्की करेगा ही । वे एक ईमानदार और उच्च कोटि के अधिकारी हैं और उनकी ईमानदारी को सभी जानते हैं । मैं कहना चाहूंगा कि आज सारे देश में सबसे बढ़िया प्रशासन हरियाणा का है, सबसे अच्छी ला एण्ड आर्डर की स्थिति जो हमारे प्रदेश के अन्दर है, इसका श्रेय श्री चौधरी भजन लाल जी को ही जाता है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मांगेराम गुप्ता जी ने जिस अच्छी चीज को अपने बजट के अन्दर रखा है, वह है डाईवर्सीफिकेशन आफ ऐग्रीकल्चर ।

प्रो0 सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । जैसा कि ब्यूरोक्रेसी की बात आयी है, हम यह नहीं कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी अच्छी नहीं है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो 11 एच0 सी0 एस0 अफसर, आई0 ए0 एस0 के रूप में सिलैक्ट किए हैं, उनको एक साल होने के बाद भी कहीं पर पोसटिंग आर्डर क्यों नहीं दिए गए हैं ?

Mr. Deputy Speaker : This is not a point of order.

Prof. Sampat Singh : Sir, it is a valid point of order. If Government does not want to give reply तो यह गवर्नमैंट की मर्जी है । मैंने तो अपना प्वायंट रेज करना था, कर दिया है ।

सिंचाई मंत्री (चौ0 जगदीश नेहरा) : डिप्टी स्पीकर साहब, ये सदन का समय खराब कर रहे हैं । इन्होंने अपने दो बार प्वायंट उठाए हैं । अगर इसी तरह से सवाल किए जाएंगे तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या यह क्वैश्चन आवर है ?

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह हाउस चलाने का तरीका है । ये क्यों बार-बार इन्टरप्ट कर रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस गरिमामय सदन के जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, वे कई बार अपनी मर्यादा से बाहर चले जाते हैं । इस सदन की जो गरिमा है वह तो सभी सम्मानित सदस्यों की साझी है । ऐसा करके ये लोग प्रैस को और हरियाणा की जनता को कोई अच्छी इम्प्रैशन नहीं दे रहे हैं । हमें अपनी मर्यादा के अन्दर रहकर ही अपने

[श्री राजेन्द्र सिंह बिसला]

काम करने चाहिएं । (घण्टी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने समय के अन्दर ही अपनी बात खत्म कर लूंगा । सर, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं जैसा कि आप भी जानते हैं कि आज बड़ी भारी बेरोजगारी है और ज्यादा नौकरियां सरकार लोगों को नहीं दे सकती । हमारी सरकार ने आज इतने अच्छे प्रोग्राम, इतने अच्छे कार्यक्रम बनाए हैं जिन के लिए सरकार बधाई की पात्र है । सर्वप्रथम सरकार ने निर्णय लिया है कि डाईवर्सीफिकेशन आफ एग्रीकल्चर किया जाए । आप सभी जानते हैं कि आज थोड़ी थोड़ी जमीन पर दस या बारह लोग गुजारा करते हैं, लेकिन उनका गुजारा ठीक से नहीं होता । सरकार ने कृषि का डाईवर्सीफिकेशन करके एक बड़ा भारी निर्णय लिया है । आज इस निर्णय की बड़ी भारी चर्चा है और इसका बड़ा भारी श्रेय आज की सरकार को जाता है । अभी दिल्ली के अन्दर जो फूलों का मेला लगा हुआ है, उस मेले में मैं गया हुआ था, वहां पर साउथ से भी काफी लोग आए थे, उन्होंने भी सरकार के इस निर्णय की काफी सराहना की है । आज लोग महसूस करते हैं कि कृषि का डाईवर्सीफिकेशन होना चाहिए । सरकार इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए छोटे छोटे लोन, कम इंट्रस्ट पर लोगों को दे रही है जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है । उपाध्यक्ष महोदय, आज हम सभी मानते हैं और सदन के नेता ने भी कहा है कि बिजली की समस्या है और बिजली जितनी हरियाणा के लोगों को मिलनी चाहिए, उतनी बिजली हम आज नहीं दे पा रहे हैं । लेकिन मैं सम्पत सिंह से निवेदन करना चाहूंगा कि वे जो अपनी रैलियों में, अपने भाषण में लोगों से यह कहते हैं कि सरकार के जो मीटर रीडर चैक करने आते हैं, या जो बिजली की चोरी करने से रोकते हैं, उनको आप मारो । उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह अच्छी बात है ? बिजली की चोरी को रोकने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि बिजली के अन्दर पूरा सुधार हो । जिस तरह के हालात हैं, लोगों को ये गुमराह करते हैं, नारा देते हैं कि जो कर्मचारी बिजली की चोरी रोकते हैं उन अधिकारियों को मारो, मीटर चैक करने आते हैं तो उनका घेराव करो । यह तो अपोजीशन के पार्ट पर पुअर रिफलैक्शन है । मैं बिजली के बारे में ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आदरणीय मुख्य मन्त्री जी ने इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है । एक और बहुत अच्छी योजना जो हमारे आदरणीय मुख्यमन्त्री जी ने शुरू की है, वह है 'अपनी बेटी अपना धन' । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ-साथ महर्षि दयानन्द भी यही कहते थे कि हमारे समाज में सबसे ज्यादा उपेक्षित महिला वर्ग है । हमारे समाज में सबसे ज्यादा शोषण महिलाओं का हुआ है, इस शोषण को रोकने का श्रेय हमारी सरकार को जाता है । चौदहवीं तक लड़कियों की शिक्षा और टैक्नीकल एजूकेशन के लिए गरीब हरिजन और बैकवर्ड परिवार की जो बेटियां हैं, उनको स्पैशल वजीफे दिये जाते हैं । यह बहुत अच्छी योजना है । आदरणीय प्रधानमंत्री जी गर्व महसूस करते हैं और उन्होंने यह ऐलान किया है कि 'अपनी बेटी अपना धन' नामक योजना जो हरियाणा सरकार ने बनाई है, इस योजना को दूसरे प्रदेशों के अन्दर भी बनाना चाहिए। यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी सफलता है । शिक्षा के स्तर के बारे में भाई सम्पत

सिंह जी, ओम प्रकाश चौटाला और बंसी लाल जी ने बहुत नुक्ताचीनी की है। शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं और विशेषकर भाई मुलाना जी को बधाई देता हूं कि जिन्होंने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बहुत ठोस नीतियां बनाई और निर्णय लिये हैं । नकल को रोकने के लिए भिवानी शिक्षा बोर्ड ने बड़े अच्छे निर्णय लेकर मास स्केल पर जो नकल होती थी, उसको रोका है, गांव के लोग एग्जामिनेशन सैन्टर्ज पर लाठी लेकर पहुंचते थे । ला एण्ड आर्डर स्टेट में खराब लगता था । आज उस नकल को रोका है और बड़ा भारी सुधार करने में सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारी सफल हुए हैं ।

अभी यमुना जल समझौते के बारे में बड़ी भारी चर्चा इस सदन में हुई और हमारे विपक्ष के साथियों ने इस पर बड़ी नुक्ताचीनी की है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि यमुना जल समझौता अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है । मैं पिछली बार पी० ए० सी० का चेयरमैन था । भाई जिले सिंह और राम बिलास जी मेरे साथ थे । ताजेवाला हैडवर्क्स और हथनीकुण्ड बैराज पर निरीक्षण के लिए हमारी विधान सभा की कमेटी गई थी । ये जो अपोजीशन की बैन्च के सदस्य, थे, ये सभी इस विचार के थे कि ताजेवाला हैडवर्क्स का बाकायदा निर्माण होना चाहिए, हथनीकुण्ड का निर्माण होना चाहिये । मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने पांच स्टेटस के साथ इस ऐतिहासिक समझौते को करवाया है और वह भी तब, जब वहां हमारी पार्टी की सरकार न हो । ऐसा समझौता चौधरी भजन लाल ही करा सकते हैं । (घण्टी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि हथनी कुण्ड बैराज का निर्माण शीघ्र होगा । 100 वर्ष से पुराना ताजेवाला हैडवर्क्स है यह कभी भी प्राकृतिक प्रकोप का शिकार बन सकता है इसलिए सरकार इसके बारे में भी ध्यान दे । उपाध्यक्ष महोदय, आप बार बार घण्टी मार रहे हैं और इशारा कर रहे है । आपको पता है कि हम कांग्रेसी कितने अनुशासित होते हैं ? आपने मुझे बोलने का समय दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने कल जो बजट इस हाउस में प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं । मैं इस बात के लिये सरकार को बधाई देती हूं कि सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं रखा है । हमारी सरकार ने 1250 करोड़ का अनुमानित बजट रखा है जबकि 222.29 करोड़ रुपये की राशि केन्द्र की तरफ से है । सरकार ने आम आदमी के खाने की चीजों पर जैसे बाजरा है, ज्वार है, पर कोई टैक्स नहीं लगाया है, यह बहुत ही अच्छी बात है । दूसरा जो सूरजमुखी का तेल है, जिसको आम आदमी प्रयोग में लाता है, खासतौर पर बीमार आदमी इसका काफी प्रयोग करता है, दूसरी स्टेटों की तरह इस पर से सरकार ने सेल्ज टैक्स हटा दिया है । यह बड़ी ही प्रशंसनीय बात है लेकिन इसके साथ साथ मैं यह कहूंगी कि इस बजट के अन्दर खेती के लिये

[श्रीमती चन्द्रावती]

जो पैसा रखा गया है, वह पर्याप्त नहीं है, वह कुछ कम रखा गया है, पहले से ज्यादा रखना चाहिये था । इसकी निस्बत बिजली के लिये, इरीगेशन के लिये सरकार ने काफी पैसे का प्रावधान इस बजट में किया है लेकिन आज जो हमारे प्रान्त के अन्दर नहरें अटी पड़ी हैं, उनके लिये मैं समझती हूं कि सरकार को ज्यादा पैसा रखना चाहिये था । आज हमें पानी पंजाब की तरफ से क्यों नहीं आ रहा है, इसलिये एक तो नरवाना के पास और कुछ उधर पंजाब साईड से नहरें अटी पड़ी हैं जिस कारण से पानी नहीं आ रहा है, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये । हम सब को वालंटैरिली एक आर्गेनाईजेशन बनाकर इन नहरों की मिट्टी को हटाना चाहिये ताकि पानी आगे आ सके । नहरों की सफाई की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

मैं आपको बताती हूं कि एक मिट्ठी गांव है वहां पर एक टंकी बनी हुई है । इसी सिलसिले में मैंने एक सवाल भी दिया था कि 10 अक्तूबर को पानी गया, उसके बाद 30 जनवरी तक पानी वहां पर नहीं गया । लेकिन प्रोफैसर सम्पत सिंह जी ने जानबूझ कर यह सवाल आने ही नहीं दिया इसीलिये मैं उस वक्त बीच में बोल भी रही थी । जब सवाल पूछने की बात होती है तो दो तीन मिनट में ही पूछा जाता है लेकिन इन्होंने जब बोलना शुरू किया तो लैक्चर ही दे डाला, जिस के कारण उस वक्त मुझे बोलने का समय ही नहीं मिला । मैं यह बताना चाहती हूं कि वहां पर साढ़े तीन या चार सालों में केवल 11 बार पानी आया और ज्यादा से ज्यादा पांच दिन या आठ दिन ही पानी आया । इसी गांव के नीचे छः सात गांव आते हैं जिनमें पानी नहीं जाता जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है । इसलिये सरकार इस ओर ध्यान देवे । हमारे वहां पर बोरिंग वैलज हैं, उनके लिये सरकार ने अलग से कुछ नहीं किया है । कई जगहों पर मीठा पानी है और गहरा भी है । रिवाड़ी के अन्दर एक ऐक्सीअन है या एस० डी० ओ० है, वह तो कभी कुओं को देखने आता ही नहीं है, परिणामस्वरूप कुएं खराब हो जाते हैं । इस इलाके में बोरिंग वैलज ज्यादा हैं, अगर एक अफसर की अलग से ड्यूटी भिवानी में भी लग जाए तो बेहतर रहेगा । एक तो टेलीफोन न मिलने की वजह से अफसर भी नहीं मिलता । इसी तरह से झांजड़ा गांव है, वहां पर जो कुआं है, उसको वहां के कुछ बैकवर्ड क्लासिज के लोगों ने ईन्टों और पत्थर डाल कर बन्द कर रखा है, जिसके लिये कई बार सम्बन्धित अधिकारियों को कहा जा चुका है । मैंने कई बार उसको कहा है लेकिन मैं समझती हूं कि आज तक उसको ठीक से चालू नहीं किया गया है । हवा और पानी तथा बिजली बहुत जरूरी हैं । पता नहीं ये बोरिंग वैल एम० आई० टी० सी० के अंडर हैं या पीने के पानी में हैं लेकिन उसका अलग से नाम नहीं लिया गया । अगर उसका नाम ले लेते तो आपको हम इस बात के लिए डबल बधाई दे देते ।

इसी तरह से शिक्षा की बात है । सरकार ने जो साक्षरता अभियान चलाया है, यह बहुत अच्छा है । कहते हैं कि पूत कपूत सो का धन संचे, पूत सपूत खो का धन

संचे । अगर पूत सपूत हो गया तो कमा लेगा वरना खो देगा । तो शिक्षा की भी ऐसी ही बात है । इसी तरह से 'अपनी बेटी अपना धन' की भी अच्छी स्कीम है। इस बारे में बिसला जी ने कह दिया था इसलिये मैं कुछ नहीं कहूंगी । आपका आंगन-वाड़ी का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है लेकिन जो बच्चों के लिये न्यूट्रीशन की चीजें आती हैं, वे ऊपर ही बंट जाती हैं । मेरे पास मेरे हल्के का कोई आदमी आया, मैं उसका नाम नहीं लूंगी । वह कहने लगा कि हमारा झगड़ा हो गया और मेरी खूब पिटाई की गई है । मेरे घर वालों ने उससे पूछा कि क्या बात हो गई । पता चला कि यह झगड़ा इस सामान को बांटने की वजह से हुआ । तो जो सी० डी० पी० ओज० हैं, वे इसको वहीं खत्म कर देते हैं । मैं चाहती हूं कि वह कम से कम बच्चों तक तो जाना चाहिये । यह बहुत अच्छी स्कीम है । इसके तहत मां और बच्चे के लिए न्यूट्रीशन का प्रावधान है लेकिन वह वहीं खत्म हो जाता है । जो बात अभी मैंने आपको बताई है, वह हिसार का वाक्या है । इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे जो प्रोग्राम अच्छे हैं, अगर वे लोगों तक पहुंचते हैं तो लोग खुश होंगे । अगर लोगों तक नहीं पहुंचते तो चाहे जितनी भी अच्छी स्कीम क्यों न बने, उससे लोगों को कोई फायदा नहीं होगा । पंचायतों के बारे में मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि उनको स्कूलों का अधिकार देंगे । लेकिन क्या आपने पंचायतों के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया है ? मैंने तो इस बात को कहीं देखा नहीं । मैं चाहती हूं कि आगे जो आप सप्लीमैंटरी डिमांडज लाएं, उनके द्वारा पंचायतों के लिए अलग से बजट मांगा जाए । आपने उनको जो अधिकार दिए हैं, वे तभी मिलेंगे जब आप उनको पैसा देंगे । इसके अलावा, आज कल जो बड़े गांव हैं, उनकी बुरी हालत है । जो गांव के लोग शहरों में बसते हैं, वे चाहे झज्जर है या रोहतक है, वहां सैनेटरी का इन्तजाम नहीं है । इसके लिए मैंने कई बार सुजैशन दिया है । जब तक आप गन्दे पानी को ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक बीमारियां होती रहेंगी । मैं तो लोगों को हमेशा सलाह देती हूं कि आपस में मिल कर इस काम को कर लें जैसे आपने बिजली के लिए सैल्फ फाइनैंसिंग की स्कीम चलाई है, उसी तरह से सैनीटेशन के लिए भी कर दें ताकि बीमारियां खत्म हो जाएं । हमारे हल्के में एक नम्बरदार रूप चन्द है जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं । उनके दो जवान लड़कों को लकवा लग गया । तो इस तरीके से ये बीमारियां फैल रही हैं । हम यहां पर पैस्टीसाइड के बारे में कहते हैं कि यह एक अच्छी चीज है लेकिन यह अच्छी नहीं है । इसका जो छिड़काव होता है उसको परिन्दे खाते हैं । इसका छिड़काव सब से ज्यादा कपास के ऊपर होता है । जब कपास पर छिड़काव होगा तो बिनौला दूर कैसे जाएगा, बिनौले पर भी कीटनाशक दवाई का असर आता है । उसको भैंस खाती है, वह भी बीमार हो सकती है । हम भैंसों का घी दूध खाते हैं, हम भी बीमार हो सकते हैं । मैंने कभी दूसरा घी खाया नहीं मैंने तो भैंस का ही घी खाया है। डिप्टी स्पीकर साहब, श्री रामपत बिसलवास गांव के रहने वाले हैं और वे मेरे रिश्ते में चाचा लगते हैं । वे कहते हैं कि उन्होंने अपनी फसल में कभी भी कारखाने में बनी हुई खाद नहीं डाली और कभी भी आज तक कपास में किसी कीटनाशक दवाई के छिड़काव की जरूरत नहीं पड़ी । उपाध्यक्ष महोदय, विदेशों

[श्रीमती चन्द्रावती]

से जो बीज मंगवाया जाता है, उसके साथ कई किस्म के घास का बीज भी आ जाता है। जो पी0एच0 48 बीज के साथ घास का बीज आया था, जिसको लोग कांग्रेसी घास कहते हैं, उस घास के बीज के आने से हमारे यहां पर वह घास बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा होने लग गया है। मैं यह कहना चाहती हूं कि विदेशों से जो बीज मंगवाया जाए उसके साथ किसी किस्म के घास के बीज नहीं आने चाहिएं। आपने रूरल डिवैल्पमैंट के लिए अलग से पैसे का प्रावधान किया है, इसकी मुझे खुशी है। जैसे आपने मेवात के विकास के लिए मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड बनाया, उसका जो लाभ लोगों को पहुंचना चाहिए वह सभी लोगों को पहुंच नहीं पा रहा है। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि लोहारू से ज्यादा बैकवर्ड एरिया और कोई नहीं है। लोहारू सबसे ज्यादा बैकवर्ड एरिया है। झज्जर का सालाहावास भी बैकवर्ड एरिया है। बाढ़ड़ा का सतनाली बैकवर्ड एरिया है। उन एरियाज की डिवैल्पमैंट के लिये आप चाहे डिवैल्पमैंट बोर्ड न बनाएं, बोर्ड बनाने पर एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा ज्यादा होगा लेकिन उन इलाकों की डिवैल्पमैंट के लिए अलग से पैसे का प्रावधान किया जाना चाहिए, यह जरूरी है। सरकार ने यह बहुत अच्छी बात की है कि एक एम0एल0 ए0 अपने हल्के में 20 लाख रुपए विकास के काम पर खर्च करवा सकेगा और एक एम0 पी0 एक करोड़ खर्च करवा सकेगा। यह बहुत अच्छी बात है। आपने एक एम0एल0ए0 को 20 लाख रुपए खर्च करवाने की जो बात की है, उसके लिए मैं वित्त मन्त्री को बधाई देती हूं क्योंकि कुछ काम एम0एल0ए0 की मर्जी से उनके हल्कों में हो जाएंगे। यह काम सबसे पहले गुजरात स्टेट ने किया था।

अब मैं सड़कों के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। हमारे यहां सड़कें अच्छी हैं लेकिन फिर भी कुछ सड़कें टूटी हुई हैं। उन सड़कों में बिचुमैन की हेराफेरी हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में अच्छी सड़कें बनाई गई हैं, और भी बन रही हैं। इसके अलावा, मैं एक बात यह भी कहना चाहती हूं कि बसें इन्टीरियर के गांवों तक नहीं जाती। बसें इन्टीरियर के गांवों तक जानी चाहिएं। एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जो हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कारपोरेशन बनाई है, उसका काम सैटिसफैक्टरी नहीं है। ए0जी0 ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उस कारपोरेशन में अनस्किल्ड लोग ज्यादा भर्ती कर लिए गए हैं। अगर उस कारपोरेशन में ज्यादा भर्ती करने की जरूरत है तो जो स्किल्ड लोग मारे मारे फिर रहे हैं, जे0 ई0 वगैरह उनको भर्ती किया जा सकता है। जो लोग इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट से ट्रेनिंग ले कर आते हैं, उनको भर्ती किया जा सकता है मेरे हल्के लोहारू में एक इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग स्कूल है, उसमें अभी तक पूरा स्टाफ नहीं है और न ही उसके लिए कोई बिल्डिंग बनाई गई है। मैं मुख्य मंत्री जी से इस बात का जरूर आश्वासन चाहूंगी कि वे कम से कम वहां पर उस स्कूल की बिल्डिंग जरूर बनवा दें। यह हमारा बैकवर्ड एरिया है। वहां पर जो प्रिंसीपल साहब गए, उन्होंने यह लिख दिया कि वहां पर इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग स्कूल की जरूरत ही नहीं है। एक वहां पर कई डाक्टर आए,

उन्होंने कह दिया कि वहां पर प्राइमरी हैल्थ सैन्टर की जरूरत नहीं है। यदि वे लोग इस तरह से लिखते हैं तो सरकार उनकी इस तरह की बातों को क्यों मानती है। सरकार को उनकी बातों को डी ग्रेड कर देना चाहिए। वह इस तरह की बात इसलिये लिखते हैं क्योंकि वे लोग बैकवर्ड एरिया में जाना नहीं चाहते, इसीलिये तो हमारे ऊपर अंग्रेज राज कर गए। वे सबसे ज्यादा साउथ को अच्छा मानते थे। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि गांवों के पढ़े लिखे लड़के भी वहां पर जाना नहीं चाहते। उनको सरकार को कोई इनसैंटिव देना 13.00 बजे चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने काफी बच्चों को सर्विस दी है, मैं चाहती हूं कि काफी लोग बेरोजगार हैं इसलिए और अधिक सर्विस का प्रावधान करना चाहिए।

एक बात मैं कोआप्रेशन डिपार्टमैंट के बारे में कहना चाहती हूं। इस बारे में मेरा कहना है कि जो कोआप्रेटिव सोसायटीज हैं, उनमें किसानों के भी शेयर होते हैं। मैं चाहती हूं कि उनको भी उस शेयर का डिवीडेंड मिलना चाहिए। दूसरे मैं साथ ही साथ यह भी चाहती हूं कि कहीं पर नैचुरल कलैमिटी यानि ओले आदि पड़ने की स्थिति आती है तो किसानों को तुरन्त सहायता दी जानी चाहिए।

अब मैं पशुधन के बारे में भी कहना चाहती हूं। लोग जर्सी गाय वगैरा तो लाते हैं लेकिन मैं चाहती हूं कि अपने यहां की गाय और भैंसों की नस्ल को सुधारा जाये ताकि अधिक से अधिक दूध भी हो सके। अब पीछे कुरुक्षेत्र में किसी ने आर्टि-फिशियल दूध तैयार किया था लेकिन बाद में वह व्यक्ति पकड़ा गया। मैं चाहती हूं कि जिस गति से आबादी बढ़ रही है उस गति से दूध की पैदावार भी बढ़ायी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार राजधानी क्षेत्र के तहत कुण्डली में एक फलों की मण्डी बनाने जा रही है, इस बारे में मेरा कहना है कि सरकार को जब कोई ऐसा काम लार्ज स्केल पर करना हो तो उपजाऊ जमीन नहीं लेनी चाहिए। जो बंजर जमीन है, उसको यूज करना चाहिये। अगर उपजाऊ जमीन ले ली गई तो कल को जिनकी जमीन ली गई है, उनके घर बर्बाद हो जायेंगे। पैसे के चक्कर में पड़ कर जो उन्हें मिलता है, एक साल तक तो वे गुलछर्रे उड़ाते रहते हैं, कभी मारूती कार ले लेते हैं या अपने छोरे छोरी की शादी में खर्च कर देते हैं लेकिन बाद में उनको बहुत दिक्कत आती है। इस बारे में मैं किसानों को कहती हूं कि तुम अपनी जमीन मत बेचो, नहीं तो कल को तुम्हारी छोरियां इन कोठियों में झाड़ू लगाएंगी। इस बारे में मेरा कहना यह है कि यदि सरकार उनकी जमीन लेती है तो कम से कम उनकी जमीन लेने के बदले में नौकरी अवश्य दे ताकि उनका गुजारा हो सके। मैं यह भी चाहती हूं कि जो कारखाने बनाये जाते हैं, वे जी.टी. रोड पर न बनाकर दूसरी जगह पर बनाएं और उनको जी.टी. रोड से वहां तक सड़क दे दी ताकि कोई दुर्घटना भी न हो। फ्रांस में ऐसी स्थिति हो गई कि जी.टी. रोड बन्द होने

[श्रीमती चन्द्रावती]

पर फौज की गाड़ियां भी नहीं जा पाईं। यहां पर भी ऐसी हालत न हो जाये इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जी. टी. रोड पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और कहीं पर भी पूरे हरियाणा में जी.टी. रोड पर पशुओं का कोई क्रासिंग नहीं है। जी टी. रोड पर कैटल एप्रोच पूरे हरियाणा में कहीं पर भी नहीं है। करनाल हिसार बाई पास को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होता है। यह बहुत जरूरी चीज है इसलिये सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सड़क के पास अगर किसी की कोई दुकान या मकान हो तो उसका मुंह भी जी.टी. रोड की तरफ नहीं करने देना चाहिए। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदय, वाटर सप्लाई के लिए जौहड़ बहुत जरूरी हैं। जब तक इन जौहड़ों में बरसात का पानी इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक पशुओं को पीने का पानी नहीं मिलेगा और पशुओं के लिये पीने के पानी की समस्या बनी रहेगी। मेरे हल्के के कुछ गांवों में पानी बिल्कुल नहीं है। मिट्ठी गांव है, मलिक सालंग साल्हेवास और न जाने कितने ही गांव ऐसे हैं जिनमें पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या रहती है। इस बारे में मैंने पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट को चिट्ठियां भी लिखी हैं। उन चिट्ठियों का जवाब भी मेरे पास आया है जिसमें उन्होंने माना है कि मिट्ठी गांव में 4 दिन तक पानी नहीं आया। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी प्रार्थना है कि चाहे किसी भी तरह से हो, पीने का पानी जरूर पहुंचना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपका धन्यवाद करती हूं तथा अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब श्री ओम प्रकाश बेरी बोलेंगे। बेरी साहब आपको एक बात मैं पहले ही क्लीयर कर दूं कि आपका नाम चौधरी बंसी लाल जी ने रिकमेंड करके भेजा है, क्या आप उनकी पार्टी की तरफ से बोलेंगे। (विघ्न)

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : उपाध्यक्ष महोदय, चाहे उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया है लेकिन मैं एक बात पहले ही बता देना चाहता हूं कि मुझे कम से कम एक घंटे का समय मिलना चाहिए। मैं उनकी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा।

श्री उपाध्यक्ष : आपको अपने हिसाब से आधे घंटे का समय दिया जा सकता है इसलिये आप अपने समय का ध्यान रखें और ज्यादा समय न लें।

श्री बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इनको भी आपोजीशन से ही समझ लें हमारी पार्टी के बाकी सदस्य 5—5 या 7-7 मिनट बोल लेंगे अगर ये कुछ ज्यादा बोलें तो इनका टाईम हमारे टाईम में से काट लें। इनको हमारी पार्टी में ही मान लें।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : वे तो इस बात से इन्कार कर रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश बेरी (बेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने कल वर्ष 1995–96 के लिये जो बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और उस पर सदन में परिचर्चा चल रही है, मैं भी इस पर अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उन्होंने विभिन्न विभागों के लिये योजना खर्च दर्शाया है, मैं उनके बारे में अपने विचार रखना चाहूंगा और उनका थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। बिजली के लिये योजना खर्च 261.85 करोड़ रुपये रखे गये हैं जो बजट का 20.9% बनता है, सामाजिक व सामुदायिक विकास की मद में 456.38 करोड़ रुपये रखे गए हैं जो 36.5% बनता है, इरीगेशन एण्ड फ्लड कन्ट्रोल के लिये 248.36 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है जो 19.9% बनती है। एग्रीकल्चर सम्बन्धी कार्य के लिये 79.64 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है जो कुल बजट का 7.2% बनती है, ट्रांसपोर्ट के लिये 66.54 करोड़ दर्शाया गया है। इसी तरह से इण्डस्ट्रीज पर 56.29 करोड़ रुपये दिखाया गया है। इसमें डेफिसिट दिखा दिया 14.50 करोड़ रुपये जो साल के एण्ड तक बढ़ कर 69 करोड़ रुपये हो जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, वही किसी पिटी बातें इस बजट में भी दोहरा दी गई हैं कि हमें 10वें फाइनैन्स कमीशन की सिफारिश के आधार पर करों में ज्यादा हिस्सा मिल जाएगा या कुछ ग्रान्टस मिल जाएंगी, नान प्लान एक्सपैंडिचर को कम किया जायेगा या जो घाटा है, उसको बचत करके पूरा कर लिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, हर साल वही किसी पिटी बातें हैं और हर साल यही बातें कह दी जाती हैं। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों करते हैं। हर साल बजट के बाद नये टैक्स लगा कर हरियाणा की जनता के साथ अन्याय किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय इस डैफिसिट को पूरा करने के लिये मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि अपने 36 मन्त्रियों की जो फौज खड़ी कर रखी है, उसको कम कीजिए। बोर्डज और कारपोरेशन्ज के चेयरमैन्ज को कोई पावर नहीं है, आई0 ए0 एस0 जो एम0डी0 हैं, उनको सारी पावर्ज दे रखी हैं। जो कि काम को ठीक प्रकार से चला सकते हैं। बोर्ड व निगमों के चेयरमैन नहीं बनाये जाने चाहिएं। डैफिसिट को पूरा करने के लिए वही घिसी पिटी बातें करने का कोई फायदा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, अब तो यह एक रिवाज सा हो गया है कि चाहे यूनियन बजट हो या स्टेट गवर्नमैंट का बजट हो, कहने को तो बजट कर मुक्त होता है लेकिन हर सरकार बजट पास होने के बाद नये कर लगा देती है, कभी किसी चीज पर तो कभी किसी चीज पर और इस मामले में इन्होंने एक्सैप्शनल बात नहीं की। इनमें कर लगाने की हिम्मत होनी चाहिए और इस बजट में कर लगाते। इन्होंने तो एक तरीका इस्तेमाल कर रखा है कि या तो बजट से पहले या बजट के बाद कर लगा देते हैं। इसके अलावा, मैं यह कहना चाहता हूं कि विभिन्न विभागों की योजनाओं पर जो खर्चा दिखाया है और जो प्रस्ताव वित्त मन्त्री जी

[श्री ओम प्रकाश बेरी]

ने किया है, मैं उस बारे में स्पष्ट रूप से सरकार के ऊपर इल्जाम लगाना चाहता हूं कि पहले के वर्षों में भी और आने वाले वर्षों में भी मुझे आशंका है कि यह पैसा उन्हीं इलाकों में खर्च किया जा रहा है जो मुख्यमन्त्री जी के और इस सरकार के चहेते इलाके हैं। इस प्रकार से पैसा खर्च करने से इस प्रदेश के अन्दर क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया है, रिजनल इम्बैलेन्स पैदा हो गया है। इसका उदाहरण मैं विभिन्न विभागों की चर्चा करते हुए दूंगा। सबसे पहले मैं सिंचाई विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। मुख्यमन्त्री जी की सरकार जून 1991 में आई थी। उस वक्त ये कहने लगे थे कि उस आदमी का नाम या मुख्यमन्त्री का नाम भजन लाल होगा जो एस0 वाई0 एल0 प्रोजैक्ट पूरा करवाएगा। इन्होंने एलान किया था कि जो एस0 वाई0 एल0 का काम अधूरा पड़ा हुआ है, वह यह सरकार एक साल के अन्दर अन्दर पूरा करवा देगी। (विघ्न) उसके बाद 6 महीने की बात कही गई। मैंने बार बार कहा कि मुख्यमन्त्री जी आप कम से कम यह बता दें कि वह साल कौन सी तारीख को शुरु और कौन सी तारीख को खत्म होगा। अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि जो प्रस्ताव मांगे राम गुप्ता जी ने रखा है, उसमें सरकार ने एस0 वाई0 एल0 के बारे में इतना ही कहा है कि हम केन्द्रीय सरकार और पंजाब सरकार से एस0 वाई0 एल0 नहर के पंजाब क्षेत्र में आने वाले भाग को शीघ्र पूरा करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। इनकी इच्छा शक्ति समाप्त हो गई है और इन्होंने जो खोखले दावे किए थे, वे कतई तौर पर निर्मूल हो गए हैं और कतई तौर पर इनकी इसको बनाने की इच्छा शक्ति नहीं है। ये क्यों नहीं बनाना चाहते ? हमारे जो इलाके हैं जैसे रोहतक, सोनीपत, रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, भिवानी, गुड़गांव और फरीदाबाद जिले हैं, इनके साथ राजनैतिक आधार पर नहरी पानी के बंटवारे के बारे में काफी अर्से से भेद भाव किया जा रहा है। हमारे पानी का हिस्सा 1977 से चौधरी भजन लाल के जिले में जा रहा है। सिरसा जिले में नरवाना सब डिवीजन में जा रहा है। हमारे खेत प्यासे पड़े हुए हैं और हमारे गले सूखे पड़े हैं। आज ये ऐसे हालात हमारे साथ कर रहे हैं। मैंने 12 मार्च 1993 को विधान सभा में एस्टीमेट कमेटी की 25वीं रिपोर्ट पेश की थी।

चौधरी जगदीश नेहरा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर डिप्टी स्पीकर सर, यह हाउस को गुमराह कर रहे हैं और यह जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, वह रिपोर्ट यह है कि लिफ्ट इरीगेशन करके वहां पर पानी ले जाया जाए। एक नहर और बनाई जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाउस को यह क्लीयर करना चाहता हूं कि नरवाना लिंक चैनल से जितना हम पानी जमुना में भाखड़ा से ले जा सकते हैं उतना हम ले जा रहे हैं और इसके अलावा अभी पिछले दिनों नरवाना लिंक चैनल की कैपेसिटी 2400 क्यूसिक रह गई थी। हमने उसको रिपेयर करके उसकी कैपेसिटी 3400 क्यूसिक की है और इस पर एक करोड़

रुपया खर्च किया है। इससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी ही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय जितना पानी वहां सरकार ले जा सकती है और यह सरकार ही नहीं बल्कि जितनी भी सरकारें रही हैं, यह सिस्टम ऐसा ही है। यह तो ओम प्रकाश बेरी का सस्ती लोकप्रियता लेने का तरीका है कि दक्षिणी हरियाणा के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। दक्षिणी हरियाणा में जो भी 84—85—86 में नहरें निकली हैं, वह कांग्रेस ने ही निकाली हैं और जितना भाखड़ा का पानी नरवाना चैनल में ले जाया जा सकता है, उतना ही जा रहा है। ये इस तरह के ऐलीगेशन लगाकर सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश बेरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि ये जरा ध्यान से बात सुनते रहें और जिस ढंग से मैंने सुझाव दिए हैं, उनका बाद में जवाब दे दें। इस तरह से बीच बीच में इंट्रप्ट न करें। उपाध्यक्ष महोदय, 12 मार्च, 1993 को जो मैंने ऐस्टीमट कमेटी की 25वीं रिपोर्ट पेश की, आज तक सरकार ने उसको क्रियान्वित करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया जब कि साफ तौर पर इस रिपोर्ट में दर्शाया था की इन इलाकों को 18 लाख एकड़ फुट पानी सिरसा, हिसार तथा नरवाना को दिया जा रहा है और यह पानी राजनीतिक आधार पर उन इलाकों को दिया जा रहा है जिनके 1977 से लेकर आज तक मुख्यमन्त्री रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा में भी पंजाब में भी और केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार है इसलिये एस0 वाई0 एल0 का बकाया 15 फीसदी काम आराम से हो सकता है लेकिन सरकार जानबूझकर एस0 वाई0 एल0 के प्रोजैक्ट को नहीं बनवा रही है क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर पानी की चोरी जारी नहीं रखी जा सकेगी। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय ये डीसिल्टिंग की बात करते हैं, नरवाना ब्रांच की कैपेसिटी की बात करते हैं। सर, मैं इसको नरवाना ब्रांच के बारे में बताना चाहता हूं कि इस ब्रांच की सैक्शनड कैपेसिटी 42 सौ क्यूसिक की है लेकिन इस ब्रांच में इतनी सिल्ट जमा हो चुकी है कि आज इसकी कैपेसिटी घटकर ज्यादा से ज्यादा 2600 क्यसिक ही रह चुकी है। मैं इस बारे में आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार नरवाना ब्रांच की छंटाई करवाए और 50 किलो मीटर की लम्बाई तक इसके किनारों को तीन तीन फुट ऊंचा करवा दें। उपाध्यक्ष महोदय, यह काम कुछ ही करोड़ रुपये खर्च करके दो या तीन महीने में किया जा सकता है। अगर सरकार ऐसा करती है तो आराम से हमारे इलाकों में भी पानी पहुंच जाएगा और हमारे इलाकों से पूरा इंसाफ भी हो जाएगा। जिस तरह से आज ये एक महीने में 24 दिन पानी ले रहे हैं तो ऐसा करने से दो हफ्ते पानी ये ले सकेंगे और दो हफ्तों के लिये पानी हमारे इलाकों में जा सकेगा। लेकिन सरकार हमारे इलाकों के साथ भेदभाव कर रही है जो सरकार को नहीं करना चाहिए। इन्होंने सिर्फ डीसिल्टिंग के लिये 15 लाख रुपये भाखड़ा मेन लाईन कैनाल के लिये रखे हैं। आज भाखड़ा मेन लाइन कैनाल की क्षमता 11500

[श्री ओम प्रकाश बेरी]

क्यूसिक से घटकर करीब 6 हजार क्यूसिक ही रह गयी है। आज हालात इस तरह खराब हो गए हैं कि इसमें जो रावी व्यास का पानी लेकर आ रहे हैं, वह किस तरह से आएगा। यह पानी सरकार हरियाणा में लाना ही नहीं चाहती। इसके अलावा ये यमुना के ऐग्रीमेन्ट के बारे में बात करते हैं।

चौधरी जगदीश नेहरा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, जो यह कह रहे हैं तो उसी का खुद कंट्राडिक्शन भी कर रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि सिरसा और हिसार जिलों में पानी ज्यादा जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ ये यह भी कह रहे हैं कि भाखड़ा मेन लाईन की कैपेसिटी घटकर 6 हजार क्यूसिक ही रह गयी है। तो यह किस तरह से ऐलीगेशन लगा रहे हैं कि हिसार और सिरसा जिलों में पानी ज्यादा जा रहा है। इनकी दोनों बातों में स्वयं ही कंट्राडिक्शन है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हिसार, सिरसा, कैथल और करनाल में पानी ज्यादा जा रहा है जबकि दूसरी तरफ खुद ही कह रहे हैं कि उसकी कैपेसिटी कम हो गयी। ये दोनों ऐलीगेशन किस आधार पर लगा रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश बेरी : उपाध्यक्ष महोदय, ये समझने की कोशिश करें लेकिन इनकी समझ में तो कुछ आता नहीं है। मैं कंट्राडिक्शन नहीं कर रहा हूं बल्कि ये खुद ही कंट्राडिक्शन कर रहे हैं। मैं तो हरियाणा के इंट्रेस्ट में कह रहा हूं कि आप भाखड़ा मेन लाइन की सफाई करवाएं। जब तक एस0 वाई0 एल0 नहीं बन जाती तब तक भाखड़ा का पूरा पानी लाने के लिये इसकी सफाई करवानी जरूरी है। आपने 1.8 एम0ए0 एफ0 पानी के बारे में बताया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को नरवाना ब्रांच की सफाई करवाकर इसके किनारों को तीन तीन फुट ऊंचा करवाकर हमारे इलाकों में पानी भेजना चाहिए। यह तो सरकार की जिम्मेदारी है। इसी तरह से ये डीसिल्टिंग के बारे में कह रहे हैं कि हम छंटाई करवा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज भी जे. एस. बी. के बारे में सवाल आया था तो मन्त्री जी ने इस बारे में हाउस को गुमराह किया, मन्त्री जी को ज्ञान ही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, या तो मन्त्री जी को इस बारे में ज्ञान नहीं है या फिर इनके ओफिसर इनको गुमराह कर रहे हैं, गलत बातें बता रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय मैंने उस वक्त भी कहा था और अब भी कहता हूं कि बांकरा हैड के बाद पिछले कई महीनों से जे0 एस0 बी0 में कतई तौर पर पानी नहीं डाला जा रहा है और बहुत से गांव पीने के पानी से और नहरी पानी से वंचित किए जा रहे हैं जबकि उनसे आबियाना वसूला जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जे0 एस0 बी0 नहर में बहुत बड़े बड़े कीकर के दरख्त खड़े हुए हैं और 6—7 फुट ऊंची सिल्ट उसमें जमा हो चुकी है। सरकार का यह दायित्व है कि वह इस

नहर की छंटाई करवाए, सफाई करवाए । उपाध्यक्ष महोदय, यह इलाका भी इसी प्रदेश का इलाका है, इसीलिये सरकार को इस इलाके के साथ भी इंसाफ करना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, जब तक उन इलाकों के लिये पानी नहीं भेजा जाता जे0 एस0 बी0 की सफाई नहीं हो जाती तब तक उन इलाकों के गांव वालों से आबियाना नहीं लिया जाना चाहिए तथा जे0 एल0 एन0 कैनाल से आलटरनेटिव अरेजमैन्ट करके सिंचाई और पीने का पानी मुहैया करवाया जाना चाहिए । सर, यह तो सरकार का दायित्व बनता है सरकार डीसिल्टिंग के बारे में कागजों में आंकड़े तो दे देती है कि हमने इतनी डीसिल्टिंग करवायी लेकिन मौके पर जा कर देखो तो कतई तौर पर भी सफाई नहीं होती है । मैं मार्च 1993 के महीने में पूरे हरियाणा में गया था । मैंने भिवानी जिले में, रिवाड़ी जिले में और महेन्द्रगढ़ जिले में नहरों की और पम्प हाउसिज की जो हालत देखी उसको देखकर मुझे रोना आता है कि हरियाणा की सरकार उन लोगों के साथ क्यों ऐसा विहेव कर रही है क्यों ज्यादती कर रही है ? 1986-87 में जब चौधरी बंसी लाल जी प्रदेश के मुख्यमन्त्री बने थे तब इन्होंने हुक्म दिया था कि पावर हाउसिज को एनरजाइज कर दीजिए । 28 एनरजाइज कर दिए गए थे, बाकी 30-35 पावर हाऊस की तरफ आज तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया । पम्प हाउसिज में 7-7 फुट गाद जमा है, उन इलाकों में पीने के पानी की समस्या है, सरकार खोखले दावे करती है कि हर गांव में पीने का पानी उपलब्ध कराया है । (बंटी) उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मुझे बोलते हुए 10 मिनट ही हुए हैं । मुझे तो अभी बहुत बोलना है । उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सीपेज की प्रौबलम है, हमारे इलाके के अन्दर जवाहर लाल नेहरु नहर और जे0 एस0 बी0 पैरेलल चलती है, वहां पर 15-20 साल से पानी के रिसाव की गंभीर समस्या है । लेकिन सरकार ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया । 1992 में सरकार ने मेरे हल्के के लिए एक स्कीम पेश की थी । यह स्कीम 73 लाख रुपये की थी लेकिन ऐसी स्कीम मंजूर करने से क्या फायदा जिसके लिए फंड प्रोवाइड नहीं किया जाता । मंत्री जी का हल्का रोड़ी है, उस इलाके की सीपेज की समस्या को हल करने के लिए मुख्यमन्त्री जी ने शुभारम्भ कर दिया क्योंकि वह मन्त्री जी का हल्का था । पिछड़े इलाकों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है, जानबूझकर उन इलाकों के साथ ज्यादती की जा रही है । सीपेज की प्राब्लम की वजह से 50 हजार किले भूमि 15 साल में बरबाद हो चुकी है, उन किसानों को राहत दी जानी चाहिए । सीपेज की प्रॉब्लम परमानैन्टली हल की जानी चाहिए । यमुना जल के बारे में भी चौधरी भजन लाल जी ने हाउस में आश्वासन दिया था कि यमुना के बारे में जब कोई ऐग्रीमैंट होगा, उस एग्रीमैंट पर दस्तखत करने से पहले पूरे सदन को विश्वास में लिया जाएगा लेकिन हमें तो विश्वास में लेना दरकिनार अपने मन्त्रिमण्डल को भी विश्वास में नहीं लिया और यमुना जल समझौते पर दस्तखत कर दिए । जिससे मोटे तौर पर हरियाणा का 20 फीसदी पानी कम हो गया । दिल्ली, यू0पी0, हिमाचल और राजस्थान

[श्री ओम प्रकाश बेरी]

को पानी दे दिया गया है। मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली को पीने का पानी चाहिए। पीने का पानी मिलना चाहिए लेकिन यह अकेले हरियाणा की जिम्मेदारी नहीं है, पंजाब से भी लेना चाहिए, यू0पी0 और राजस्थान से भी लिया जाना चाहिए। अकेला हरियाणा क्यों दे ? 1954 के समझौते के मुताबिक खरीफ की फसल में हरियाणा का 77 परसैंट, यू0पी0 का 23 परसैंट, रबी के वक्त हरियाणा का 73 परसैंट और यू0पी0 का 27 परसैंट। अगर पानी ज्यादा पड़ जाए और 10900 क्यूसिक पानी आ जाए तो हरियाणा का 67 परसैंट और यू0पी0 का 33 परसैंट होता था। इस नये समझौते के आने की वजह से वह घटकर 47.8 परसैंट हो गया है, जो मैंने एम0ओ0यू0 पढ़ा है उसके मुताबिक। गड़बड़ तो यह है कि सरकार उस एग्रीमैंट को हाउस में पेश नहीं करना चाहती। क्या हालात हैं जिससे इस समझौते को छिपाया जा रहा है। इस तरह से कोई काम चलने वाला नहीं है। कंपट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल की 31 मार्च, 1992 की जो रिपोर्ट है, इसमें लिखा है कि वैस्ट यमुना सिस्टम में ज्यादा पानी चले, इसकी क्षमता बढ़े। पानी जो समुद्र में पहुंच जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक स्कीम बनाई गई थी, उस स्कीम पर न तो इस बजट में कोई प्रावधान किया गया है और है न ही पहले किया गया था। वह क्या स्कीम थी, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं :—

> "The scheme envisaged bringing water from Tajewala to Munak Head (Karnal District) through existing WJC system by adding one additional bay at Tajewala for raising its capacity by 1600 cusecs and remodelling of the Main Line Upper and Main Line Lower canals for increasing carrying capacity by 1600 cusecs and 1350 cusecs respectively. No work had, however, been carried out for increasing the carrying capacity. From Munak Head, water was to be carried through Delhi Parallel Branch from which supply was delivered to JLN Feeder off taking at RD 145250. Delhi Parallel Branch was remodelled to a designed capacity of 5156 cusecs upto RD 145250 during 1969-70 to 1986-87 at the cost of Rs. 687 lakhs. The total required capacity at RD 145250 of Delhi Parallel Branch was 7076 cusecs for feeding off taking channels (Delhi Parallel Branch down stream RD 145250 : 1783 cusecs, Bhalaut Sub Branch : 2052 cusecs and JLN Feeder : 3241 cusecs) against the designed capacity of 5156 cusecs. The quantity of water actually released in Delhi Parallel Branch during July to September each year from 1982 to 1992 ranged between 301 and 4302 cusecs while the actual quantity of water released in JLN Feeder after meeting downstream requirement of Delhi Parallel Branch and Bhalaut Sub Branch ranged between 60 cusecs and 1200 cusecs. Thus, the failure to increase the carrying capacity of existing WJC system and insufficient capacity of Delhi Parallel Branch resulted in short delivery of water in JLN system."

इस स्कीम की तरफ सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है, इन हल्कों के साथ सरकार ने पूरा भेदभाव बरता है । फिर सरकार कहती है कि हमने कोई भेदभाव नहीं किया है । कम से कम इस बजट में तो इसके लिये कोई प्रावधान किया जा सकता था ।

डिप्टी स्पीकर साहब, दादूपुर नलवी की एक स्कीम जोकि 1984 से मन्जूरशुदा है । आज 1984 से 1995 आ गया है, इस स्कीम से कुरुक्षेत्र अम्बाला और यमुनानगर जिलों को फायदा होना चाहिए था लेकिन सरकार ने न ही इस बजट में इस के लिए प्रावधान किया है और न ही पिछले बजट में प्रावधान किया था । उस इलाके के लोग पानी को तरस रहे हैं । यमुना इन इलाकों के पास से गुजरती है लेकिन दादूपुर-नलवी स्कीम पर अमल न होने के कारण उन इलाकों के लोगों को पीने के पानी से व सिंचाई से जानबूझकर वंचित किया जा रहा है । अभी सरकार ने यमुना के बारे में अपर रिवर यमुना बोर्ड बनाना मन्जूर कर लिया है, बना भी दिया है । रावी-व्यास व भाखड़ा के मैनेजमैंट का जो बोर्ड बना था, उसमें जो स्टेट्स-बैनीफिशरीज होती थीं, वे सारी की सारी उसकी मैम्बर थीं और सैन्टर का एक नुमाइंदा उसका अध्यक्ष होता था । प्रैक्टीकल रूप से आज पंजाब सरकार का बी0एम0बी0 पर पूरा कंट्रोल है लेकिन आगरा कैनाल की क्या स्थिति है ? वह हरियाणा से गुजरती है लेकिन उस पर पूरा कंट्रोल यू0पी0 सरकार का है । इसका कंट्रोल लेने के लिए आज तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है । इस बारे में, मैं यह कहूंगा कि सरकार पानी के मामले में कोई खास चिंतित नहीं है क्योंकि जिस इलाके के मुख्यमन्त्री बनते रहे हैं, उन इलाकों में पानी बाकायदा पहुंच रहा है और वह भी शेष इलाकों को पानी देने के लिये तैयार नहीं है, यह कितनी गल्त परम्परा है ?

डिप्टी स्पीकर साहब, इसके अलावा मैं स्प्रिंकलर सैट्स के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा । यह स्कीम 1974 के बाद इंट्रोड्यूस की गयी थी । जब चौधरी बंसीलाल जी इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री हुआ करते थे तो इन्होंने ऐग्रीकलचर इम्पलीमैंट्स पर दरांती से लेकर कम्बाईंड हारवैस्टर तक के ऊपर से सेल्ज टैक्स बिल्कुल माफ कर रखा था । एक तो इस सरकार ने हमारा पानी छीन लिया, दूसरे अगर किसी तरह से हम स्प्रिंकलर सैट्स लगाकर थोड़ा बहुत खेती से पैदावार बढ़ाने का काम करते हैं तो स्प्रिंकलर सैट्स पर इस सरकार ने 8.8 परसैन्ट सेल्ज टैक्स लगा रखा है । इससे किसानों को काफी दिक्कत हो रही है । इस बारे में, मैंने कई बार अनुरोध भी किया है कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश व राजस्थान की सरकारों ने स्प्रिंकलर सैट्स को कर-मुक्त कर रखा है, उसी प्रकार इस सरकार को भी स्प्रिंकलर सेटस को कर-मुक्त कर देना चाहिए और किसानों की मदद करनी चाहिये । किसान विरोधी काम नहीं करना चाहिए । 8.8 परसैन्ट जो सेल्ज टैक्स स्प्रिंकलर सैट्स पर है, उसको कर-मुक्त कर देना चाहिए ताकि गरीब आदमी की, गरीब किसानों की मदद की जा सके ।

[श्री ओम प्रकाश बेरी]

इसके साथ-साथ मैं बिजली के बारे में भी थोड़ा सा कहना चाहूंगा । (घंटी) डिप्टी स्पीकर, इस तरह से आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं, मैंने तो अभी बहुत बोलना है । (शोर)

श्री बंसीलाल : डिप्टी सरकार साहब, 1 बजकर 6 मिनट पर इन्होंने बोलना शुरु किया था । बी0ए0सी0 की मीटिंग में यह तय हुआ था कि दोनों तरफ से दो-दो मेन स्पीकर्ज आधा-आधा घण्टा बोलेंगे । और बाकी बोलने वाले 5-6 मिनट में अपने हल्के की बात कह लेंगे । कल शाम में और आज में कोई फर्क पड़ गया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता लेकिन तय यही हुआ था । 1.36 बजे तक तो आप इनको कुछ कहो मत, बोलने दें । जो इंटरफीरैन्स होती है, उसकी वजह से टाइम बढ़ाना होगा ।

श्री ओमप्रकाश बेरी : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इररैलेवैन्ट कभी नहीं बोलता जब मैं बोल लूंगा तो मैं खुद ही कह दूंगा । तो मैं बिजली के बारे में कह रहा था । पानीपत और फरीदाबाद थर्मल प्लांट्स की जो पावर जनरेट करने की कैपेसिटी जो आज है, वह 32 और 35 परसैन्ट है, इससे ज्यादा बिजली वहां पैदा नहीं की जा सकती । मेरा एक सुझाव है कि अगर इन थर्मल प्लांट्स को सुचारू रूप से चलाने की क्षमता नहीं है तो इनको एन0टी0पी0सी0 के सुपुर्द कर दिया जाए ताकि यह क्षमता बढ़कर 70-75 परसैंट हो जाए और प्रदेश को ज्यादा बिजली मिल सके ।

इसके अलावा जो लाईन लासिज हैं, वे नैचुरल-वे में केवल 15 परसैंट ही होने चाहिए लेकिन आज 40 से 45 परसैंट बल्कि 50 परसैंट तक लाईन लासिज हैं और बिजली की चोरी बड़े योजनाबद्ध तरीके से हो रही है । बिजली की चोरी को रोकने के लिए सरकार कोई प्रबन्ध करे ताकि लोगों की सारी समस्याएं दूर हो सकें । इसके इलावा, मैं बताना चाहता हूं कि बिजली के बारे में, वर्ष 1995-96 में योजना के खर्चे पर 261 करोड़ 85 लाख रुपये दिखाये हैं । मैं वित्तमन्त्री महोदय को बतलाना चाहता हूं कि वे पिछले 10-15 सालों के पूरे बजट उठा कर देख लें, हर साल कभी डेढ़ सौ करोड़ रुपया, कभी 200 करोड़ रुपया योजना के खर्चे पर बिजली के बारे में खर्च करने की बात कही है । लेकिन कितना खर्चा योजनाओं पर किया गया इन 15 सालों के बीच में, ये वह स्वयं देख लें । क्या यह बात सही नहीं है कि योजनाओं के खर्चे को डाइवर्ट करके नान-प्लान एक्सपैन्डीचर में डाल दिया जाता है और किसी किस्म का कोई खर्च योजनाओं पर नहीं किया जाता ?

श्री उपाध्यक्ष : बेरी साहब, आपका टाइम हो गया है ।

श्री ओम प्रकाश बेरी : सर, यह तो बहुत लम्बा मामला है । मैं तो सरकार को अच्छे सुझाव दे रहा हूं ।

चौधरी बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, कल बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में यह बात हुई थी कि आध-आध घंटा दो मेन स्पीकरों को मिलेगा । मुख्य मन्त्री जी ने इस बात को ऐग्री किया था तो आप इनको आध घंटा तो बोलने दें ।

बैठक का समय बढ़ाना

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, ये 24 मिनट बोल चुके हैं इसलिए आप 6 मिनट के लिए बैठक का समय और बढ़ा दें ।

श्री उपाध्यक्ष : यदि हाउस सहमत हो तो बैठक का समय 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए ।

आवाजें : ठीक है जी ।

श्री उपाध्यक्ष : बैठक का समय 5 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है ।

वर्ष 1995-96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री ओम प्रकाश बेरी : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था कि जो योजना के लिए प्रावधान है, आप 15 साल का पुराना बजट उठा कर देख लें, उस पर कोई पैसा खर्च नहीं किया गया बल्कि उसको नान प्लान में डाल देते हैं । इसी वजह से आज बिजली बोर्ड का घाटा साढ़े सोलह सौ करोड़ रुपया हो गया है । दिल्ली की सरकार ने 1976 में यमुना नगर के लिए एक सुपर थर्मल प्लांट लगाने की मन्जूरी दी थी और उसके लिए 600 एकड़ जमीन भी एक्वायर की गई थी लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया । आज इन्होंने इजराइल की कम्पनी आइजनबर्ग से समझौता किया है । ये कहते हैं कि हम कंज्यूमर को 1.92 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देंगे । पता नहीं थर्मल प्लांट लगने के बाद उसका कितना खर्चा बढ़ जाएगा ? मेरे हिसाब से कंज्यूमर को कम से कम साढ़े तीन रुपए या चार रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलेगी । इसके लिए मैमोरैंडम आफ अंडर स्टैंडिंग है जिसको सदन में रखना चाहिए था ताकि मैम्बर्ज को पता चल जाता कि वह किस आधार व शर्तों पर हुआ है ।

इसी प्रकार से मैं अपने इलाके के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं । यह जो एक्सप्लेनेटरी मैमोरैंडम आन दि बजट पेश किया गया है, इसकी किताब के पेज 105 पर लिखा है कि जिन किसानों को ट्यूबवैल की बिजली के लिए राहत दी गई है, यानी जिन इलाकों को ट्यूबवैल के मामले में बिजली के रेट्स की राहत दी गई

[श्री ओम प्रकाश बेरी]

है, इसमें वह इलाका दर्शाया गया है जिसको 44 रुपए प्रति बेसिक हार्स पावर की दर से ट्यूबवैल को बिजली देने का प्रावधान किया गया है । उसमें इलाके हैं तहसील दादरी, भिवानी, लोहारु तहसील और नाहड़ । सब तहसील नाहड़, सब-तहसील के कुछ इलाके रिवाड़ी जिले में चले गए और कुछ मातनहेल सब-तहसील जो झज्जर में पड़ती है, उसमें चले गए । तो मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जो गांव पुरानी नाहड़ तहसील के थे, उन सब को यह सस्ती बिजली की सुविधा दो । एक जिले से दूसरे जिले में जाने के बाद उनके वाटर टेबल में कोई चेंज नहीं आई है ।

बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : डिप्टी स्पीकर साहब, यह बात हमारे सामने आई थी । बोर्ड उसको एग्जामिन कर रहा है । अगर ऐसी बात है तो हम जरूर उनको रिलीफ देंगे ।

श्री ओम प्रकाश बेरी : उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में ट्रांसफारमर प्रियारिटी के हिसाब से बदला जाता है लेकिन मैं अपने हल्के की बात कहता हूं कि वहां पर 15 दिन से लेकर एक महीने तक इसको बदला जाता है । कम से कम इस किस्म की बात तो इनको नहीं करनी चाहिए । बिजली के मामले में इन्होंने एक सैल्फ फाइनैंसिंग स्कीम चलाई है । इसमें गरीब किसान 25-30 हजार रुपए कहां से देगा ? मैं चाहता हूं कि इसको खत्म किया जाए और जो आपने 11 हजार ट्यूबैल्ज को कनैक्शन देने का टारगैट बनाया है, उनमें अधिकतर कनैक्शन रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, भिवानी और झज्जर तहसील के लोगों को प्रयारिटी के हिसाब से दिए जाने चाहिएं । इसी तरह से मैं रोड्ज के बारे में कहना चाहता हूं । इनकी कागजों में तो बेशक रिपेयर हो गई होगी लेकिन प्रैक्टीकली नहीं हुई है। मैं आपको सड़कों के नाम बताता हूं । एक तो झज्जर से कोसली है, झज्जर से गुडियानी , साम्पला, झज्जर, बेरी दुबलधन तथा बेरी से सांपला । इन सड़कों की हालत इतनी खराब है कि आप आंख बन्द करके गाड़ी में बैठ जाएं । जब इनमें से किसी भी सड़क पर गाड़ी पहुंचेगी तो आपको पता लग जाएगा कि वह सड़क आ गई है । रोडज के बारे में हमारे इंजीनियर्ज काफी सक्षम हैं । हमारे इंजीनियर्ज से एक्सप्रैस हाई-वे बनवाने की बजाए, मलेशिया की एक फर्म को बनाने का ठेका दिया है । वह फर्म उसको बनाएगी । क्या मलेशिया के इंजीनियर्ज ज्यादा अच्छे हैं ? क्या हमारे देश के इंजीनियर्ज पर सरकार को भरोसा नहीं है, इसलिए इस सरकार ने उसको बनाने के लिए मलेशिया की फर्म के साथ समझौता किया है ? हमारे इंजीनियर्ज के साथ यह बड़ी भारी ज्यादती है । डिप्टी स्पीकर साहब, ट्रांसपोर्ट के बारे में मैं थोड़ा-सा कहना चाहूंगा । जो 50 किलोमीटर तक की लम्बाई के रूट परमिट प्राइवेट लोगों को दिए गए थे, उनके बारे में हमारा बड़ा भारी बिटर एक्सपीरियंस हो गया है । जिन लोगों को जिन रूट्स के परमिट दिए गए थे, वे उन रूट्स पर बसें चलाने की बजाय हरियाणा रोडवेज के जनरल मैनेजर से मिल करके पुलिस वालों से मिल

करके और सचिव आर0टी0ए0 से मिल करके जो वायबल रूट्स हैं, उन पर अपनी बसें चला रहे हैं । इसके अलावा, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पब्लिक के साथ बड़ी भारी ज्यादती हो गई है क्योंकि जिन रूट्स के परमिट प्राइवेट आपरेटर्ज को दिए गए थे, उन रूट्स से हरियाणा रोडवेज की बसें विदड्रा कर ली गई हैं । मैं तो यह कहूंगा कि यह दोहरी मार पड़ गई ।

श्री उपाध्यक्ष : बेरी साहब अब आप अपनी स्पीच समाप्त करें । आपको बोलते हुए आधा घंटा हो गया है ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री ओम प्रकाश बेरी : डिप्टी स्पीकर साहब, आप कम से कम हाउस का 15 मिनट टाईम बढ़ा दें । मुझे बातें तो कहनी ही हैं ।

चौधरी बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, बी0ए0सी0 की मीटिंग में यह बात आई थी कि अगर जरूरत पड़े तो हाउस का टाईम आधा घंटा बढ़ाया जा सकता है । इसलिए आप इनको बोलने के लिए 15 मिनट का टाईम और दे दें ।

चौधरी भजन लाल : इसीलिए हमने सैशन दो दिन के लिए और बढ़ा दिया है । इस समय हाउस का टाईम घंटा आधा घंटा बढ़ाने के क्या मायने हैं ? (शोर)

चौधरी बंसी लाल : माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि इनको 15 मिनट और बोलना है । आपने इनके 5–7 मिनट तो शोर करके ही खराब कर दिए । Let him remain on his legs कल ये 15 मिनट और बोल लेंगे । कल ये जो 15 मिनट बोलेंगे वह मेरे टाईम में से आप काट लेना ।

चौधरी भजन लाल : नहीं, यह सवाल ही पैदा नहीं होता । वह आधा घंटा बोल चुके हैं ।

चौधरी बंसी लाल : बी0ए0सी0 की मीटिंग में सारी बात हुई है । I am not speaking beyond the scope of the discussion, which took place in the Business Advisory Committee meeting.

श्री उपाध्यक्ष : यदि हाउस सहमत हो तो बैठक का समय 3 मिनट और बढ़ा दिया जाए ।

आवाजें : ठीक है जी, 3 मिनट से ज्यादा न बढ़ाया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : बैठक का समय 3 मिनट और बढ़ाया जाता है । Please wind up within two minutes.

वर्ष 1995-96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री प्रकाश बेरी : डिप्टी स्पीकर साहब, दो मिनट में तो मेरी बातें पूरी नहीं होंगी । मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में कह रहा था कि लोगों को सहूलियतें देने के लिए प्राइवेट आप्रेटर्ज और हरियाणा रोडवेज की बसों के बीच में कम्पीटीशन चलाना चाहिए ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके । हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं और जिन रूट्स पर प्राइवेट लोगों को परमिट दिए गए हैं, उन रूट्स पर चल रही हैं, उनको विदड्रा नहीं करना चाहिए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिलती रहे । मैं सरकार से एक बात कहना चाहूंगा और बेशक सरकार इस बारे में इंक्वायरी कर ले कि जिन लोगों को जिस रूट के परमिट मिले हैं, वे लोग उन रूट्स पर अपनी बसें न चला करके, दूसरे रूट्स पर चला रहे हैं । मैं आपको मिसाल के तौर पर बताऊंगा कि शेरिया से बहादुरगढ़ का परमिट मिला हुआ है और बिरधाना से बहादुरगढ़ का परमिट मिला हुआ है लेकिन वे बस चलाते हैं बेरी से बहादुरगढ़ । मैं एक बात और ट्रांसपोर्ट के बारे में कहना चाहूंगा । हमारे यहां रोहतक में हरियाणा रोडवेज के जनरल मैनेजर पिछले 6 साल से बैठे हैं । वह जनरल मैनेजर किस तरह से लोगों के साथ जुल्म ढा रहे हैं, उसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा । वहां के एम्पलाइज ने आपस में मिल कर उस जनरल मैनेजर के खिलाफ सरकार को एक ज्ञापन भी दिया था कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए । कोई भी हरियाणा रोडवेज का जनरल मैनेजर कहीं पर भी 6 साल से नहीं बैठा होगा लेकिन रोहतक में बैठा है ।

Mr. Deputy Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 a.m., tomorrow.

*13.38 | (The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Wednesday, the 15th March, 1995.)

26725—H.VS.—H.G.P. Chd.